भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 12 भाद्रपद, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 123, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

21 साल की मॉडल की घर में घुसकर की हत्या

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 21 साल की मॉडल की उसके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आरोप जिम ट्रेनर इमरान पर लगा है। वह पिछले कुछ समय से युवती को जानता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, युवती मुस्कान के परिजन बाहर गए हुए थे और वह घर में अकेली थी तभी आरोपी वहां पहुंचा और उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। इसमें आरोपी भागते हुए नजर आ रहा है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी घर तक कैसे पहुंचा और वारदात के बाद किस रास्ते से फरार हुआ।

ऑटो ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए मिला एक साल

एजेंसी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी न जानने वाले ऑटो व टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए एक

साल का समय दिया। वीरवार को मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस बीच में ड्राइवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस कदम से मराठी भाषा की शर्त को लागू करने का काम एक साल के लिए टल गया है। ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर संगठनों ने फडणवीस से मुलाकात कर नियम का पालन करने के लिए और समय मांगा था। फडणवीस ने यह भी कहा कि मुंबई में काम करने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी की कामचलाऊ जानकारी जरूरी होने का संगठनों ने समर्थन किया है। उन्होंने तर्क दिया कि ड्राइवर अलग-अलग उम्र के हैं और कई लोग लंबे समय से पढ़ाई से दूर हैं इसलिए उन्हें मराठी सीखने में समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार इस समय का इस्तेमाल सिर्फ रियायती अवधि के तौर पर नहीं, बल्कि क्लास और स्टडी मटीरियल के जरिए ड्राइवरों को सीखने में मदद करने के लिए करेगी।

टीएमसी का ममता गुट बैंक-अकाउंट इस्तेमाल न करे: कलकत्ता हाईकोर्ट

एजेंसी, कलकत्ता। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट को पार्टी के चार बैंक खाते चलाने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इन खातों में करीब 804 करोड़ जमा हैं और पुलिस ने इनसे निकासी पर रोक लगा रखी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने वीरवार को इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसी राहत देने से उसके पहले के आदेश का असर खत्म हो जाएगा। उस आदेश में राजनीतिक दल के रोजमर्रा के खर्च पूरे करने की अनुमति दी गई थी। मामले की अगली सुनवाई दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद होगी। कोर्ट ने इससे पहले दोनों पक्षों को अपना-अपना पक्ष बताते हुए हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि चार खातों को चलाने की आगे अनुमति देने का आदेश उनके पहले के आदेश को 'गलत' साबित कर देगा।

ओलंपिक में भारत की बढ़ानी होगी भागीदारी : पीएम मोदी

खेलो इंडिया डायलॉग में कहा- युवाओं को स्क्रीन से ज्यादा प्लेग्राउंड चाहिए

एजेंसी, नई दिल्ली। पीएम मोदी ने वीरवार को 1,500 से ज्यादा जगहों पर युवाओं और खिलाड़ियों से

वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक के 20 से ज्यादा खेलों में भारत की भागीदारी नहीं रही। ओलंपिक में भारत की भागीदारी बढ़ानी होगी। 2036 ओलंपिक के लिए अभी से खिलाड़ी तैयार करें।

मोदी ने कहा- 15 अगस्त को देश के सामने स्पोर्ट्स विजन रखा। यह सिर्फ मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित भारत और देश की खेल शक्ति बढ़ाने का अभियान है। पीएम ने कहा- मैं हमेशा कहता हूं- जो खेले, वो खिले। आज युवाओं को स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर और प्लेग्राउंड चाहिए। पीएम ने कहा स्वस्थ समाज और मजबूत परिवार के लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जरूरी है। खेल हमें चैंपियन के साथ बेहतर प्रतियोगी बनना सिखाते हैं।

पैरा एथलीट्स की सफलता समाज और परिवारों में नई उम्मीद जगाती है। उन्होंने कहा कि शीतल और अवनी लेखरा की उपलब्धि पर- शीतल के आर्चरी मेडल और अवनी लेखरा के दो मेडल ने जम्मू-कश्मीर और देश को गौरवान्वित किया। झंडू कुमार समेत कई पैरा एथलीट प्रेरणा दे रहे हैं। फौजा सिंह ने 100 साल की उम्र के बाद भी फिटनेस की मिसाल पेश की।

कार्यक्रम खेल मंत्रालय के 'खेलो इंडिया संवाद-खेल की बात, पीएम के साथ' अभियान के तहत आयोजित किया गया। इसका मकसद युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जोड़ना है। कार्यक्रम में भारतीय ओलिंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा के अलावा मौजूदा और पूर्व खिलाड़ी समेत अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता भी शामिल हुए।

स्टेडियम ही नहीं लोगों की सोच भी बदली : मांडविया

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पीएम मोदी ने युवाओं को देश का उज्ज्वल भविष्य बताया है। 12 जनवरी को युवाओं के साथ समय बिताने का असर बजट में भी दिखा, जिसे वित्त मंत्री ने यूथ ड्रिवन बताया। उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ा बदलाव स्टेडियम में नहीं, बल्कि लोगों की सोच में आया है। एक तरफ वे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने तिरंगे को विश्व मंच तक पहुंचाया है। दूसरी तरफ वे खिलाड़ी हैं, जो तिरंगे को पोडियम तक पहुंचाने का सपना देख रहे हैं।

कानपुर में विमान क्रैश पायलट व ट्रेनी की मौत

एजेंसी, कानपुर। यूपी के कानपुर में ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। हादसे में पायलट और ट्रेनी की मौत हो गई। विमान ने वीरवार सुबह 11:30 बजे उड़ान भरी थी। 11:50 बजे यानी उड़ान के महज 20 मिनट बाद गंगा बैराज के पास खेत में क्रैश हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विमान करीब 200-250 फुट ऊपर था, तभी अचानक हवा में डगमगाया। फिर नीचे गिरा। नीचे गिरते ही पूरा विमान टूटकर बिखर गया। पुर्जे दूर तक बिखर गए। हालांकि, विमान में आग नहीं लगी। हादसे से जुड़े वीडियो सामने आए हैं। इनमें दिख रहा है कि जमीन में गिरने के बाद विमान मलबे में तब्दील हो गया। एक पायलट कॉकपिट के पास फंसा हुआ है। दूसरा गंभीर हालत में विमान से थोड़ी दूर खून से लथपथ पड़ा है। विमान की एक सीट भी टूटकर बाहर आ गई। करीब 12:15 बजे पुलिस-प्रशासन की टीम पहुंची। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

नेपाल बाढ़ में 359 शव बरामद 288 भारतीय समेत 1500 लापता

एजेंसी, काठमांडू। नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ के बाद अब तक 359 शव बरामद किए जा चुके हैं। वीरवार शाम 5 बजे तक चितवन जिले में सबसे ज्यादा 132 शव मिले हैं। करीब 1,500 लोगों की तलाश जारी है। इनमें 288 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। वहीं, 21 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया है, जिनमें से 11 की पहचान हो चुकी है।

इसी बीच प्रशासन ने भोटेकोशी नदी में फिर बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी किया है। चीन से मिली सैटेलाइट तस्वीरों में बाढ़ वाली जगह पर नदी का पानी रुकने से एक झील बनने की जानकारी मिली है। झील में पानी बढ़ रहा है और इसके टूटने का खतरा भी बना हुआ है। भोटेकोशी नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों, यात्रियों और राहत-बचाव में जुटे लोगों को नदी किनारे और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है।

नेपाल की मदद के लिए भारत बैली ब्रिज भेजेगा

नेपाल में बाढ़ से टूटे रास्तों और पुलों को फिर से जोड़ने के लिए भारत बैली ब्रिज भेजेगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यह एक पोर्टेबल और पहले से तैयार किया जा सकने वाला पुल है, जिसे जरूरत वाली जगह पर जल्दी लगाया जा सकता है। बाढ़ या भूस्खलन में जब कोई पुल टूट जाता है, तो बैली ब्रिज कम समय में रोड कनेक्टिवटी को बहाल करने में मदद करता है। इसे जरूरत के मुताबिक दूसरी जगह भी ले जाकर लगाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री धामी का युवा विद्यार्थियों से संवाद, जिज्ञासाओं का किया समाधान

एजेंसी, उधमसिंहनगर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीरवार को रुद्रपुर के एक निजी विद्यालय में मेरे सपनों का उत्तराखंड पर आयोजित 'मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन' कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान युवा विद्यार्थियों से संवाद कर उनके विचारों, सुझावों और भविष्य के उत्तराखंड को लेकर उनकी परिकल्पनाओं को जाना। मुख्यमंत्री ने उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा विद्यार्थियों की ऊर्जा, सोच और विकसित उत्तराखंड के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उत्साहवर्धक है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश की भावी पीढ़ी, सशक्त, आत्मनिर्भर और जागरूक बने, यही हमारी प्राथमिकता है। युवाओं के विचार और सुझाव उत्तराखंड के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा के साथ-साथ युवाओं को रोजगार, कौशल विकास, नवाचार और उद्यमिता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत-विकसित उत्तराखंड' के संकल्प को साकार करने के लिए शिक्षा, रोजगार, नवाचार, कौशल विकास, पर्यटन, कृषि, खेल और तकनीक सहित प्रत्येक क्षेत्र को सशक्त बनाया जा रहा है। युवा शक्ति उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है और उनके सपनों, विचारों एवं प्रतिभा को अवसर देकर हम एक आत्मनिर्भर, सक्षम और विकसित उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा केवल आज का नहीं बल्कि कल के भविष्य भी हैं।

ब्लिंकिट-स्विगी, डीमार्ट से 5 किलो से ज्यादा शक्कर नहीं मिलेगी

एजेंसी, नई दिल्ली। ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे क्विक-कॉमर्स एप्स से अब ग्राहक एक बार में 2 से 5 किलो तक ही चीनी खरीद पाएंगे। देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले चीनी की सप्लाई घटने और कीमतों में अचानक आई तेजी के बाद यह फैसला लिया गया है। उपभोक्ता मामले विभाग के मुताबिक, 26 अगस्त को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 65.05 रुपए किलो पर पहुंच गई है। महज एक महीने पहले 26 जुलाई को यह 48 रुपए प्रति किलो थी। यानी 30 दिनों में चीनी 35.5% से महंगी हुई है। ऑफलाइन बाजार में डीमार्ट और रिलायंस रिटेल जैसे सुपरमार्केट्स ने प्रति ग्राहक 2 से 3 किलो चीनी खरीदने की सीमा तय की है।

स्लाटर हाउस-मीट दुकानों पर 'डबल लाइसेंस' का झंझट खत्म, हरियाणा सरकार करेगी संशोधन बिल पास

एजेंसी, चंडीगढ़। नायब सरकार मीट की दुकानों और स्लाटर हाउस संचालकों के दोहरे लाइसेंस की व्यवस्था के झंझट को खत्म करने जा रही है।

नए प्रावधान लागू होने के बाद

मीट कारोबार के लिए नगर निगम या नगरपालिका से अलग ट्रेड लाइसेंस लेने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग पहले से ही इन गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ऐसे में दोहरे लाइसेंस की व्यवस्था अनावश्यक है। बृहस्पतिवार को विधानसभा में हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2026 और हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 पेश किए गए। संशोधित बिल के अनुसार, केंद्र सरकार के मंत्रिमंडलीय सचिवालय के विनियमन प्रकोष्ठ की ओर से दोहरे लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त करने के निर्देशों के बाद इस व्यवस्था की समीक्षा की गई और दोहरे लाइसेंस की व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधित विधेयकों में हरियाणा नगर निगम व नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 329 की उपधारा (1) को हटाने का प्रविधान किया गया है। मौजूदा धारा 329 (1) के तहत बिना नगर निगम आयुक्त व नगरपालिका आयुक्त के लाइसेंस के मछली विक्रेता, पोल्ट्री कारोबार अथवा मानव उपभोग के लिए मांस आयात करने का कारोबार करना या मांस, मछली अथवा पोल्ट्री बेचने की जगह संचालित करना प्रतिबंधित है। इन बिलों में संशोधन का सबसे बड़ा असर यह होगा कि मीट की दुकान या संबंधित कारोबार के लिए नगर निगम व नगर पालिकाओं से अलग ट्रेड लाइसेंस लेने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि मांस कारोबार पर सभी नियंत्रण खत्म हो जाएंगे।

विधानसभा में न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पेश

हरियाणा सरकार ने विधानसभा में हरियाणा न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य पंजाब न्यायालय अधिनियम 1918 में मौजूद पुराने और अप्रचलित कानूनी प्रविधानों को मौजूदा कानून के अनुरूप करना है।

सीएम रेखा ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए बच्चों संग मनाया रक्षाबंधन का पर्व

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर वीरवार को मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से आए बच्चों के साथ आत्मीयता और उल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया।

इस अवसर पर बच्चों ने मुख्यमंत्री को अपने हाथों से राखियां बांधीं, मिठाई खिलाई, कविताएं और गीत सुनाए। मुख्यमंत्री ने उनके साथ खुलकर संवाद किया और उनके स्कूल, पढ़ाई और परिवार से जुड़ी बातें पूछीं। बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ मुख्यमंत्री से बातचीत की और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने बच्चों को उपहार देकर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान कई बच्चों ने उनके लिए विशेष रूप से कविताएं और गीत तैयार किए थे, जिन्हें उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि राखी केवल एक धागा नहीं, बल्कि एक-दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक है। बच्चों के साथ सहज संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि वे अपने भाई-बहन के साथ झगड़ते हैं या नहीं। बच्चों के जवाब पर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए उन्हें रक्षाबंधन के दिन एक-दूसरे से झगड़ा न करने और हमेशा प्यार से रहने का वादा भी कराया। इस दौरान पूरा माहौल हंसी, अपनापन और बच्चों की मासूमियत से भर गया।

पंजाब के हड़ताली मुलाजिमों पर होगी कार्रवाई

आप सरकार ने गैरहाजिर रहने वालों की लिस्ट मांगी; सीएम ने नहीं की मीटिंग

एजेंसी, चंडीगढ़। पंजाब में महा हड़ताल करने वाले मुलाजिमों पर आम आदमी पार्टी कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। सरकार ने बिना परमिशन के ड्यूटी से गैरहाजिर मुलाजिमों की लिस्ट तलब कर ली है।

इसके लिए सेक्रेटरी लेवल के अफसरों को कहा गया है। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सरकार का तर्क है कि इनके काम न करने की वजह से लोगों को परेशानी हुई। इससे पहले सीएम भगवंत मान ने भी मुलाजिमों को लेकर कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने मुलाजिमों से जालंधर में एक बजे की मीटिंग तय की थी। उससे पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि हड़ताल खत्म करो, तभी बातचीत होगी। दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। इसके बाद मुलाजिम मीटिंग करने गए, तो सीएम ने उन्हें टाइम नहीं दिया। वहीं, 7 लाख से ज्यादा मुलाजिमों-पेंशनर्स की महा हड़ताल की वजह से वीरवार को सरकारी कामकाज ठप रहा। सरकारी दफ्तर, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में ओपीडी सेवाएं बंद रहीं। पठानकोट में यूनियन के जिलाध्यक्ष विशालवीर ने कहा कि धरना खत्म कर दिया, लेकिन सांझा मोर्चा के अगले आदेश तक हड़ताल जारी रहेगी।

जालंधर में मुलाजिमों व पुलिस में धक्कामुक्की

जालंधर में मुलाजिमों और पुलिस में धक्कामुक्की हुई। मुलाजिम यहां रोड जाम करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धक्के देकर हटाने की कोशिश की, जिसमें कुछ मुलाजिम सड़क पर बैठ गए। इधर, मोहाली सिविल अस्पताल में दवाई लेने पहुंचे एक व्यक्ति ने बताया कि गार्ड ने उसे यह कहकर बाहर कर दिया कि आज हड़ताल है, अब कल आना। वहीं, पठानकोट में नगर निगम दफ्तर, सिविल अस्पताल में ताले लटके मिले। अफसरों की कार चलाने वाले ड्राइवर भी हड़ताल में शामिल हैं। इसके चलते अधिकारियों को दफ्तर पहुंचने में परेशानी हुई। लुधियाना के डीसी भी सुबह साढ़े 9 बजे तक अपने कार्यालय नहीं पहुंचे थे। जालंधर में शाहकोट से 86 साल की रिटायर्ड टीचर रणधीर कौर धरना देने पहुंची है।

आंध्र प्रदेश में बस व ऑटो-रिक्शा की टक्कर, 7 की मौत

एजेंसी, पलनाडु। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में वीरवार को एक बस ने ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हुए। घायलों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। हादसा चिलकलूरिपेट मंडल के अड्डा रोड के पास हुआ। बस विजयवाड़ा से तिरुपति जा रही थी, तभी उसने 15 यात्रियों को लेकर जा रहे ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी।

पुलिस के मुताबिक, ऑटो-रिक्शा सड़क के गलत तरफ मुड़कर बस के रास्ते में आ गया था। उस समय बस करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। नरसारावपेट के डीएसपी एम. हनुमंत राव के मुताबिक, हादसा रात करीब 1 बजे हुआ। तिरुपति जा रही बस एक यात्री को लेने के लिए चिलकलूरिपेट के पास बाईपास पहुंची थी। यात्री को लेने के बाद बस नरसारावपेट बस स्टैंड की ओर जा रही थी। इसी दौरान कला मंदिर जंक्शन के पास बस की ऑटो-रिक्शा से टक्कर हो गई। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में घायल छह लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हिमाचल में साढ़े तीन साल में 7 .59 करोड़ पर्यटक पहुंचे, 2 .64 लाख विदेशी सैलानी भी आए : सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान 7 करोड़ 59 लाख 5 हजार 479 पर्यटकों का आगमन हुआ है। इनमें 2 लाख 64 हजार 824 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने विधानसभा में पर्यटकों की संख्या और विदेशों से आने वाले सैलानियों का देशवार ब्योरा भी दिया है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान गगरेट के विधायक राकेश कालिया के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। विधायक ने पूछा था कि पिछले तीन वर्षों में 1 अगस्त 2026 तक प्रदेश में कितने पर्यटक आए और इनमें किस-किस देश के पर्यटक शामिल हैं। उन्होंने देशवार पर्यटकों की संख्या का ब्योरा भी मांगा था। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार वर्ष 2023 में हिमाचल में 1 करोड़ 60 लाख 49 हजार 24 पर्यटक पहुंचे। वर्ष 2024 में पर्यटकों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 81 लाख 24 हजार 694 हो गई। वर्ष 2025 में प्रदेश में 3 करोड़ 11 लाख 47 हजार 155 पर्यटकों का आगमन हुआ। वर्ष 2026 में 1 अगस्त तक 1 करोड़ 6 लाख 28 हजार 706 पर्यटक हिमाचल पहुंचे। इन आंकड़ों को मिलाकर पिछले तीन वर्षों और वर्ष 2026 में 1 अगस्त तक प्रदेश में कुल 7 करोड़ 59 लाख 5 हजार 479 पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया है। सरकार ने इसी अवधि में हिमाचल आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बताई है। कुल 2 लाख 64 हजार 824 विदेशी पर्यटक प्रदेश पहुंचे। इनमें सबसे अधिक पर्यटक यूनाइटेड किंगडम से 49 हजार 29 आये। संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाले पर्यटकों की संख्या 26 हजार 207 रही। इसके अलावा फ्रांस से 8 हजार 417, इटली से 5 हजार 1 और कनाडा से 7 हजार 323 पर्यटक हिमाचल पहुंचे। संयुक्त अरब अमीरात से 677, पाकिस्तान से 7 और अमेरिका से 26 हजार 207 पर्यटकों का आगमन हुआ। इसी अवधि में जर्मनी से 9 हजार 283, मलेशिया से 5 हजार 713, ऑस्ट्रेलिया से 15 हजार 226 और स्विट्जरलैंड से 3 हजार 398 पर्यटक हिमाचल आए।

यूके से सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक पहुंचे हिमाचल

संबोधन | उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति पुस्तिका का किया विमोचन, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का भी किया शुभारंभ

यूपी की आबादी चुनौती नहीं, बड़ी संभावना : मुख्यमंत्री योगी

एजेंसी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली, ऊर्जावान युवा वर्कफोर्स यूपी में है। इन्हें प्लेटफॉर्म उलब्ध कराना सरकार का काम है। राजदूत, उच्चायुक्त समेत विदेशी प्रतिनिधिमंडल मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ से अधिक है, इसलिए आपके सामने बड़ी चुनौती है। मैं उनसे कहता हूं कि जितनी बड़ी चुनौती, उतनी ही बड़ी संभावना है। यूपी की जिस आबादी को लोग चुनौती कहते हैं, हम उसे डेमोग्रॉफिक डेविडेंड मानते हैं। इनके स्केल को स्किलिंग से जोड़कर इसका उपयोग डेमोग्रॉफिक डेविडेंड के रूप में कर पाते हैं।

मुख्यमंत्री वीरवार को लोकभवन में स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 107 स्टार्टअप्स को 3.42 करोड़ रुपए से अधिक और नौ इनक्यूबेटर्स को 1.79 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करने के उपरांत युवा उद्यमियों व उद्योग प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 पुस्तिका का विमोचन तथा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इस दौरान लघु फिल्म के माध्यम से यूपी के स्टार्टअप इकोसिस्टम से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री योगी ने 2014 से पहले और इसके बाद भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम की चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत में व्यापक बदलाव दिख रहा है। 2014 के पहले देश में मात्र 500 स्टार्टअप्स थे, अब इनकी संख्या ढाई लाख से ऊपर है। स्टार्टअप इकोसिस्टम अब भारत के युवाओं के सपनों की उड़ान को गति दे रहा है। 2017 से पहले यही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी थी। उस समय यहां कुल 120 स्टार्टअप थे, लेकिन डबल इंजन सरकार के प्रोत्साहन व सकारात्मक वातावरण के कारण आज इनकी संख्या 24 हजार से अधिक हो गई। इसमें आठ यूनिकॉर्न हैं। यूपी की स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत आज इस मौके पर 107 स्टार्टअप व नौ इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। यूपी स्टार्टअप नीति के तहत 12 नए इन्क्यूबेटर्स को भी मान्यता प्रदान कर रहे हैं। योगी ने कहा शिक्षा, रोजगार, स्टैंडअप, स्टार्टअप, इन्क्यूबेटर्स आदि के बारे में इकोसिस्टम तब तैयार होता है, जब धारणा के साथ ही आमजन की मानसिकता भी उसके अनुरूप दिखाई दे।

2017 से रोजगार, इन्क्यूबेटर्स, शिक्षा इनोवेशन की चर्चा एक सपना

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'भारत इनोवेट्स' के कई स्टार्टअप्स का मैंने दौरा किया था। अपने कार्यों की बदौलत उन्होंने यूपी की पहचान और धारणा को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर जाने पर सांसद के रूप में मैंने भी महसूस किया कि लोग शक की निगाहों से देखते थे। धारणा यह थी कि जहां सड़कों में गड्ढे और बिजली के अभाव में अंधेरा दिखने लगे, समझो यूपी आ गया। उत्सव से पहले उपद्रव होता था। स्कूल-कॉलेज, बाजार महीनों बंद रहते थे। आमजन कर्फ्यू के साये में जीने को विवश था। उस समय पांच वर्ष में 700 से अधिक दंगे हुए। उन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार, इन्क्यूबेटर्स, शिक्षा, इनोवेशन की चर्चा करना एक सपना ही था।

युवाओं में लोकतंत्र के प्रति बढ़ा आकर्षण पठानियां ने समझाई संसदीय प्रणाली

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंचे विभिन्न शिक्षण संस्थानों के करीब 220 छात्र-छात्राओं से विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने संवाद किया। कौंसिल चैंबर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौपाल, सरस्वती पैराडाइज स्कूल संजौली, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लालपानी तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग के विद्यार्थियों ने विधानसभा अध्यक्ष से लोकतांत्रिक व्यवस्था और सदन की कार्यप्रणाली से जुड़े विषयों पर चर्चा की।

कुलदीप सिंह पठानियां ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश की आबादी करीब 140 करोड़ है और भारत में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए देश को युवाओं का देश भी कहा जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि लोकसभा और विधानसभा लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर हैं। देश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधि इन सदनों का गठन करते हैं और जनता की समस्याओं तथा आवश्यकताओं को सदन में उठाते हैं।

उन्होंने कहा कि कानून बनाने का अधिकार केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पास होता है। लोकसभा और विधानसभाएं संविधान और निर्धारित प्रक्रिया के तहत कानून बनाने का कार्य करती हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था संघीय ढांचे पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर शासन व्यवस्था संचालित होती है।

संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने विधानसभा अध्यक्ष से कई सवाल पूछे। पठानियां ने विद्यार्थियों के प्रश्नों का सिलसिलेवार जवाब देते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका और सदन की कार्यवाही के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि युवाओं और विद्यार्थियों में विधानसभा की कार्यवाही देखने को लेकर बढ़ती रुचि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। प्रतिदिन करीब 200 विद्यार्थी सदन की कार्यवाही देखने पहुंच रहे हैं।

डुढालटी स्वास्थ्य शिविर में 250 मरीजों की जांच विक्रमादित्य बोले- आधुनिक सुविधाएं दे रही सरकार

मुफ्त स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने ग्रामीणों की जांच कर मुफ्त दवाइयां कीं वितरित

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य संस्थानों की सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने यह बात शिमला ग्रामीण के डुढालटी में आयोजित नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के दौरान कही।

पंचायत घर डुढालटी में लायंस क्लब शिमला और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला के संयुक्त तत्वाधान में नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। विक्रमादित्य सिंह ने शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला डॉ. यशपाल रांटा और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लोकेंद्र शर्मा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

चिकित्सा उपकरणों पर खर्च होंगे तीन हजार करोड़ : विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। अस्पतालों में आधुनिक मशीनरी और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए करीब तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश के लोगों को अपने ही राज्य में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

उन्होंने बताया कि हाल ही में चमियाना अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी शुरू की गई है। यह सुविधा मरीजों को लगभग 30 से 50 हजार रुपये में उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि निजी अस्पतालों में इसी प्रकार की सर्जरी के लिए पांच लाख रुपये से अधिक खर्च करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

रिक्त पद भरने की प्रक्रिया जारी : कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मचारियों और तकनीशियनों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इससे अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 10 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा योजना भी प्रदेश सरकार जल्द लागू करने जा रही है।

उन्होंने कहा कि टूटू विकास खंड का बनूटी क्षेत्र तेजी से मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर हैं और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डुढालटी में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में करीब 250 लोगों ने नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच करवाई। मरीजों को आवश्यक दवाइयां भी मुफ्त वितरित की गईं।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को पावन पर्व रक्षा बंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। दोनों ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि यह पर्व भाई-बहन के पवित्र रिश्ते, प्रेम, विश्वास और आपसी स्नेह का प्रतीक है।

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने अपने संदेश में कहा कि रक्षा बंधन भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह त्योहार समाज में आपसी भाईचारे और सद्भाव को बढ़ावा देने के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस पर्व को आपसी प्रेम और मिलजुलकर मनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि रक्षा बंधन भाई-बहन के बीच प्यार, स्नेह और परस्पर विश्वास को मजबूत करने वाला पर्व है। यह त्योहार समाज में एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देता है तथा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मूल्यों को संजोने का अवसर प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई-बहन के अटूट रिश्ते के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने रक्षा बंधन के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उन्होंने कहा कि त्योहार हमारी सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कामना की कि रक्षा बंधन का पावन पर्व प्रदेश के प्रत्येक परिवार में खुशियां, प्रेम, शांति और समृद्धि लेकर आए। साथ ही उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से इस पर्व को आपसी भाईचारे और सौहार्द की भावना के साथ मनाने का आग्रह किया।

पीएम श्री चौपाल स्कूल के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौपाल के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। विद्यार्थियों ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति से उनकी पढ़ाई को बेहतर दिशा मिलेगी और शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने में सहायता मिलेगी। विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को अपनी शैक्षणिक आवश्यकताओं और विद्यालय से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की उपलब्धता से विषयवार पढ़ाई मजबूत होगी तथा विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी में भी बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

आईजीएमसी शिमला में मरीज सुविधाओं को मिला नया विस्तार

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों और प्रदेश सरकार की मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं की प्रतिबद्धता के अनुरूप इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (आईजीएमसी) शिमला में स्वास्थ्य सेवाओं तथा आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन की ओर से मरीजों और उनके तीमारदारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सुधार किए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में अस्पताल के बी-ब्लॉक को विशेष रूप से उन्नत एवं सुदृढ़ किया गया है। यहां वार्डों के आधारभूत ढांचे, वातावरण और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार किया गया है। अस्पताल प्रशासन का प्रयास है कि उपचार के दौरान मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ स्वच्छ, सुरक्षित,

बी-ब्लॉक का हुआ कायाकल्प

आरामदायक और गरिमापूर्ण वातावरण भी उपलब्ध हो।

बाल रोगियों के लिए बनाया आकर्षक माहौल : बी-ब्लॉक के बाल रोग वार्ड में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। बच्चों के लिए वार्ड के वातावरण को अधिक आकर्षक, सकारात्मक और बाल-मित्र बनाने के उद्देश्य से दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी और रंगीन सजावट की गई है। इससे अस्पताल के वातावरण को बच्चों के अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि उपचार के दौरान सकारात्मक माहौल बच्चों के मन से अस्पताल को लेकर होने वाले भय को कम करने में सहायक हो सकता है।

वार्डों में स्वच्छता, रखरखाव और मरीजों की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि मरीजों को उपचार के साथ आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी बेहतर तरीके से उपलब्ध हों।

मरीजों के अनुभव में सुधार पर जोर : चिकित्सा अधीक्षक, आईजीएमसी शिमला ने कहा कि प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में संस्थान का उद्देश्य केवल अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि मरीजों के समग्र अनुभव और संतुष्टि में सुधार करना भी है। बी-ब्लॉक का उन्नयन इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

विधानसभा सत्र के छठे दिन पठानियां ने संभाली सदन की कमान

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 14वें विधानसभा के 12वें सत्र के छठे दिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया। सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में निर्धारित कार्यों को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया और सदस्यों को संसदीय नियमों एवं परंपराओं के अनुरूप अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया।

सदन की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई तथा सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों और प्रदेश से जुड़े मुद्दे उठाए। अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने सदस्यों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और सदन की गरिमा बनाए रखते हुए कार्यवाही संचालित की।

फोरलेन भूमि अधिग्रहण पर केंद्र की शर्त से हिमाचल नाराज

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला-मटौर फोरलेन परियोजना को लेकर केंद्र सरकार की नई शर्त से राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। केंद्र ने नम्होल और घुमारवीं के समीप करीब 16 किलोमीटर के दो हिस्सों के लिए भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी हिमाचल सरकार को उठाने को कहा है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि भूमि अधिग्रहण का खर्च भी राज्य सरकार को ही वहन करना है तो बेहतर होगा कि फोरलेन का निर्माण कर राज्य सरकार ही टोल वसूली करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब फोरलेन का निर्माण और टोल वसूली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है तो भूमि अधिग्रहण की लागत भी उसी को वहन करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इस शर्त पर पुनर्विचार का आग्रह किया जाएगा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष भी मामला उठाया जाएगा।

वहीं, कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर वाहनों की गति सीमा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार सर्वे करवाएगी। वर्तमान में इस मार्ग पर गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर्वे के बाद इसे 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा किए जाने पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गति सीमा बढ़ाने से पहले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा।

मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने फोरलेन पर लगाए गए टोल बैरियर से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा भी उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू-मनाली क्षेत्र के स्थानीय लोगों को टोल शुल्क में राहत देने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।

हिमराल ने प्रदेशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष हरि कृष्ण हिमराल ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के पवित्र रिश्ते, प्रेम, विश्वास और आपसी स्नेह का प्रतीक है। यह पर्व परिवार के सदस्यों को एक-दूसरे के प्रति अपने दायित्व और जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। हरि कृष्ण हिमराल ने अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है, जो समाज में प्रेम, भाईचारे और सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस पर्व को आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ मनाने का आह्वान किया।

शोघी में विद्यार्थियों को कानून और अधिकारों के प्रति किया जागरूक

नशामुक्ति, बाल अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं पर विद्यार्थियों को दी अहम जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के सौजन्य से राज्य कार्य योजना के अंतर्गत ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल, शोघी में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सहायक विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता पूजा चंदेल ने विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों और उनके लिए उपलब्ध सहायता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वर्ष 2025 की नशा मुक्ति एवं विधिक सहायता योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य नशे से प्रभावित लोगों को उपचार, पुनर्वास और कानूनी सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।

उन्होंने बच्चों के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वर्ष 2024 की बाल-मित्र विधिक सेवा योजना के बारे में भी विद्यार्थियों को जागरूक किया। उन्होंने बच्चों के मौलिक अधिकारों, छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार, बाल मजदूरी पर रोक तथा किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी।

पूजा चंदेल ने विद्यार्थियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। इनमें सुकन्या समृद्धि योजना और मध्यान्ह भोजन योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं शामिल रहीं। उन्होंने किसी भी आपात स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए बाल सहायता दूरभाष संख्या 1098 तथा आपातकालीन सहायता संख्या 112 की जानकारी भी दी।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने कानूनी अधिकारों और सहायता से जुड़े विषयों पर जानकारी प्राप्त की तथा अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। वक्ता ने विद्यार्थियों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के साथ-साथ दूसरों को भी कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने का आह्वान किया।

विद्यालय की प्रधानाचार्या किरण शर्मा ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी जानकारी विद्यार्थियों को जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने में सहायता करती है।

विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने रक्षा बंधन पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने प्रदेश और देशवासियों को हिंदुओं के पवित्र एवं पारंपरिक पर्व रक्षा बंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि रक्षा बंधन केवल राखी का धागा नहीं, बल्कि भाई का बहन की रक्षा के लिए अटूट वादा है। हर भाई इस वचन को निभाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है और बहनें भी इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करती हैं।

पठानियां ने कहा कि भारत विविधताओं में एकता वाला देश है, जहां विभिन्न पर्व और त्योहार पूरे उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। रक्षा बंधन भी भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के पवित्र रिश्ते को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण पर्व है। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसे राखी तथा श्रावणी के नाम से भी जाना जाता है।

उन्होंने कहा कि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती है। यह परंपरा भारतीय संस्कृति की गहराई और परिवार में रिश्तों के महत्व को दर्शाती है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रक्षा बंधन हमें यह संदेश देता है कि रिश्ते केवल खून से नहीं, बल्कि भावनाओं और विश्वास से मजबूत होते हैं। एक-दूसरे की भावनाओं को समझकर और सम्मान देकर समाज में सच्चा भाईचारा स्थापित किया जा सकता है। आज के समय में जब रिश्तों में दूरी बढ़ रही है, ऐसे त्योहार पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हिमाचल में आवास सहायता बढ़ाकर 3 .63 लाख करने की मांग

महंगाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राशि बढ़ाने की उठी मांग

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने की मांग विधानसभा में उठी। विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने सदन में संकल्प प्रस्तुत करते हुए पात्र परिवारों को मिलने वाली आवास सहायता राशि बढ़ाकर 3 लाख 63 हजार रुपये करने की मांग की।

विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के लिए केवल मकान बनाने की योजना नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का आधार है। पहाड़ी प्रदेश में वर्तमान सहायता राशि से गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और टिकाऊ मकान बनाना कठिन हो गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए योजना के तहत केंद्र की ओर से वर्तमान में करीब 1.30 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है। प्रदेश सरकार की ओर से भी अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन निर्माण सामग्री और मजदूरी की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण यह राशि पर्याप्त नहीं रह गई है। उन्होंने सरकार से प्रदेश में लाभार्थियों को वास्तव में मिलने वाली सहायता राशि और लंबित भुगतानों की स्थिति स्पष्ट करने का भी आग्रह किया।

विधायक ने सदन को बताया कि वर्तमान में सीमेंट की कीमत करीब 380 से 450 रुपये प्रति बोरी, ईंटों की कीमत 7,000 से 9,000 रुपये प्रति हजार और सरिया तथा टीएमटी की कीमत लगभग 60 हजार रुपये प्रति टन तक पहुंच गई है।

दुर्गम क्षेत्रों में मकान बनाना महंगा

विक्रम ठाकुर कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए परिवहन पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। कई गांव सड़क से दूर होने के कारण सामग्री ढुलाई की लागत और बढ़ जाती है। ऐसे में गरीब परिवारों के लिए योजना की मौजूदा सहायता से मकान पूरा करना चुनौतीपूर्ण है। विक्रम ठाकुर ने केंद्र और प्रदेश सरकार से मिलकर सहायता राशि में आवश्यक बढ़ोतरी करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया, ताकि योजना के पात्र परिवारों को सुरक्षित और टिकाऊ आवास उपलब्ध हो सकें।

पांच लाख की चोरी में फरार आरोपी योगराज गिरफ्तार, पूछताछ जारी

भारतेन्दु संवाददाता, अनीश सूद, शिमला। शिमला पुलिस की ओर से वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान योगराज के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, वह वर्ष 2025 में हुई चोरी की वारदात के बाद से गिरफ्तारी से बच रहा था।

पुलिस के मुताबिक, 10 मई 2025 की रात नत्थू राम लच्छमनदास हलवाई की दुकान में चोरी हुई थी। आरोपी पर दुकान का गल्ला तोड़कर उसमें रखी करीब पांच लाख रुपये की नकदी चोरी करने का आरोप है। वारदात के बाद से योगराज फरार चल रहा था।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि योगराज को सुन्नी थाना में दर्ज अभियोग संख्या 68/2025 में 19 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला 25 नवंबर 2025 को दर्ज किया गया था और इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4) और 305(ए) के तहत कार्रवाई की गई थी।

इसके बाद सदर थाना पुलिस ने 26 अगस्त 2026 को पांच लाख रुपये की चोरी के मामले में योगराज को नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे चार दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर भेजा गया।

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान चोरी की वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों, संभावित सहयोगियों और चोरी की रकम की बरामदगी को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।

रक्षाबंधन राखी के धागे से मजबूत हुआ स्नेह, जयराम ठाकुर से महिला मोर्चा ने निभाया भाई-बहन का रिश्ता

विधानसभा में जयराम ठाकुर को महिला मोर्चा ने बांधी राखी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने विधानसभा पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को राखी बांधकर पर्व की खुशियां साझा कीं। भाजपा महिला जिला अध्यक्ष रीना शर्मा के नेतृत्व में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जयराम ठाकुर की कलाई पर राखी बांधी और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।

इस अवसर पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और आपसी रिश्ते की भावना को मजबूत करने वाले रक्षाबंधन पर्व को उत्साह के साथ मनाया। विधानसभा परिसर में हुए इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने जयराम ठाकुर को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दीं।

भाजपा महिला जिला अध्यक्ष रीना शर्मा के साथ प्रेम चौहान, संजू शर्मा, लता शर्मा, मीनाक्षी रंजन, पूनम, बिंदु सूद और सिया सविता भी मौजूद रहीं। सभी ने बारी-बारी से जयराम ठाकुर की कलाई पर राखी बांधी और उनके सुखद, स्वस्थ तथा लंबे जीवन की कामना की।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है, जो भाई-बहन के बीच प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के भाव को दर्शाता है। राखी का धागा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि रिश्तों की मजबूती और एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक भी है।

जयराम ठाकुर ने महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के पवित्र रिश्ते और आपसी स्नेह का पर्व है। यह त्योहार परिवार और समाज में प्रेम, विश्वास तथा भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संदेश देता है।

उन्होंने सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख, समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना की। कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला।

इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है। रक्षाबंधन जैसे पर्व सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के साथ लोगों को आपसी प्रेम और सद्भाव का संदेश देते हैं। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से राखी बांधकर इस भावना को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसे पर्व समाज में भाईचारे, आपसी सम्मान और सद्भाव की भावना को मजबूत करते हैं।

विधानसभा अध्यक्ष से उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की शिष्टाचार भेंट

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 12वें सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां से उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

शिष्टाचार भेंट के दौरान विधानसभा की कार्यवाही और सत्र से संबंधित विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को सत्र के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं दीं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने भी उपमुख्यमंत्री का स्वागत किया।

इस अवसर पर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों, जनहित से जुड़े मुद्दों तथा विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर होने वाली चर्चाओं को लेकर विचार साझा किए गए। दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से संचालित करने के महत्व पर भी चर्चा की।

सदन की कार्यवाही आरंभ होने से पहले हुई इस शिष्टाचार भेंट को विधानसभा सत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सदन की कार्यवाही का संचालन किया।

आदित्य बिड़ला कैपिटल ने देहरादून से शुरू किया गोल्ड लोन कारोबार

देहरादून से उत्तराखंड में गोल्ड लोन कारोबार की शुरुआत, आदित्य बिड़ला कैपिटल ने सुरक्षित ऋण पर दिया जोर

◆ **आने वाले समय में शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विस्तार के जरिए कंपनी अपनी पहुंच बढ़ाने की योजना पर काम करेगी**

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार ने उत्तराखंड में गोल्ड लोन क्षेत्र में प्रवेश किया है। कंपनी ने देहरादून में अपनी समर्पित शाखा शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही ग्राहकों को स्वर्ण आभूषणों के बदले संगठित, सुरक्षित और सुविधाजनक ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में कंपनी ने कदम बढ़ाया है। कंपनी के अनुसार यह पहल उसके व्यापक वित्तीय सेवा पोर्टफोलियो के विस्तार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोल्ड लोन कारोबार में प्रवेश के साथ कंपनी का लक्ष्य उत्तराखंड में अपनी वित्तीय सेवाओं की पहुंच को और मजबूत करना है।

कंपनी के मुताबिक उत्तराखंड में संगठित गोल्ड लोन कारोबार के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। राज्य में छोटे और मध्यम कारोबार का विस्तार हो रहा है तथा औपचारिक ऋण व्यवस्था को लेकर लोगों की स्वीकार्यता भी बढ़ रही है। इसके अलावा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में तेजी से विकसित हो रहे बाजारों के कारण सुरक्षित और सुविधाजनक ऋण सेवाओं की मांग में वृद्धि हो रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कंपनी ने देहरादून को अपने शुरुआती विस्तार के लिए महत्वपूर्ण बाजार माना है। देहरादून राज्य की राजधानी होने के साथ प्रमुख व्यावसायिक और प्रशासनिक केंद्र भी है।

आदित्य बिड़ला कैपिटल की गोल्ड लोन सेवा में शाखा आधारित सुविधा के साथ डिजिटल माध्यम से जुड़ने का विकल्प भी शामिल होगा। कंपनी का कहना है कि ग्राहकों को ऋण प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत पारदर्शी मूल्य निर्धारण, गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों की सुरक्षित देखरेख और सरल ऋण प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों को ऐसी सेवा उपलब्ध कराना है, जिसमें उन्हें ऋण लेने के दौरान स्पष्ट जानकारी और बेहतर सुविधा मिल सके।

कंपनी के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी-गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार राकेश सिंह ने कहा कि गोल्ड लोन कारोबार की शुरुआत आदित्य बिड़ला कैपिटल के व्यापक और ग्राहक केंद्रित वित्तीय सेवा तंत्र के निर्माण की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की राजधानी के रूप में देहरादून की स्थिति, यहां विकसित हो रहा कारोबारी तंत्र और संगठित वित्तीय सेवाओं की बढ़ती मांग इसे कंपनी के लिए महत्वपूर्ण बाजार बनाती है।

ऋण प्रक्रिया में पारदर्शिता

कंपनी शाखा और डिजिटल माध्यमों को जोड़कर ग्राहकों को एकीकृत सुविधा देने की दिशा में काम करेगी। इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार सेवा का माध्यम चुनने में आसानी होगी। गोल्ड लोन के क्षेत्र में आभूषणों की सुरक्षा और ऋण प्रक्रिया में पारदर्शिता को महत्वपूर्ण माना जाता है। कंपनी ने भी इन दोनों पहलुओं को अपनी सेवा का प्रमुख आधार बनाया है। ग्राहकों के स्वर्ण आभूषणों को सुरक्षित रखने के साथ ऋण से जुड़ी शर्तों और मूल्य निर्धारण को स्पष्ट रखने पर जोर दिया जाएगा।

उत्तराखंड में छोटे कारोबारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए समय पर वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण होती है। व्यक्तिगत और कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग विभिन्न ऋण विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में स्वर्ण आभूषणों के आधार पर मिलने वाला ऋण कई ग्राहकों के लिए उपयोगी वित्तीय विकल्प बन सकता है। कंपनी की नई पहल इसी बाजार में संगठित वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जुड़ी है। देहरादून में समर्पित शाखा शुरू होने के बाद कंपनी उत्तराखंड में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। कंपनी का कहना है कि स्थानीय ग्राहकों की बदलती वित्तीय जरूरतों को समझकर उनके अनुरूप सेवाएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता रहेगी। आने वाले समय में शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विस्तार के जरिए कंपनी अपनी पहुंच बढ़ाने की योजना पर काम करेगी।

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की ठोस नीति जरूरी : यूकेडी

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

◗ **नेपाल आपदा पर यूकेडी ने जताया दुख**

उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि नेपाल और उत्तराखंड भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए प्राकृतिक आपदाएं दोनों के लिए बड़ी चुनौती हैं। ऐसे कठिन समय में सीमाओं से ऊपर उठकर मानवीय सहयोग और आपसी समन्वय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कुकरेती ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नेपाल सरकार और स्थानीय प्रशासन को युद्धस्तर पर अभियान चलाकर प्रभावित लोगों तक भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, अस्थायी आवास और अन्य जरूरी सहायता तत्काल पहुंचानी चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से भी नेपाल की आवश्यकता के अनुसार हरसंभव मानवीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की अपील की।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आपदा प्रबंधन और हिमालयी क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर दीर्घकालिक समन्वय तंत्र मजबूत किया जाना जरूरी है। हिमालय केवल भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि दोनों देशों की साझा प्राकृतिक विरासत है। इसलिए हिमालयी राज्यों और पड़ोसी देशों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षित विकास और प्रभावी आपदा प्रबंधन की ठोस नीति बनाई जानी चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल ने आपदा प्रभावित नेपाल के नागरिकों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए हरसंभव मानवीय समर्थन की भावना दोहराई।

एमडी की फर्जी पहचान बनाकर कंपनी से 3.20 करोड़ ठगे, एसटीएफ ने आरोपी दबोचा

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

उत्तराखंड एसटीएफ ने 3.20 करोड़ रुपये की हाईप्रोफाइल साइबर ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी चंद्र कांत मिश्रा को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कंपनी के प्रबंध निदेशक की फर्जी पहचान बनाकर व्हाट्सऐप के माध्यम से कंपनी के महाप्रबंधक को झांसे में लेने और अलग-अलग बैंक खातों में करोड़ों रुपये स्थानांतरित कराने का आरोप है। एसटीएफ की साइबर अपराध पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण, डिजिटल निगरानी और मैनुअल इनपुट के आधार पर आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी। इसके बाद कोलकाता के महेशतल्ला स्थित ग्रीन फील्ड सिटी में दबिश देकर उसे उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कंपनी के उच्चाधिकारी और प्रबंध निदेशक बनकर महाप्रबंधक से संपर्क किया। उन्होंने परियोजना के अग्रिम भुगतान और जरूरी कारोबारी लेन-देन का हवाला देकर रकम विभिन्न बैंक खातों में भेजने के निर्देश दिए। इसी प्रक्रिया में करीब 3.20 करोड़ रुपये की ठगी की गई। इनमें श्याम ट्रेडिंग कंपनी का बैंक खाता भी शामिल था।

गिरफ्तारी के दौरान एसटीएफ ने आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन, चार सिम कार्ड और एक एचपी लैपटॉप बरामद किया। लैपटॉप की जांच में विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के संपादन योग्य दस्तावेज, बैंक ऋण आवेदन, आधार और पैन कार्ड की प्रतियां समेत कई संवेदनशील डिजिटल दस्तावेज मिले हैं। एजेंसी को आशंका है कि इनका इस्तेमाल अन्य साइबर अपराधों में भी किया गया होगा।

श्रमिक देश-प्रदेश के विकास की आधारशिला : अग्रवाल

कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम में अग्रवाल ने श्रमिकों को बांटी स्वास्थ्य-शिक्षा किट

◆ **जलशक्ति विभाग ने सरकार की अधिसूचना के तहत बिल जारी करने की दी सफाई**

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

आशीर्वाद वाटिका, हरिद्वार रोड, ऋषिकेश में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ऋषिकेश विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने सहभागिता की। इस दौरान बड़ी संख्या में पंजीकृत श्रमिकों को स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी आवश्यक सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में करीब 400 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया।

डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रमिकों को स्वास्थ्य पोषक आहार किट वितरित की। इसके साथ ही श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा किट और महिलाओं के लिए महिला स्वास्थ्य किट भी दी गई। उन्होंने सभी श्रमिकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्रमिक वर्ग देश और प्रदेश के विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है।

श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत : प्रेमचंद अग्रवाल

विधायक ने कहा कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार के साथ उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे कार्यक्रमों से श्रमिक परिवारों को सीधे तौर पर लाभ मिलता है और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिलती है। कार्यक्रम में ऋषिकेश नगर निगम के मेयर शंभू पासवान, श्यामपुर मंडल अध्यक्ष चंद्र मोहन पोखरियाल, ऋषिकेश मंडल अध्यक्ष मनोज ध्यानी, मंडल महामंत्री दीपक बिष्ट, राजेंद्र थलवाल, विजय पवार, राजेश दिवाकर और चंदू यादव सहित कई जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और श्रमिक मौजूद रहे।

चम्पावत को 62.97 करोड़ की 50 विकास योजनाओं की सौगात

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

◆ **धामी बोले- मातृशक्ति के सशक्त होने से मजबूत होगा उत्तराखंड**

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को चम्पावत के धूरा स्थित रामलीला मैदान में आयोजित 'मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव-2026' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चम्पावत को 62.97 करोड़ रुपये की 50 विकास योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर धामी ने कहा कि वह अपनी बहनों, माताओं, बेटियों और भांजियों के बीच अपने घर आए हैं। चम्पावत से मिलने वाला प्रेम और अपनापन उन्हें हमेशा ऊर्जा देता है। उन्होंने कुमाऊंनी भाषा में मातृशक्ति से संवाद किया और उनसे रक्षा सूत्र बंधवाकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने 11.08 करोड़ रुपये की 20 योजनाओं का लोकार्पण और 51.89 करोड़ रुपये की 30 योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं से जिले में सड़क, पेयजल, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा और धार्मिक पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर क्षेत्र के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों की घोषणाएं भी कीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प प्रदेश की प्रत्येक मातृशक्ति को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तराखंड की पहचान हिमालयी चोटियों और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ यहां की मेहनती, साहसी और आत्मनिर्भर मातृशक्ति से भी है। महिला सशक्तीकरण का अर्थ केवल सरकारी योजनाओं का लाभ देना नहीं, बल्कि महिलाओं को शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाकर परिवार और समाज के निर्णयों में भागीदार बनाना है।

अंकिता के न्याय को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन

न्याय की राखियां लेकर सीएम आवास पहुंचीं महिलाएं

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

गीत से सरकार को जगाने पहुंचीं महिलाएं।

रक्षाबंधन के पर्व पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं अंकिता भंडारी समेत प्रदेश की बेटियों और बहनों के न्याय की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचीं। महिलाओं ने अपने साथ न्याय की राखियां, रोली, मौली, धूप-दीप और मिठाई लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि महिलाओं के पहुंचने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया।

मुख्यमंत्री आवास के बाहर महिलाओं ने अंकिता भंडारी मामले में पूर्ण न्याय की मांग उठाई। उन्होंने सरकार की कथित उदासीनता और मामले की जांच की प्रगति को लेकर सवाल किए। इस दौरान महिलाओं ने गीत के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। गीत में अंकिता भंडारी, नन्ही परी और प्रदेश की उन बेटियों एवं बहनों की पीड़ा को स्वर दिया गया, जो गंभीर अपराधों का शिकार हुई हैं। भावपूर्ण प्रस्तुति के दौरान कई महिलाओं की आंखें नम हो गईं।

महिला कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रक्षाबंधन पर लाई गई राखियां केवल पर्व की रस्म नहीं बल्कि बेटियों की सुरक्षा, न्याय और सरकार की जवाबदेही का प्रतीक हैं। काफी देर तक मुख्यमंत्री से मुलाकात का प्रयास किया गया, लेकिन जब मुलाकात नहीं हो सकी तो महिलाओं ने प्रशासन के अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में अंकिता भंडारी मामले में पूर्ण न्याय, जांच की वर्तमान स्थिति और प्रगति स्पष्ट करने तथा कथित वीआईपी की पहचान और भूमिका से जुड़े सवालों का निष्पक्ष जांच के माध्यम से जवाब सामने लाने की मांग की गई। इसके साथ ही महिला और बाल अपराधों के गंभीर मामलों की समयबद्ध जांच, फास्ट ट्रैक अदालतों में सुनवाई और पीड़ित परिवारों को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग भी उठाई गई।

नंदानगर में दरकी पहाड़ी, मलबे की चपेट में आए दो वाहन

टैक्सी स्टैंड के पास गिरे पत्थर; बाल-बाल बचे लोग।

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

नंदानगर में सितेल-सुतोल टैक्सी स्टैंड के पास गुरुवार को अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। भारी मलबे और बड़े पत्थरों की चपेट में आने से सड़क किनारे खड़े दो वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। भूस्खलन के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि घटना के दौरान कोई व्यक्ति मलबे की चपेट में नहीं आया।

स्थानीय लोगों के अनुसार पहाड़ी टूटने के बाद काफी देर तक मलबा और बड़े-बड़े पत्थर गिरते रहे। इस दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी जारी थी, जिससे हादसे का खतरा बना रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में जाने से रोक दिया।

नंदानगर के उपनिरीक्षक मनोज भट्ट ने बताया कि सितेल एवं सुतोल टैक्सी स्टैंड के पास पहाड़ी का हिस्सा अचानक टूट गया। मलबे की चपेट में आने से दो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि पहाड़ी से अभी भी मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। मानसून के दौरान चमोली में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।

रुद्रपुर में धामी ने छात्रों से जाना भविष्य का उत्तराखंड

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'मेरे सपनों का उत्तराखंड' विषय पर आयोजित मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने युवाओं के विचार, सुझाव और भविष्य के उत्तराखंड की उनकी परिकल्पना जानी तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मार्गदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार शिक्षा के साथ रोजगार, कौशल विकास, नवाचार, उद्यमिता, पर्यटन, कृषि, खेल और तकनीक के क्षेत्र में अवसर बढ़ा रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के संकल्प से जुड़कर योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 'मेरे सपनों का उत्तराखंड' प्रतियोगिता में प्रदेशभर के 2,67,744 विद्यार्थियों ने अपने विचार और निबंध भेजे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की सोच और प्रतिभा को अवसर देकर आत्मनिर्भर एवं विकसित उत्तराखंड का निर्माण किया जाएगा।

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

◆ **राज्यपाल गुरमीत सिंह बोले- रक्षाबंधन पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने वाला पर्व**

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के पवित्र रिश्ते, अटूट स्नेह, विश्वास और अपनत्व का प्रतीक पर्व है। यह त्योहार पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के साथ समाज में प्रेम, सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा देता है।

राज्यपाल ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि मातृशक्ति के सम्मान और स्नेह का अवसर भी है। बहनें परिवार में स्नेह, संस्कार और संवेदनाओं की मजबूत आधारशिला होती हैं। उनका अपनापन और आशीर्वाद परिवार को मजबूती देने के साथ समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे पर्व भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से इस पर्व को प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाने का आह्वान किया।

उन्होंने इस पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।

घरेलू कहासुनी में पति ने पत्नी को पाटल से काटकर उतारा मौत के घाट

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

डालनवाला क्षेत्र के मोहनी रोड पर घरेलू विवाद के बाद एक पति ने अपनी पत्नी की पाटल से वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कुछ ही समय बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अयोध्या निवासी रामजी लाल करीब तीन महीने पहले पत्नी और तीन बच्चों के साथ काम की तलाश में देहरादून आया था। करीब दस दिन पहले ही परिवार मोहनी रोड स्थित किराये के मकान में रहने लगा था। रामजी लाल राजमिस्त्री का काम करता था। गुरुवार सुबह काम पर जाने को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने पत्नी पर पाटल से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर डालनवाला पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मृतका की बहन ने बताया कि दोनों के बीच पहले किसी तरह के तनाव की जानकारी नहीं थी।

हल्द्वानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रथम चरण का शिलान्यास आज

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के खेल क्षेत्र में शुक्रवार को नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में समारोह आयोजित कर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों की समीक्षा की और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना युवाओं और खेल प्रतिभाओं के लिए ऐतिहासिक अवसर है। विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक खेल सुविधाएं और खेल विज्ञान से जुड़ी सुविधाएं प्रदेश में ही उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना उनका लंबे समय से देखा गया सपना था, जो अब धरातल पर उतर रहा है।

एसआईआर में थोक आपत्तियों को लेकर कांग्रेस का हमला

धस्माना बोले- पात्र नागरिक को मताधिकार से वंचित करना असंवैधानिक

◆ **धस्माना ने 6500 फॉर्म-7 की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की**

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाने का लगाया आरोप।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एआईसीसी सदस्य सूर्यकांत धस्माना ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रतिवेदन सौंपकर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। धस्माना ने आरोप लगाया कि एसआईआर के दौरान मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए सुनियोजित तरीके से आपत्तियां दाखिल की जा रही हैं।

उन्होंने देहरादून के टर्नर रोड निवासी मोहम्मद अलीम और उनकी पत्नी खशीन फारूकी का मामला उठाते हुए कहा कि दोनों का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है और वे लंबे समय से देहरादून में रह रहे हैं। उनके अनुसार दोनों के आवेदन बार-बार खारिज किए जा रहे हैं, जबकि वे उसी विधानसभा क्षेत्र के भीतर दूसरे पते पर स्थानांतरित हुए हैं।

धस्माना ने ऊधमसिंह नगर की किच्छा, गदरपुर, खटीमा, नानकमत्ता और रुद्रपुर विधानसभा सीटों में लगभग 6500 फॉर्म-7 दाखिल किए जाने का भी उल्लेख किया। उनका दावा है कि इन आपत्तियों में बड़ी संख्या मुस्लिम मतदाताओं से संबंधित है और कई आपत्तियां सीमित लोगों द्वारा दाखिल की गई हैं।

उन्होंने मांग की कि इन सभी आपत्तियों की स्वतंत्र समीक्षा हो तथा बिना बूथ स्तर अधिकारी की जांच, दस्तावेजी प्रमाण और संबंधित मतदाता को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिए किसी का नाम न हटाया जाए। धस्माना ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद है और पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित करना गंभीर विषय है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने की मांग की।

रुद्रपुर में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले ठुकराल समेत कांग्रेस नेता हिरासत में

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिला मुख्यालय दौरे के दौरान रुद्रपुर में सियासी माहौल उस समय गरमा गया, जब जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन सौंपने जा रहे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल समेत कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सिटी क्लब के पास हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं उनके सामने रखना चाहते थे।

पूर्व विधायक ठुकराल अपने समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी में थे। इसी दौरान मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और उन्हें घेर लिया। पुलिस ने ठुकराल समेत कांग्रेस प्रदेश सचिव दिनेश पंत, जिला पंचायत सदस्य सुखदेव हालदार, दिनेश कोली, राम सेवक कोली, आनंद शर्मा और सुनील चुघ सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस वाहन से वहां से रवाना कर दिया।

पुलिस की कार्रवाई के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई। उन्होंने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई का विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने से रोकने का प्रयास बताया।

पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि उनका उद्देश्य मुख्यमंत्री का विरोध करना नहीं था। वे जिला अस्पताल की समस्याओं और क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रही परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराने जा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल लंबे समय से अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है और कई मामलों में उन्हें दूसरे अस्पतालों के लिए रेफर किया जाता है। ठुकराल ने मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं शुरू नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े सवाल जनता के हित से जुड़े हैं और कांग्रेस इन मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी।

लुधियाना ग्रेनेड साजिश में आतंकी नेटवर्क का हुआ खुलासा

मलेशिया से लौटे तीन संदिग्धों से पूछताछ में जेलों और विदेशों तक फैले नेटवर्क के मिले सुराग

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना

मलेशिया से हाल ही में डिपोर्ट कर भारत लाए गए तीन संदिग्धों से पुलिस और खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में पंजाब में सक्रिय सीमा पार से संचालित नार्को-टेरर नेटवर्क को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ कथित तौर पर पंजाब में आतंकी गतिविधियों और विस्फोटों को अंजाम देने के लिए स्थानीय गैंगस्टरों और जेलों में बंद अपराधियों का इस्तेमाल कर रही थी। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में सामने आई जानकारी लुधियाना की सब्जी मंडी के पास चीनी निर्मित ग्रेनेड से किए जाने वाले कथित नाकाम हमले की साजिश से भी जुड़ी है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक डिपोर्ट किए गए आरोपियों अजय मलेशिया, जसप्रीत सिंह उर्फ जस बेहबल और पवनदीप सिंह से गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े संपर्कों की जानकारी सामने आई। अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकी संचालक कथित तौर पर इस नेटवर्क को निर्देश दे रहा था और मलेशिया में रह रहे अली नामक व्यक्ति के माध्यम से आरोपियों तक संदेश पहुंचाए जा रहे थे।

जांच के अनुसार मलेशिया में रहने के दौरान जस बेहबल की मुलाकात अली से हुई थी। पुलिस का दावा है कि अली पाकिस्तानी खुफिया तंत्र के संपर्क में था और उसके माध्यम से जस बेहबल तथा उसके साथियों के संपर्क सीमा पार बैठे संचालकों से हुए। अजय मलेशिया के बारे में भी जांच में खालिस्तानी कट्टरपंथियों और विदेशी संचालकों से संपर्क होने की जानकारी सामने आने की बात कही गई है।

पुलिस के मुताबिक इस मामले के तार पंजाब और राजस्थान की जेलों तक जुड़े हुए हैं। मामले में पुलिस पहले ही 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें श्री मुक्तसर साहिब, श्री गंगानगर और फरीदकोट की जेलों में बंद छह कैदी भी शामिल हैं।

जांच के अनुसार राजस्थान के गंगानगर निवासी अजय और फरीदकोट निवासी जस बेहबल ने जेल में बंद अपने संपर्कों के माध्यम से कुछ युवकों को कथित साजिश में शामिल किया। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है।

पुलिस के अनुसार इससे पहले लुधियाना के शिवपुरी चौक के पास गश्त के दौरान कुलदीप नामक युवक को ग्रेनेड से भरे बैग के साथ गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसका साथी शेखर फरार हो गया था। पूछताछ में कथित तौर पर सामने आया कि अमृतसर से विस्फोटक लाकर लुधियाना में हमला करने की योजना थी।

जांच अधिकारियों का कहना है कि यह हमला सीमा पार बैठे संचालकों के साथ कथित सौदे का हिस्सा था। अजय मलेशिया पर पाकिस्तानी संचालकों के लिए नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क में शामिल होने का भी आरोप है। पुलिस अब इस पूरे मामले में आर्थिक लेनदेन और अन्य संपर्कों की भी जांच कर रही है।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाए जाने की आशंका है। इसके बाद स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से इन्हें अलग-अलग स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क में नशीले पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और आतंकी गतिविधियों के बीच संबंधों की जांच कर रही हैं।

पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य मददगारों, स्लीपर सेल और संदिग्ध संपर्कों की तलाश में जुटी है। जांच एजेंसियां गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी का सत्यापन कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों की भूमिका सामने आ सकती है।

नेपाल बाढ़ के बाद लापता चंडीगढ़ वासियों की तलाश तेज, प्रशासन ने मांगी जानकारी

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। नेपाल में हाल ही में आई अचानक बाढ़ के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने नेपाल में लापता हुए शहर के निवासियों की जानकारी जुटाने के लिए पहल शुरू की है। प्रशासन ने शहर के लोगों से अपील की है कि यदि उनका कोई परिजन, परिचित या चंडीगढ़ निवासी नेपाल में बाढ़ की घटना के बाद से लापता है या उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो इसकी सूचना उपायुक्त कार्यालय को दी जाए।

प्रशासन की ओर से इसके लिए विशेष नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य नेपाल में फंसे या लापता चंडीगढ़वासियों से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना है, ताकि जरूरत के अनुसार बचाव एवं सहायता कार्यों में समन्वय किया जा सके।

चंडीगढ़ प्रशासन ने नागरिकों से कहा है कि लापता व्यक्ति से संबंधित जानकारी नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 112 या 0172-2700025 पर दी जा सकती है। इसके अलावा नागरिक ड्डस्त्रष्-ष्द्धस्त्रञ्चठ्ठद्ब.द्बठ्ठ पर ई-मेल के माध्यम से भी सूचना भेज सकते हैं। उपायुक्त कार्यालय के कार्यालय अधीक्षक मोहन सिंह से भी इस संबंध में संपर्क किया जा सकता है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सूचना देते समय लापता व्यक्ति का नाम, चंडीगढ़ में पता, नेपाल में संभावित स्थान, यात्रा से जुड़ी जानकारी और उपलब्ध संपर्क विवरण साझा करें। इससे संबंधित अधिकारियों को व्यक्ति की पहचान और संभावित स्थिति का पता लगाने में मदद मिल सकेगी।

प्रशासन के अनुसार नियंत्रण कक्ष के माध्यम से प्राप्त सभी सूचनाओं को संकलित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों के साथ जानकारी साझा की जाएगी, ताकि नेपाल में लापता लोगों का पता लगाने के प्रयासों में मदद मिल सके।

नेपाल में प्राकृतिक आपदा के बाद कई क्षेत्रों में लोगों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने निवासियों से जुड़ी किसी भी संभावित सूचना को गंभीरता से लेने का निर्णय लिया है। प्रशासन का कहना है कि समय पर मिली जानकारी से प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

चंडीगढ़ प्रशासन ने नागरिकों से इस अपील को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि नेपाल में फंसे अथवा लापता चंडीगढ़ निवासियों के संबंध में समय रहते जानकारी जुटाई जा सके।

प्रशासन ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को नेपाल में मौजूद किसी चंडीगढ़ निवासी के लापता होने की जानकारी है, तो वह बिना देरी किए नियंत्रण कक्ष या उपायुक्त कार्यालय से संपर्क करे। प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे।

बठिंडा में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क, अस्पताल में तैयारियां तेज

सिविल अस्पताल में छह बिस्तरों का विशेष वार्ड, फ्लू केंद्र में होगी मरीजों की जांच

भारतेंदु संवाददाता, बठिंडा। मौसम में बदलाव और तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू और अन्य वायरल संक्रमणों से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। संभावित मरीजों को समय पर जांच और उपचार उपलब्ध कराने के लिए बठिंडा के सिविल अस्पताल में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। अस्पताल के मेडिकल वार्ड में छह बिस्तरों का अलग स्वाइन फ्लू वार्ड तैयार किया गया है। जरूरत पड़ने पर संदिग्ध और संक्रमित मरीजों को इस वार्ड में भर्ती कर उपचार दिया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से वार्ड में मरीजों के लिए जरूरी दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। विभाग का उद्देश्य संभावित मामलों की पहचान जल्द करना और संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाना है।

अस्पताल में बनाया गया विशेष फ्लू केंद्र : सिविल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण बांसल ने बताया कि अस्पताल की आपातकालीन सेवा के पास विशेष फ्लू केंद्र बनाया गया है। यहां ऐसे मरीजों की जांच की जाएगी, जिनमें स्वाइन फ्लू या अन्य वायरल संक्रमण से जुड़े लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने बताया कि बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, कमजोरी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण वाले मरीजों की चिकित्सकीय जांच की जाएगी। चिकित्सक की सलाह के अनुसार जरूरत पड़ने पर मरीज का नमूना लेकर आगे की जांच करवाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि संदिग्ध मरीजों की आरटीपीसीआर जांच की सुविधा अस्पताल की प्रयोगशाला में ही उपलब्ध रहेगी। इससे नमूने की जांच के लिए मरीजों को दूसरी जगह जाने की जरूरत कम होगी और जांच प्रक्रिया में लगने वाला समय भी कम किया जा सकेगा। रिपोर्ट और मरीज की स्थिति के आधार पर चिकित्सक आगे के उपचार का निर्णय ले सकेंगे।

छह बिस्तरों का अलग वार्ड तैयार : अस्पताल प्रशासन ने संभावित स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए छह बिस्तरों का अलग वार्ड तैयार किया है। इसमें संदिग्ध और संक्रमित मरीजों को जरूरत के अनुसार भर्ती किया जा सकेगा। वार्ड में आवश्यक दवाइयां और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध रखने के साथ कर्मचारियों की भी व्यवस्था की गई है।

जालंधर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

भारतेंदु संवाददाता, जालंधर। अवैध शराब की तस्करी और बिक्री के खिलाफ जालंधर पुलिस तथा आबकारी विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। जिले के अलग-अलग इलाकों में टीमों ने छापेमारी कर नाजायज शराब बरामद की और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जालंधर वेस्ट के थाना भार्गव कैंप पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब पांच पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उससे शराब के स्रोत और इसकी आगे की सप्लाई से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं, भोगपुर पुलिस ने बिल्ला नामक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चंडीगढ़ मार्का शराब बरामद होने की बात सामने आई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी शराब कहां से लेकर आया था और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बाद अवैध शराब का कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में शराब की अवैध तस्करी, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है और अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान करने में जुटी है।

पंजाब में एनालॉग पनीर पर एक साल तक पूरी तरह रोक

उत्पादन, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर भी सरकार ने लगाया प्रतिबंध

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य में एनालॉग यानी गैर-डेयरी पनीर के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(ए) के तहत जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

सरकार के फैसले के बाद राज्य में एनालॉग पनीर से जुड़े कारोबार पर पूरी तरह रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति या कारोबारी इसका उत्पादन करने, गोदाम में रखने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने, वितरण करने या बेचने का काम नहीं कर सकेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

क्या है एनालॉग पनीर : एनालॉग पनीर सामान्य दूध से तैयार होने वाले असली पनीर से अलग होता है। इसे दूध की जगह वनस्पति तेल, वनस्पति वसा, स्टार्च और अन्य सामग्री का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है। कई बार ऐसे उत्पादों को असली पनीर के नाम पर बाजार में बेचने की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए इसके उत्पादन और कारोबार पर रोक लगाने का फैसला किया है।

निर्माण से बिक्री तक पूरी रोक : सरकारी आदेश के अनुसार एनालॉग पनीर का केवल उत्पादन ही प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बल्कि इसके भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर भी रोक रहेगी। इसका मतलब है कि निर्माता, थोक कारोबारी, वितरक और दुकानदार किसी भी स्तर पर इस उत्पाद का कारोबार नहीं कर सकेंगे। खुले में या पैक करके एनालॉग पनीर की बिक्री करना भी प्रतिबंध के दायरे में आएगा।

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य बाजार में ऐसे उत्पादों की उपलब्धता को नियंत्रित करना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित तथा मानकों के अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को आदेश का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

उल्लंघन पर कार्रवाई : प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई कारोबारी एनालॉग पनीर का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण या बिक्री करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभागों द्वारा बाजार और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच भी की जा सकती है।

सातवीं की नूर ने दूसरी बार कैंसर मरीजों के लिए दान किए अपने बाल

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। सेवा की भावना उम्र की मोहताज नहीं होती। चंडीगढ़ की सातवीं कक्षा की छात्रा नूर सचदेवा ने इसका उदाहरण पेश करते हुए दूसरी बार कैंसर मरीजों के लिए अपने बाल दान किए हैं। नूर सेक्टर-35 स्थित खालसा पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं और परिवार के साथ खरड़ में रहती हैं।

नूर ने वर्ष 2024 में भी कैंसर मरीजों के लिए अपने बाल दान किए थे। इस बार भी उनके बाल मुंबई स्थित मेदांता अस्पताल भेजे जाएंगे, जहां उनसे मरीजों के लिए विग तैयार की जाएगी। नूर का कहना है कि कैंसर से जूझ रहे मरीजों को बाल झड़ने के कारण खुद को अकेला या दूसरों से अलग महसूस नहीं करना चाहिए। वह चाहती हैं कि उनके बाल किसी मरीज के चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास वापस लाने में मदद करें।

नूर के पिता सतीश सचदेवा ने बताया कि उनकी बेटी ने एक बार कैंसर पीड़ित महिला को देखा था, जिसके इलाज के दौरान सारे बाल झड़ गए थे। इस दृश्य से प्रभावित होकर नूर ने पूछा कि वह ऐसे मरीजों की मदद कैसे कर सकती है। पिता ने उसे बाल दान कर विग बनाने की जानकारी दी, जिसके बाद नूर ने यह संकल्प लिया।

सतीश सचदेवा खुद भी समाजसेवा से जुड़े हैं और अब तक 158 बार प्लेटलेट्स दान कर चुके हैं। उन्होंने जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए 'लीव फॉर ह्यूमैनिटी' संस्था भी बनाई है। नूर का कहना है कि यदि थोड़े से बाल किसी कैंसर मरीज के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है।

छोटे कारोबारी एआई से कम समय और खर्च में विज्ञापन कर सकेंगे तैयार

एआई इंसानों की जगह नहीं लेगा, काम की दक्षता बढ़ाएगा; छोटे कारोबारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। डिजिटल विज्ञापन और विपणन के तेजी से बदलते दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने कारोबारियों के सामने नई संभावनाएं खोल दी हैं। हालांकि, एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ नौकरियों पर असर, फर्जी खबरों और डीपफेक जैसी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। टेडएक्स के मंच पर चंडीगढ़ में गूगल एड्स सॉल्यूशंस के कंट्री हेड अंकित शर्मा ने दैनिक जागरण के वरिष्ठ संवाददाता बलवान करिवाल से बातचीत में एआई के भविष्य और डिजिटल विज्ञापन में इसकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की।

अंकित शर्मा ने कहा कि एआई पूरी तरह इंसानों की जगह नहीं लेगा। इसके बजाय यह काम करने की दक्षता बढ़ाएगा। भविष्य में एआई कई कार्य करेगा, लेकिन उसे दिशा देने, नियंत्रित करने और निर्णय लेने की भूमिका इंसान की रहेगी। उन्होंने कहा कि कई ऐसे काम हैं, जिनमें मानवीय मौजूदगी जरूरी होती है। मशीन किसी कार्य को एक स्तर तक कर सकती है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार बदलाव या काम को अनुकूलित करने के लिए इंसान की जरूरत होगी।

उन्होंने बताया कि आने वाले समय में 'ह्यूमन इन द लूप' की जगह 'ह्यूमन इन द लीड' की अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। यानी एआई और एआई एजेंट काम करेंगे, लेकिन इंसान उनकी निगरानी करते हुए उन्हें दिशा देगा। इससे नौकरियों में दक्षता बढ़ेगी और कई कार्य स्वचालित होंगे, लेकिन पूरा कार्यबल खत्म नहीं होगा।

लुधियाना में न्यूजीलैंड भेजने के नाम पर 12 लाख की ठगी

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना। विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले कबूतरबाजों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। ताजा मामले में एक व्यक्ति के छोटे भाई को न्यूजीलैंड भेजने का झांसा देकर 12 लाख रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपी ने न तो पीड़ित के भाई को विदेश भेजा और न ही पैसे वापस किए। पुलिस की जांच के बाद थाना दरेसी पुलिस ने आरोपी पारस कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी शिकायत में गुरप्रीत सिंह ने बताया कि आरोपी पारस कुमार ने उसे अपनी बातों में लेकर विश्वास में लिया। आरोपी ने दावा किया था कि विदेश में उसकी अच्छी जान-पहचान और प्रभाव है।

बिना परमिट शराब परोसने पर मोहाली कैफे मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

भारतेंदु संवाददाता, मोहाली। सेक्टर-118 स्थित टीडीआई सिटी के 'द अमीगोज कैफे एंड लाउंज' में बिना लाइसेंस ग्राहकों को शराब परोसने का मामला सामने आया है। गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार रात आबकारी विभाग की टीम ने कैफे में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने रोयल स्टैग व्हिस्की की तीन बोतलें बरामद कीं।

आबकारी विभाग की शिकायत पर बलौंगी थाना पुलिस ने कैफे मालिक राहुल चौधरी के खिलाफ पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 68-1-14 के तहत मामला दर्ज कर उसे मौके से हिरासत में ले लिया। विभाग को सूचना मिली थी कि कैफे में बिना वैध लाइसेंस या परमिट के शराब रखकर ग्राहकों को परोसी जा रही है।

सूचना के बाद आबकारी निरीक्षक अशोक कुमार ने कर्मचारियों के साथ कैफे में छापा मारा। पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही। छापेमारी के दौरान कैफे में दो लोग शराब पीते मिले,

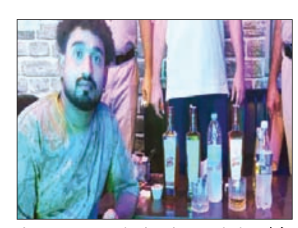

लेकिन टीम को देखते ही दोनों मौके से फरार हो गए। वहीं, कैफे में मौजूद राहुल चौधरी ने खुद को संचालक बताया। अधिकारियों ने शराब रखने और परोसने संबंधी लाइसेंस या परमिट मांगा, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

जांच के दौरान कैफे से बरामद तीन बोतलों में एक खुली और दो सीलबंद थीं। आबकारी टीम ने शराब के नमूने लेकर बाकी माल कब्जे में ले लिया। बरामद शराब की बोतलों पर 'फोर सेल इन पंजाबी ओनली' लिखा हुआ था। पुलिस के अनुसार आरोपित राहुल चौधरी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का निवासी है।

कर्मचारियों की हड़ताल पर राजा वड़िंग ने सरकार को घेरा, लंबित मांगें पूरी करने की उठाई मांग

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की महाहड़ताल को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह राजा वड़िंग ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को अपनी लंबित मांगों और अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। कर्मचारियों की महाहड़ताल सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

राजा वड़िंग ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके साथ संवाद करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय कर्मचारियों को आंदोलन करने और अपने अधिकारों के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने को मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है।

पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा अधूरा : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले सरकारी कर्मचारियों से कई वादे किए थे। इनमें पुरानी पेंशन योजना लागू करना और कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान करना प्रमुख मुद्दे थे। उनका आरोप है कि सरकार की ओर से इन मांगों को अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।

वड़िंग ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आवाज उठा रहे हैं। कई बार बातचीत और ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन जब कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लगातार टालने से स्थिति और गंभीर होती जा रही है।

हड़ताल से आम लोगों को परेशानी : राजा वड़िंग ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। इससे अपने जरूरी काम कराने के लिए सरकारी कार्यालयों में पहुंचने वाले आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हड़ताल लंबी खिंचने से इसका असर आम जनता पर और बढ़ सकता है।

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि कर्मचारियों के साथ तत्काल बातचीत शुरू कर उनकी जायज मांगों पर निर्णय लिया जाए। सरकार को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कर्मचारियों का आंदोलन समाप्त हो और सरकारी विभागों में कामकाज सामान्य हो सके।

जांच | दस दिन में दूसरी बार पहुंचीं, सीएलयू मंजूरी अनियमितताओं पर पूछताछ जारी

मोहाली परियोजना मामले में आइएएस बराड़ फिर पहुंचीं प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय

भारतेंदु संवाददाता, जालंधर। मोहाली की एक बड़ी आवासीय परियोजना से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में आइएएस अधिकारी कंवलप्रीत कौर बराड़ वीरवार को दस दिन में दूसरी बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचीं। वह सुबह करीब 10 बजे कार्यालय पहुंचीं और बिना किसी से बातचीत किए सीधे अंदर चली गईं। उनके दूसरी बार ईडी कार्यालय पहुंचने के बाद मामले की जांच को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है।

ईडी की जांच मोहाली की उक्त आवासीय परियोजना में भूमि उपयोग परिवर्तन यानी सीएलयू की मंजूरी से संबंधित कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। जिन मंजूरियों को लेकर जांच की जा रही है, उस समय कंवलप्रीत कौर बराड़ संबंधित पद पर तैनात थीं। इसी वजह से ईडी की ओर से उनसे परियोजना से जुड़े निर्णयों, मंजूरियों और संबंधित दस्तावेजों को लेकर पूछताछ की जा रही है।

इससे पहले ईडी ने कंवलप्रीत कौर बराड़ को 18 अगस्त को पूछताछ के लिए जालंधर कार्यालय बुलाया था। उस दौरान उनसे करीब आठ घंटे तक पूछताछ की गई थी। अब दस दिन के भीतर दूसरी बार उन्हें जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। हालांकि, वीरवार को उनसे किन विशेष बिंदुओं पर सवाल किए जा रहे हैं और पूछताछ कितनी देर चलेगी, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

ईडी की जांच में परियोजना को लेकर भूमि उपयोग परिवर्तन की मंजूरी से संबंधित प्रक्रिया और

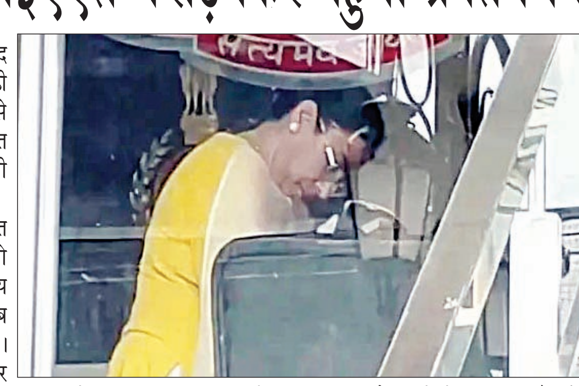

उसमें अपनाए गए नियमों की पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसी यह भी देख रही है कि परियोजना को मंजूरी देने के दौरान निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन किया गया था या नहीं।

मामले में उस समय संबंधित पदों पर तैनात रहे कुछ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। ईडी की ओर से परियोजना से जुड़ी मंजूरियों, सरकारी दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। जांच का उद्देश्य कथित अनियमितताओं से जुड़े तथ्यों और जिम्मेदारियों का पता लगाना है।

कंवलप्रीत कौर बराड़ के वीरवार को ईडी कार्यालय पहुंचने के दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधे कार्यालय के अंदर चली गईं। इससे पहले भी 18 अगस्त को पूछताछ के दौरान उन्होंने मामले को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी थी।

दस दिन के भीतर आइएएस अधिकारी को दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाए जाने से मोहाली की आवासीय परियोजना से जुड़ी जांच को लेकर हलचल बढ़ गई है। ईडी की ओर से परियोजना से संबंधित दस्तावेजों और अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल जारी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि जांच के अगले चरण में किन अधिकारियों या संबंधित पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

कश्मीर की पांच ग्लेशियल झीलें बेहद संवेदनशील, 2704 इमारतों पर मंडरा रहा खतरा

वैज्ञानिक आकलन ने बढ़ाई चिंता, संभावित झील फटने से आबादी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को खतरा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों और उनसे जुड़ी झीलों में तेजी से हो रहे बदलाव के बीच जम्मू-कश्मीर की पांच ग्लेशियल झीलों को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लेशियल झील फटने से आने वाली बाढ़ के लिहाज से 'बहुत अधिक संवेदनशील' श्रेणी में रखा गया है। वैज्ञानिक आकलन के अनुसार इन झीलों से संभावित बाढ़ की स्थिति में डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में 2,704 इमारतों के अलावा करीब 15 बड़े पुल, सड़क मार्ग और कम से कम एक जलविद्युत परियोजना प्रभावित हो सकती है।

यह आकलन ऐसे समय सामने आया है, जब हिमालयी क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ और ग्लेशियल झीलों के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता बढ़ रही है। नेपाल में अगस्त 2024 में थामे गांव में ग्लेशियल झील से आई बाढ़ ने मकानों, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया था। वहीं 26 अगस्त 2026 को नेपाल के रसुवा क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ ने भी हिमालयी इलाकों में अचानक आने वाली जल आपदाओं के खतरे को सामने ला दिया।

> **वैज्ञानिकों** के अनुसार किसी ग्लेशियल झील से निकलने वाली बाढ़ की गंभीरता का आकलन केवल उसके क्षेत्रफल से नहीं किया जा सकता। झील की वास्तविक गहराई, पानी की कुल मात्रा, संभावित बहाव की गति और नीचे तक पहुंचने में लगने वाले समय का सटीक आंकड़ा भी जरूरी है।

155 ग्लेशियल झीलों का वैज्ञानिक अध्ययन : कश्मीर विश्वविद्यालय के जियोइन्फार्मेटिक्स विभाग के शोधकर्ताओं ने कश्मीर हिमालय की 155 ग्लेशियल झीलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। शोध में झीलों के क्षेत्रफल में बदलाव, प्राकृतिक बांधों की स्थिरता और आसपास की भू-आकृतिक परिस्थितियों सहित कई संकेतकों का विश्लेषण किया गया।

अध्ययन के आधार पर ब्रामसर, चिरसर, नुंदकोल, गंगाबल और भागसर झीलों को ग्लेशियल झील फटने के लिहाज से 'बहुत अधिक संवेदनशील' माना गया है। इन झीलों से संभावित बाढ़ के रास्तों और उनके नीचे स्थित आबादी तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का भी भू-स्थानिक आकलन किया गया है।

विशेषज्ञों के अनुसार इस श्रेणी में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि झीलें वर्तमान में अस्थिर हैं या उनके प्राकृतिक बांध तत्काल टूटने वाले हैं। इसका अर्थ है कि किसी प्राकृतिक घटना या अन्य परिस्थितियों के कारण इनमें अचानक पानी निकलने का खतरा तुलनात्मक रूप से अधिक हो सकता है।

2,704 इमारतें संभावित प्रभाव क्षेत्र में

अध्ययन के मुताबिक पांचों झीलों के संभावित बाढ़ मार्गों के नीचे करीब 2,704 इमारतें और लगभग 15 बड़े पुल स्थित हैं। सड़क नेटवर्क तथा एक जलविद्युत परियोजना पर भी असर पड़ सकता है। गांदरबल, शोपियां और कुलगाम सहित विभिन्न क्षेत्रों में संभावित बाढ़ मार्गों के आसपास स्थित बस्तियों और ढांचागत सुविधाओं की पहचान की गई है। नुंदकोल और गंगाबल झीलों से निकलने वाला पानी वांगथ नाला होते हुए सिंध नदी तंत्र की ओर जाता है। संभावित बाढ़ की स्थिति में इन दोनों झीलों से जुड़े क्षेत्र में 1,184 इमारतों, चार पुलों और एक जलविद्युत परियोजना के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

तीन दशक बाद वंधामा हत्याकांड की जांच फिर शुरू

गांदरबल। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (सीआईए) ने वर्ष 1998 के चर्चित वंधामा हत्याकांड की जांच दोबारा शुरू कर दी है। गांदरबल जिले के वंधामा गांव में 25 जनवरी, 1998 को आतंकवादियों ने 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी थी। मृतकों में नौ महिलाएं और चार बच्चे भी शामिल थे।

जानकारी के अनुसार, सेना की वर्दी में आतंकवादियों का एक समूह गांव में पहुंचा था। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद कश्मीरी पंडित परिवारों को एक स्थान पर एकत्र होने के लिए कहा। इसके बाद उनके घरों में घुसकर गोलीबारी की गई, जिसमें 23 लोगों की जान चली गई। इनमें चार ऐसे परिवार भी शामिल थे, जिन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में आतंकवाद के बावजूद घाटी नहीं छोड़ी थी।

घटना के संबंध में गांदरबल पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन करीब तीन दशक बाद भी मामला अनसुलझा रहा। अधिकारियों के अनुसार, पुलिस जांच में हत्याकांड में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादियों की भूमिका सामने आई थी। अब दोबारा जांच का उद्देश्य हत्याकांड में शामिल आतंकवादियों के साथ उनके मददगारों की पहचान करना है।

बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ उद्योग जगत ने जेईआरसी से रोक की मांग की

उद्योगों पर बिजली दर बढ़ोतरी के खिलाफ एफसीआइके ने खोला मोर्चा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

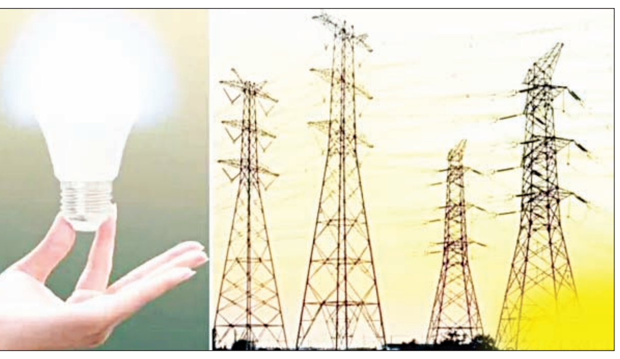

कश्मीर घाटी के उद्योग जगत में बिजली की बढ़ी दरों को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। फेडरेशन ऑफ चैंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर (एफसीआइके) ने बिजली टैरिफ में हुई वृद्धि के खिलाफ कानूनी कदम उठाते हुए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के समक्ष 17 पन्नों की पुनर्विचार याचिका दायर की है। फेडरेशन ने बढ़ी दरों पर तत्काल रोक लगाने और पुराने टैरिफ के आधार पर बिलिंग जारी रखने की मांग की है।

एफसीआइके ने आयोग के 20 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि कुल टैरिफ में 6.83 प्रतिशत वृद्धि बताए जाने के बावजूद औद्योगिक उपभोक्ताओं पर वास्तविक बोझ करीब 10 प्रतिशत तक बढ़ गया है। फेडरेशन का सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपभोक्ताओं को पांच प्रतिशत प्रस्तावित बढ़ोतरी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अंतिम आदेश में 10 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी गई।

औद्योगिक दरों में करीब 10 प्रतिशत वृद्धि : याचिका के अनुसार कम वोल्टेज वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा शुल्क 4.20 रुपये से बढ़ाकर 4.60 रुपये प्रति किलोवाट-एम्पियर घंटा कर दिया गया है। इससे दर में 9.52 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 11 केवी उच्च वोल्टेज वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए शुल्क 4.10 रुपये से बढ़ाकर 4.50 रुपये किया गया है, जो 9.76 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके अलावा स्थायी और मांग शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है।

फेडरेशन ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों के पास अभी श्रेणी और वोल्टेज के अनुसार आपूर्ति लागत का विश्वसनीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र पर इतनी बड़ी वृद्धि का आधार स्पष्ट नहीं है।

एफसीआइके ने मांग की है कि जब तक श्रेणीवार आपूर्ति लागत से संबंधित विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, तब तक पुराने टैरिफ को बहाल रखा जाए। साथ ही श्रेणीवार घाटे, बिजली संग्रह, बकाया राशि और डूबे कर्ज का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की गई है।

जम्मू-कश्मीर में बदलेगा मौसम, 31 अगस्त से कई इलाकों में बारिश बढ़ने के आसार

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आने वाले दिनों में गर्म और उमस भरा मौसम बने रहने की संभावना है। श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27 से 30 अगस्त तक मौसम सामान्यत: गर्म और उमस भरा रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर सुबह और दोपहर के समय हल्की बारिश तथा गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार 31 अगस्त और 1 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और कुछ क्षेत्रों में सुबह व दोपहर के समय बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। इसके बाद 2 से 7 सितंबर तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, इस अवधि में भी कुछ स्थानों पर सुबह और दोपहर के समय हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी रहेगी।

रक्षाबंधन पर इस बार नहीं दिखेगा चंद्रग्रहण, राहुकाल के बाद बांधें राखी

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व इस वर्ष 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा। श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री ने बताया कि श्रावण पूर्णिमा 27 अगस्त सुबह 9:09 बजे शुरू होकर 28 अगस्त सुबह 9:49 बजे समाप्त होगी। सूर्योदय-व्यापिनी पूर्णिमा होने के कारण 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना शास्त्रसम्मत है। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त को राहुकाल सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 बजे तक रहेगा। इस अवधि को छोड़कर दिनभर राखी बांधी जा सकती है। बहन को भाई के माथे पर तिलक लगाकर आरती करनी चाहिए और अक्षत अर्पित करने के बाद दाहिनी कलाई पर रक्षासूत्र बांधना चाहिए। इसके बाद मिठाई खिलाकर भाई का आशीर्वाद लेना चाहिए। भाई भी बहन को उपहार देकर उसकी रक्षा का संकल्प ले।

एच1एन1 से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की सावधानी

भारतेंदु संवाददाता, कठुआ। इन्फ्लुएंजा-ए (एच1एन1) एक मौसमी श्वसन संक्रमण है, जिससे संक्रमित होने पर आमतौर पर घबराने की जरूरत नहीं होती। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार स्वस्थ वयस्कों में यह संक्रमण सामान्य उपचार और सावधानी के साथ समय के साथ ठीक हो जाता है। हालांकि, लक्षणों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। एच1एन1 के प्रमुख लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, शरीर में दर्द और थकान शामिल हैं। कुछ लोगों में कमजोरी और अस्वस्थ महसूस होने की शिकायत भी हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार लक्षणों की तीव्रता और अवधि पर नजर रखना जरूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि यदि बुखार, खांसी या अन्य लक्षण पांच से छह दिनों से अधिक समय तक बने रहते हैं तो चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।

एलिवेटेड कॉरिडोर हादसे की तकनीकी जांच शुरू, गैंट्री खामी पर विशेष नजर

एनएचएआई विशेषज्ञ दल ने शुरू की तकनीकी जांच

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

जम्मू-कठुआ मार्ग पर मंगलवार को दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेसवे के निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर में हुए हादसे की तकनीकी जांच शुरू हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने घटनास्थल की पड़ताल के लिए विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय टीम भेजी है। प्रारंभिक जांच में लांचिंग प्रक्रिया के दौरान तकनीकी खामी की आशंका जताई गई है। हालांकि, हादसे के वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा।

यह हादसा सांबा जिले के जख क्षेत्र में एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज-15 के तहत निर्माण कार्य के दौरान हुआ था। हादसे में एक श्रमिक की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य घायल हुआ था। घटना के बाद निर्माण स्थल पर इस्तेमाल हो रही अत्याधुनिक लांचिंग गैंट्री की कार्यप्रणाली और उससे जुड़े तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है।

एनएचएआइ के जम्मू कार्यालय के अनुसार संबंधित क्षेत्र में लंबे समय से काम कर चुके तीन विशेषज्ञों को जांच के लिए मौके पर भेजा गया है। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ निर्माण कार्य से जुड़े तकनीकी दस्तावेजों की भी समीक्षा शुरू कर दी है। इसके अलावा हादसे से पहले लांचिंग गैंट्री को संचालित करने के लिए अपनाए गए क्रम और प्रक्रिया की भी जांच की जा रही है।

किश्तवाड़ दुष्कर्म मामले में तीन और आरोपित गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, किश्तवाड़। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 15 वर्षीय आदिवासी लड़की से दुष्कर्म और उसकी मौत के मामले में विशेष जांच दल ने तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें जिला अस्पताल में दिहाड़ी कर्मचारी के रूप में काम करने वाला सफाईकर्मी मोहम्मद इशाक और रियाज अहमद शेख शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपितों पर घटना को छिपाने और नाबालिग का गर्भपात कराने की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप है। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपितों की संख्या पांच हो गई है। इससे पहले पुलिस ने सरकारी स्कूल के शिक्षक और उसके भाई को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, शिक्षक पर पिछले कुछ महीनों के दौरान नाबालिग का बार-बार यौन शोषण करने का आरोप है, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई थी।

रक्षा बंधन पर्व में जवानों को मिला बहनों का स्नेह

छात्राओं ने सीमा पर तैनात जवानों को राखी बांधकर जताया सम्मान

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

सीमा से लेकर पुलिस लाइन तक जवानों के साथ छात्राओं ने मनाया रक्षा बंधन पर्व

जम्मू, 27 अगस्त। भारत रक्षा पर्व के तहत जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में रक्षाबंधन के अवसर पर भावुक कर देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए। कठुआ की जिला पुलिस लाइन से लेकर हीरानगर की अंतरराष्ट्रीय सीमा और उधमपुर के बीएसएफ केंद्र तक स्कूली छात्राओं ने देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को अपना भाई मानकर राखी बांधी और उनका मुंह मीठा करवाया। घर-परिवार से दूर ड्यूटी निभा रहे जवानों के लिए यह पल बेहद खास रहे। छात्राओं ने उन्हें शुभकामना कार्ड और संदेश भी भेंट किए।

कठुआ में बच्चियों ने बांधी हाथों से बनाई राखी : भारत रक्षा पर्व के तहत कठुआ की जिला पुलिस लाइन में टाइनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और लर्निंग टेंपल हाई स्कूल की छात्राओं ने पुलिस के विशेष अभियान समूह, अर्धसैनिक बलों और जिला पुलिस लाइन में तैनात जवानों को अपने हाथों से बनाई राखियां बांधीं।

इस दौरान कठुआ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील केसर और पुलिस उपाधीक्षक भगवान दास डांडिया मौजूद रहे। छात्राओं ने जवानों से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद एक बड़ी चुनौती रहा है और इसके खिलाफ लड़ाई में कई जवान शहीद हुए हैं।

उधमपुर में बीएसएफ जवानों को बांधी राखी

उधमपुर के एसटीसी बीएसएफ रौनदोमेल में भी भारत रक्षा पर्व के तहत रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कॉमन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल संगूर की छात्राओं और शिक्षिकाओं ने इसमें भाग लिया। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को राखियां बांधीं और मिठाई खिलाकर पर्व की शुभकामनाएं दीं। छात्राओं और शिक्षिकाओं ने जवानों को बधाई एवं शुभकामना संदेश भी भेंट किए। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए जवानों के समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा को नमन किया।

शीतल देवी की सफलता से देश की बेटियों को मिली नई प्रेरणा

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'खेलो इंडिया संवाद' कार्यक्रम के दौरान जम्मू-कश्मीर की पैरा तीरंदाज शीतल देवी की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उनकी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि जब शीतल देवी ने पैरालंपिक में पदक जीता तो पूरे जम्मू-कश्मीर के साथ देश को भी उन पर गर्व हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। खेल व्यक्ति को उठना, गिरना और गिरकर दोबारा खड़ा होना सिखाता है।

29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर से पहले आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शीतल देवी के अलावा अन्य पैरा खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि खेल बेहतर जीवन जीने और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है।

शीतल देवी जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले के लोईधार गांव की रहने वाली हैं। जन्म से ही उनकी दोनों बाजू नहीं हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपने पैरों और ठुड्डी की मदद से तीरंदाजी में ऐसी पहचान बनाई है, जिसने देश को गौरवान्वित किया है।

शीतल ने पेरिस पैरालंपिक में मिश्रित टीम तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वह कई पदक अपने नाम कर चुकी हैं।

अच्छन में जमा 11 .5 लाख टन कचरे से भूजल और झीलों पर बढ़ा खतरा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

कचरे के पहाड़ से पर्यावरण पर संकट

अच्छन कचरा निपटान स्थल पर करीब 11.5 लाख मीट्रिक टन पुराना और बिना उपचार किया गया कचरा जमा है। वर्ष 1986 से लगातार कचरा डाले जाने के कारण यहां चार दशक में विशाल कचरे का पहाड़ बन गया है। इससे पर्यावरण के साथ-साथ आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।

सबसे बड़ी समस्या कचरे से निकलने वाले प्रदूषित पानी की है। बारिश का पानी जब कचरे के ढेर से होकर गुजरता है तो उसमें हानिकारक पदार्थ मिल सकते हैं। इसके जमीन में रिसने से भूजल और आसपास के जलस्रोत प्रभावित होने की आशंका है।

अच्छन कचरा स्थल को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संयुक्त समिति भी चिंता जता चुकी है। समिति ने जुलाई 2024 में स्थल का निरीक्षण किया था। इस दौरान श्रीनगर में रोजाना पैदा होने वाले कचरे, लैंडफिल की स्थिति और आसपास मौजूद जल निकायों की नजदीकी को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। अंचर, खुशाल सर और गिलसर जैसे महत्वपूर्ण जल क्षेत्र इसके आसपास स्थित हैं।

हालिया वैज्ञानिक अध्ययन में खुशाल सर और अंचर झीलों में सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण का भी अध्ययन किया गया है। इसमें अच्छन कचरा स्थल की इन जल निकायों से नजदीकी का उल्लेख किया गया है।

महंगा प्याज बिगाड़ रहा आम लोगों की रसोई का बजट

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

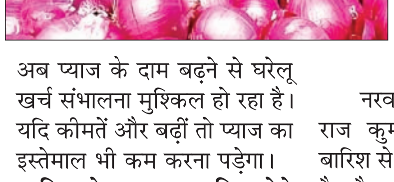

जम्मू में प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। करीब 15 दिन पहले 40 रुपये किलो बिक रहा प्याज अब 60 रुपये किलो तक पहुंच गया है। अचानक बढ़े दामों का असर लोगों की खरीदारी पर साफ दिखाई दे रहा है। पहले जहां परिवार दो से तीन किलो प्याज खरीदकर घर ले जाते थे, वहीं अब लोग एक किलो से ही काम चलाने को मजबूर हैं।

महिलाओं का कहना है कि प्याज लगभग हर सब्जी के तड़के में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सलाद में भी प्याज की मांग रहती है। ऐसे में कीमत बढ़ने से रोजमर्रा की रसोई पर सीधा असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि महंगाई पहले से ही परेशान कर रही है और अब प्याज के दाम बढ़ने से घरेलू खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। यदि कीमतें और बढ़ीं तो प्याज का इस्तेमाल भी कम करना पड़ेगा।

बारिश से फसल प्रभावित होने का असर : व्यापारियों के अनुसार दूसरे राज्यों में बारिश के कारण प्याज की फसल प्रभावित हुई है। नई फसल बाजार में आने में अभी कुछ समय लग सकता है। इसके चलते मंडियों में प्याज की आवक और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हुई हैं। रिहाड़ी के सब्जी विक्रेता मनोज दूबे ने बताया कि मंडी में प्याज महंगा आने के साथ खराब भी पहुंच रहा है। उनका कहना है कि दुकानदार केवल ग्राहकों की जरूरत पूरी करने के लिए प्याज रख रहे हैं, क्योंकि मौजूदा कीमतों में मुनाफा बेहद कम है।

नरवाल मंडी के थोक व्यापारी राज कुमार राजा के मुताबिक बारिश से फसल को नुकसान हुआ है और नई फसल आने में समय लगेगा। उनका अनुमान है कि लोगों को करीब डेढ़ महीने तक महंगे प्याज का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से सरकारी गोदामों में रखे प्याज को बाजार में उतारने की मांग की है, ताकि कीमतों में राहत मिल सके। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई की मांग भी उठाई।

लखनपुर में गोवंश तस्करी नाकाम, 17 गोवंश मुक्त

भारतेंदु संवाददाता, कठुआ

कठुआ जिला पुलिस ने लखनपुर में गोवंश तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए 17 गोवंशों को मुक्त कराया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को भी जब्त किया। यह कार्रवाई एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के निर्देशन में लखनपुर पुलिस टीम ने नाके के दौरान की।

पुलिस के अनुसार बुधवार देर रात लखनपुर के डिस्पैच प्वाइंट पर पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पंजाब से जम्मू-कश्मीर की ओर आ रहे संदिग्ध ट्रक नंबर जेके19ए-5077 को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक में 17 गोवंश लदे मिले। पुलिस ने सभी गोवंशों को ट्रक से मुक्त करवाया और वाहन को कब्जे में ले लिया। मामले में लखनपुर पुलिस ने एफआईआर नंबर 110/2026 दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

गतिरोध | उमर सरकार में कांग्रेस की भागीदारी पर मंत्री पदों का पेंच कायम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत जारी

मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कांग्रेस की दो पदों वाली मांग ने बढ़ाई हलचल

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में कांग्रेस के शामिल होने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने मंत्रिमंडल में अपने लिए दो मंत्री पद सुनिश्चित करने की मांग रखी है। दोनों दलों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। सहमति बनने के बाद ही कांग्रेस सरकार में शामिल होने को लेकर अंतिम फैसला करेगी।

कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर में गठबंधन के सहयोगी हैं, लेकिन कांग्रेस फिलहाल सरकार का हिस्सा नहीं है। अक्टूबर 2024 में उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री पद की शपथ के समय भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में दो पदों की मांग की थी। मांग पर सहमति नहीं बनने के कारण कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने से दूरी बनाए रखी थी।

इसके बाद कांग्रेस ने स्पष्ट किया था कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होने तक वह सरकार में शामिल नहीं होगी। पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर 'हमारी रियासत, हमारा हक' अभियान भी चलाया था। इस अभियान को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कई मौकों पर मतभेद भी सामने आए।

कांग्रेस को एक पद की पेशकश

कांग्रेस के जम्मू-कश्मीर मामलों के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से एक मंत्री पद की पेशकश किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर पार्टी के भीतर विचार-विमर्श चल रहा है और अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पार्टी सरकार में शामिल होने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह दो मंत्री पद चाहती है।

कांग्रेस की शर्तों पर गठबंधन में बातचीत तेज

कांग्रेस चाहती है कि सरकार में भागीदारी के साथ गठबंधन के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी उसकी भूमिका स्पष्ट हो। पार्टी ने समन्वय समिति के गठन को महत्वपूर्ण शर्त बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दोनों दलों के बीच बातचीत पर सभी की नजरें टिकी हैं। कांग्रेस का जोर केवल मंत्री पद हासिल करने तक सीमित नहीं है। पार्टी गठबंधन सरकार में नीतिगत फैसलों और प्रशासनिक मामलों में भी प्रभावी भागीदारी चाहती है।

समन्वय समिति बनाने पर जोर

कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में गठबंधन के दोनों दलों के बीच समन्वय समिति गठित करने पर भी जोर दे रही है। पार्टी का मानना है कि ऐसी समिति बनने से सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में कांग्रेस की भूमिका सुनिश्चित होगी और दोनों दलों के बीच बेहतर तालमेल कायम किया जा सकेगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सरकार में शामिल होने को लेकर अपनी मांगें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने रख दी हैं। अब पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जवाब का इंतजार कर रही है। दोनों दलों के बीच सहमति बनने के बाद ही यह तय होगा कि कांग्रेस उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल होगी या नहीं।

आस्था और विश्वास के साथ शुक्रवार का महत्व, परिवार, समाज और आत्मचिंतन से भी जुड़ा है यह दिन

डॉ. अवनीश कुमार
सह-प्रोफैसर, सोलन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतातल, कुमारहट्टी

सप्ताह के सात दिनों में शुक्रवार का अपना विशेष महत्व है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में लोग शुक्रवार को अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़कर देखते हैं। भारतीय समाज में शुक्रवार को विशेष रूप से धार्मिक आस्था, पूजा-पाठ और पारिवारिक सुख-समृद्धि से जोड़ा जाता है। वहीं इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए शुक्रवार यानी जुमा का दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है और बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार शुक्रवार केवल सप्ताह का एक सामान्य दिन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ दिन है।

हिंदू परंपराओं में शुक्रवार का संबंध मुख्य रूप से माता लक्ष्मी से माना जाता है। धन, समृद्धि, सुख और वैभव की देवी माता लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार को करने की परंपरा कई परिवारों में प्रचलित है। लोग अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं और पूजा-अर्चना के माध्यम से सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। कुछ लोग शुक्रवार को संतोषी माता और देवी के अन्य स्वरूपों की भी पूजा करते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। हालांकि धार्मिक मान्यताएं व्यक्तिगत आस्था का विषय हैं और इनके पालन का तरीका परिवार तथा क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

शुक्रवार का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में भी दिखाई देता है। सप्ताह के पांच कार्यदिवसों के बाद आने वाला शुक्रवार बहुत से लोगों के लिए सप्ताहांत की शुरुआत का संकेत होता है। नौकरी और व्यवसाय से जुड़े लोग इस दिन अपने सप्ताह के काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं और अगले दो दिनों के लिए योजनाएं बनाते हैं। कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए शुक्रवार अक्सर कामकाज के साथ-साथ आने वाले सप्ताहांत की तैयारी का दिन भी होता है। बाजारों और व्यापारिक क्षेत्रों में भी शुक्रवार को विशेष गतिविधियां देखने को मिलती हैं।

आधुनिक जीवन में शुक्रवार मनोरंजन और परिवार के साथ समय बिताने से भी जुड़ गया है। बहुत से लोग शुक्रवार की शाम को परिवार और मित्रों के साथ बाहर घूमने फिल्म देखने या भोजन करने की योजना बनाते हैं। मनोरंजन जगत में भी शुक्रवार का विशेष महत्व है क्योंकि भारत में लंबे समय से फिल्मों को शुक्रवार के दिन प्रदर्शित करने की परंपरा रही है। हालांकि अब फिल्मों और मनोरंजन की दुनिया में प्रदर्शन के तरीके बदल रहे हैं और डिजिटल मंचों के बढ़ते प्रभाव के कारण दर्शकों को पूरे सप्ताह नई सामग्री उपलब्ध होती है फिर भी शुक्रवार का आकर्षण कायम है।

इस्लाम धर्म में शुक्रवार को जुमा कहा जाता है और इसे सप्ताह का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन मस्जिदों में दोपहर के समय विशेष सामूहिक नमाज अदा की जाती है। नमाज से पहले इमाम द्वारा धार्मिक संदेश दिया जाता है जिसे खुतबा कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय के लिए यह दिन सामूहिक प्रार्थना के साथ-साथ आत्मचिंतन और सामाजिक एकता का अवसर भी प्रदान करता है। लोग एक-दूसरे से मिलते हैं और समाज में भाईचारे तथा सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं।

शुक्रवार हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन केवल काम और आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। मनुष्य के लिए अपने परिवार समाज और स्वयं के साथ समय बिताना भी आवश्यक है। लगातार व्यस्त जीवनशैली में कुछ समय रुककर अपने कार्यों की समीक्षा करना मानसिक शांति और संतुलन के लिए उपयोगी हो सकता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

बाल कैंसर की चुनौती से निपटने के लिए समय पर जांच, विशेषज्ञ उपचार और आर्थिक मदद जरूरी

प्रमोद कुमार हर्ष
कोठी, सरकाघाट, जिला मंडी

बाल कैंसर आज दुनिया के सामने स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर चुनौती है। बच्चों में होने वाला कैंसर केवल एक परिवार की परेशानी नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव पूरे परिवार की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। हालांकि चिकित्सा विज्ञान ने पिछले कुछ दशकों में कैंसर की पहचान और उपचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी बच्चों में कैंसर की समय पर पहचान, उचित उपचार और इलाज तक समान पहुंच सुनिश्चित करना अभी भी बड़ी चुनौती है। भारत जैसे विशाल देश में यह चुनौती और गंभीर हो जाती है, क्योंकि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले अनेक परिवारों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो पातीं। ऐसे में बाल कैंसर के खिलाफ केवल अस्पतालों और चिकित्सकों के स्तर पर प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि सरकार, स्वास्थ्य संस्थानों, विद्यालयों, सामाजिक संगठनों और आम जनता को मिलकर ठोस रणनीति बनानी होगी।

बच्चों में कैंसर के कई प्रकार हो सकते हैं। इनमें रक्त संबंधी कैंसर, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से जुड़े कैंसर तथा शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले अन्य कैंसर शामिल हैं। बच्चों में कैंसर के लक्षण कई बार सामान्य बीमारियों जैसे दिखाई दे सकते हैं। लगातार कमजोरी, असामान्य रूप से वजन कम होना, लंबे समय तक बुखार रहना, शरीर के किसी हिस्से में असामान्य गांठ या सूजन, बार-बार संक्रमण होना, लगातार सिरदर्द, उल्टी, हड्डियों में दर्द या त्वचा का असामान्य रूप से पीला पड़ना जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसे लक्षण हमेशा कैंसर के संकेत नहीं होते, लेकिन यदि वे लंबे समय तक बने रहें तो चिकित्सकीय जांच आवश्यक है। बीमारी की शुरुआती पहचान उपचार को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

बाल कैंसर के मामले में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जागरूकता की कमी है। कई परिवार कैंसर के शुरुआती संकेतों को सामान्य बीमारी समझकर इलाज में देरी कर देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुपलब्धता और आर्थिक कठिनाइयां भी इस देरी को बढ़ा सकती हैं। कुछ परिवारों में कैंसर को लेकर डर और सामाजिक भ्रांतियां भी मौजूद हैं। इन कारणों से बच्चे को सही चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने में समय लग जाता है। इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों को बच्चों में कैंसर के संभावित संकेतों की पहचान के लिए बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे संदिग्ध मामलों को समय रहते विशेषज्ञ केंद्रों तक भेजने की व्यवस्था मजबूत हो सकती है।

बाल कैंसर का इलाज लंबे समय तक चल सकता है और इसमें परिवार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका रहती है। दवाइयों, जांच, अस्पताल में भर्ती, आने-जाने और लंबे समय तक उपचार से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं का खर्च गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कठिन हो सकता है। कई बार परिवार के कमाने वाले सदस्य को बच्चे के इलाज के लिए काम छोड़ना पड़ता है। इससे परिवार की आय प्रभावित होती है और उपचार का खर्च और अधिक कठिन हो जाता है। सरकार को ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक सहायता की योजनाओं को सरल और प्रभावी बनाना चाहिए। सहायता का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए कागजी प्रक्रिया कम करने और डिजिटल तथा स्थानीय स्तर पर सहायता व्यवस्था मजबूत करने की आवश्यकता है। बाल कैंसर के उपचार के लिए केवल बड़े शहरों पर निर्भरता भी एक गंभीर समस्या है। देश के अनेक हिस्सों में विशेषज्ञ कैंसर अस्पताल और प्रशिक्षित बाल कैंसर विशेषज्ञ सीमित संख्या में हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संपादकीय

राष्ट्रगीत पर राजनीति क्यों?

हर राष्ट्र के कुछ ऐसे प्रतीक होते हैं, जो उसकी पहचान, इतिहास और सांस्कृतिक चेतना से गहराई से जुड़े होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राजचिह्न और राष्ट्रीय आदर्श वाक्य केवल औपचारिक प्रतीक नहीं होते, बल्कि वे देश की ऐतिहासिक यात्रा और सामूहिक स्मृति को अभिव्यक्त करते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इन प्रतीकों का महत्व और भी बढ़ जाता है। वंदे मातरम् भी ऐसा ही एक राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में लोगों के भीतर राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बावजूद आज यह गीत एक बार फिर राजनीतिक और वैचारिक विवाद के केंद्र में है।

वंदे मातरम् के वर्तमान विवाद को समझने के लिए उसके इतिहास को जानना जरूरी है। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस गीत को 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया था। उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अभी अपने शुरुआती दौर में था और देश को एकजुट करने के लिए ऐसे प्रतीकों की आवश्यकता थी, जो लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा कर सकें। बंग-भंग आंदोलन के दौरान 1905 में वंदे मातरम् जनआंदोलन का प्रमुख स्वर बन गया। उस समय विभिन्न समुदायों के लोगों ने इसे स्वतंत्रता और मातृभूमि के सम्मान के प्रतीक के रूप में अपनाया।

वंदे मातरम् का संबंध केवल किसी एक राजनीतिक संगठन या समुदाय से जोड़ना उसके इतिहास को सीमित करना होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक नेताओं और क्रांतिकारियों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत था। भगत सिंह के पत्रों में इसका उल्लेख मिलता है और अशफाक उल्ला खां जैसे क्रांतिकारी भी इससे जुड़े रहे। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में विदेश में फहराए गए अपने ध्वज पर वंदे मातरम् अंकित कराया था। ईसाई और पारसी समुदाय से जुड़े कई लोगों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसे स्वीकार किया। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय वंदे मातरम् को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावना के प्रतीक के रूप में देखा जाता था।

विवाद का एक प्रमुख आधार गीत के उन अंशों को लेकर है, जिनमें लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों का उल्लेख आता है। आलोचकों का तर्क है कि इन प्रतीकों के कारण गीत को सभी समुदायों के लिए स्वीकार करना कठिन हो सकता है। दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जाता है कि भारतीय परंपरा में देवी-देवताओं के प्रतीक केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं हैं। लक्ष्मी को समृद्धि, सरस्वती को ज्ञान और दुर्गा को शक्ति के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इस दृष्टि से वंदे मातरम् में इनका प्रयोग मातृभूमि के विभिन्न गुणों के प्रतीकात्मक चित्रण के रूप में समझा जा सकता है।

यही कारण है कि इस विवाद को केवल धार्मिक बहस के रूप में देखना उचित नहीं होगा। भारत की सांस्कृतिक परंपरा में अनेक प्रतीक समय के साथ व्यापक सामाजिक और राष्ट्रीय अर्थ ग्रहण करते रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद अशोक चक्र इसका उदाहरण है। यह भारतीय इतिहास और बौद्ध परंपरा से जुड़ा प्रतीक होते हुए भी आज पूरे देश की राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य भारतीय महाकाव्य परंपरा से लिया गया है। इसलिए किसी प्रतीक की ऐतिहासिक या सांस्कृतिक उत्पत्ति को देखते हुए उसके वर्तमान राष्ट्रीय महत्व को नकारना उचित नहीं माना जा सकता।

इस पूरे विवाद में राजनीतिक दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर मतभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव हैं, लेकिन ऐसे विषयों पर राजनीतिक लाभ के लिए समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित करने से बचना चाहिए। वंदे मातरम् का सम्मान करना किसी नागरिक की धार्मिक पहचान का प्रश्न नहीं होना चाहिए। इसी तरह किसी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए उसके विचारों को देशभक्ति या राष्ट्रविरोध की कसौटी पर रखना भी उचित नहीं है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ विविधताओं को मिटाना नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करते हुए साझा प्रतीकों के प्रति सम्मान विकसित करना है।

वंदे मातरम् का इतिहास यह भी बताता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय प्रतीकों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। जब देश अंग्रेजी शासन के अधीन था, तब ऐसे गीतों और नारों ने लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। उन्होंने लोगों को यह अहसास कराया कि भारत केवल भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि साझा इतिहास, संस्कृति और भावनाओं से बना राष्ट्र है। इसलिए आज की पीढ़ी के लिए आवश्यक है कि वह इन प्रतीकों को केवल राजनीतिक विवाद के चश्मे से न देखे बल्कि उनके ऐतिहासिक संदर्भ को भी समझे।

साथ ही सरकार और राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के नाम पर किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को अनावश्यक रूप से आहत न किया जाए। सम्मान और सहमति के बीच अंतर समझना जरूरी है। लोकतंत्र में किसी प्रतीक के बारे में अलग मत रखना संभव है, लेकिन राष्ट्रीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में उसके योगदान को नकारना उचित नहीं होगा।

-शिवांश धाकड़

कविता

पेड़ बचेंगे तो पहाड़ बचेंगे

(पूजा सूद), प्रिंसिपल बी एस सी नर्सिंग कॉलेज टांडा

पहाड़ों की गोद में पलता जीवन,
नदियों में बहता निर्मल जल,
जंगल हैं धरती का आभूषण,
इनसे ही सुंदर हर एक पल देवदार की छांव पुकारे,
मत काटो मेरा हरियाला तन,
इन वृक्षों में सांसें बसतीं,
इनसे ही रोशन है जीवन।
जहां पेड़ हैं, वहां बारिश है,
जहां बारिश, वहां जलधार,
खेतों में फिर हरियाली है,
खुशहाल रहे हर घर-परिवार।
कुल्हाड़ी जब जंगल काटे,
रोता है तब पूरा पहाड़,
सूखते जाते जल के स्रोत,
बढ़ता जाता संकट अपार।
गौरैया का घर मत उजाड़ो,
गिद्धों को भी जीने दो,
वन्य जीवों की इस धरती पर,
उनका भी अधिकार रहने दो।
औषधियों की धरती है यह,
जड़ी-बूटियों का भंडार,
इनको बचाना धर्म हमारा,
इनसे जुड़ा जन-जन का संसार।
विकास जरूरी, मगर ऐसा हो,
जिसमें प्रकृति न हो लाचार,
सड़क बने तो जंगल बचें,
बचा रहे पर्वत का श्रृंगार।

एक हाथ से राहत, दूसरे से वसूली पेट्रोल-डीजल उपकर पर बड़ा सवाल

तुलसी राम डोगरा
(स्वतंत्र लेखक),पालमपुर।

अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण से शायद ही कोई संवेदनशील नागरिक असहमत हो। समाज के इन वर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी भी है। असली सवाल मंशा पर नहीं, बल्कि तरीका और वित्तीय प्राथमिकताओं पर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर 'अनाथ एवं विधवा उपकर' लागू कर दिया है। यह उपकर 11 अगस्त की मध्यरात्रि से प्रभावी हुआ है और इससे प्राप्त राशि को अनाथ एवं विधवा कल्याण कोष में जमा करने की बात कही गई है। कल्याण के नाम पर जनता पर यह एक नया बोझ डालना क्या उचित है। सरकार के सामने राजस्व जुटाने की चुनौती हो सकती है, लेकिन हर कल्याणकारी योजना का पैसा आम जनता की जेब से निकालना कितना उचित है? पेट्रोल-डीजल केवल वाहन मालिकों की जरूरत नहीं है। इनके दाम बढ़ने का असर परिवहन, माल ढुलाई और अंततः रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ सकता है। 60 पैसे प्रति लीटर पहली नजर में बहुत छोटी राशि लग सकती है। लेकिन जब यही रकम लाखों लीटर ईंधन की बिक्री पर जुड़ती है तो सरकार के लिए यह राजस्व का स्रोत बन जाती है। दूसरी ओर उपभोक्ता के लिए यह एक और अतिरिक्त बोझ है।

यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि मार्च 2026 में विधानसभा ने सरकार को पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर अधिकतम5 प्रति लीटर तक ऐसा उपकर लगाने का अधिकार दिया था। फिलहाल सरकार ने 60 पैसे प्रति लीटर की दर तय की है। आज राजनीति में मुफ्त सुविधाओं और लोकलुभावन घोषणाओं को लेकर देशभर में बहस चल रही है। जनता को सुविधा देना गलत नहीं है, लेकिन सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उन सुविधाओं के लिए पैसा आएगा कहां से। यदि एक तरफ सरकार मुफ्त या रियायती सुविधाओं की घोषणा करे और दूसरी तरफ पेट्रोल-डीजल, बिजली, परिवहन अथवा अन्य माध्यमों से जनता पर लगातार नए शुल्क लगाए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि कल्याणकारी राज्य की कीमत आखिर कौन चुका रहा है?

जनता को यह मालूम होना चाहिए कि एक हाथ से राहत दी जा रही है और दूसरे हाथ से उससे कहीं अधिक राशि वापस वसूली जा रही है। ईंधन पर कर का प्रभाव केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। टैक्सी, बस, ट्रक और अन्य परिवहन सेवाओं की लागत में ईंधन महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में परिवहन की लागत का महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए सरकार को यह देखना होगा कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए राजस्व जुटाते समय उसका अप्रत्यक्ष असर गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारी और आम उपभोक्ता पर कितना पड़ रहा है।

सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा जुटाना नहीं, अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन इसके लिए केवल नया टैक्स लगाना ही एकमात्र रास्ता नहीं हो सकता। सरकार को अपने गैर-जरूरी खर्चों की समीक्षा, प्रशासनिक खर्चों में बचत, राजस्व संग्रह में सुधार, कर चोरी पर नियंत्रण और योजनाओं की प्राथमिकता तय करने, जैसे विकल्पों पर भी गंभीरता से काम करना चाहिए। यदि सरकार यह दावा करती है कि नया उपकर पूरी तरह अनाथों और विधवाओं के कल्याण पर खर्च होगा, तो इसके साथ पारदर्शिता और सामाजिक ऑडिट भी होना चाहिए। जनता को हर वर्ष बताया जाना चाहिए कि उपकर से कितनी राशि एकत्र हुई और उसमें से कितनी राशि वास्तव में लाभार्थियों तक पहुंची।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

राजनीति में सक्रिय रहीं प्रिया दत्त

प्रिया दत्त रोनकॉन
जन्म : 28 अगस्त 1966

प्रिया दत्त रोनकॉन भारतीय राजनीति और समाजसेवा से जुड़ी एक प्रमुख हस्ती हैं। उनका जन्म 28 अगस्त 1966 को मुंबई में हुआ था। वह प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता सुनील दत्त तथा मशहूर अभिनेत्री नरगिस दत्त की बेटी हैं। राजनीतिक और फिल्मी विरासत वाले परिवार में पली-बढ़ी प्रिया दत्त ने आगे चलकर राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके भाई अभिनेता संजय दत्त हैं, जबकि उनकी बहन नम्रता दत्त हैं। प्रिया दत्त का परिवार लंबे समय से सामाजिक कार्यों और सार्वजनिक जीवन से जुड़ा रहा है।

प्रिया दत्त ने मुंबई के सोफिया कॉलेज से समाजशास्त्र में कला स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित सेंटर फॉर मीडिया आर्ट्स से टेलीविजन निर्माण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सामाजिक कार्यों और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी शुरू की। अपने परिवार से मिले सामाजिक सरोकारों को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया।

प्रिया दत्त ने वर्ष 2005 में सक्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण कदम रखा। 22 नवंबर 2005 को हुए उपचुनाव में वह मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुईं। इसके बाद वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की और पंद्रहवीं लोकसभा की सदस्य बनीं।

सांसद के रूप में प्रिया दत्त ने सामाजिक और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया। उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ-साथ महिलाओं, बच्चों, युवाओं और जरूरतमंद वर्गों से जुड़े विषयों पर भी सक्रियता दिखाई। राजनीति के साथ समाजसेवा को महत्व देना उनकी सार्वजनिक पहचान का प्रमुख हिस्सा रहा है।

हालांकि वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पूनम महाजन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद प्रिया दत्त सार्वजनिक जीवन और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी रहीं।

हिमाचल के जंगलों पर बढ़ता संकट, अंधाधुंध कटान से जलस्रोत, वन्यजीव और पर्यावरण पर मंडरा रहा खतरा

बृज भूषण गांव हनोगी (456), डा. महोगी, त. औट (मंडी)

हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में जीवनदायिनी सदाबहार नदियों के स्रोत हैं, जो स्वच्छ जल के साथ-साथ अन्न उत्पादन के लिए सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता बनाए रखते हैं। हरे-भरे जंगल जैविक विविधता और सुंदर घाटियां हिमाचल की प्राकृतिक संपदा को चार चांद लगाती हैं। हिमाचल प्रदेश को ईश्वर ने प्रकृति के अपार सौंदर्य से सराबोर किया है। कहा जाता है कि प्रकृति हमारे जीवन की सहचरी है और इसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। जहां जंगल हैं वहां पानी है, जहां पानी है वहां खेती है और जहां खेती है वहां मानव जीवन पूर्ण रूप से निर्भर है। वास्तव में जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि मनुष्य, पशु-पक्षियों और समूचे पर्यावरण के जीवन का महत्वपूर्ण आधार हैं। यदि जंगल समाप्त होते गए तो इसका नुकसान केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि असंख्य जीव-जंतुओं को भी उठाना पड़ेगा।

पहाड़ों की पूरी जीविका ही वन-उपवन, उद्यान, खेती और पशुपालन पर आधारित है। यही हिमाचल के ग्रामीण जीवन की बुनियाद है। देवभूमि के चारों ओर फैले घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और हरियाली यहां रहने वाले लोगों के साथ-साथ वन्यजीवों और पक्षियों को भी जीवन का आश्रय प्रदान करते हैं। जंगलों में अनेक प्रकार के पेड़-पौधे, औषधीय वनस्पतियां और वन्य जीव पाए जाते हैं। प्रकृति ने हिमाचल को जो अनमोल और अद्भुत सौंदर्य दिया है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहना चाहिए। मगर वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति की दी हुई यह अनमोल सौगात धीरे-धीरे नष्ट होने के कगार पर पहुंच रही है।

इसका सबसे बड़ा कारण अंधाधुंध विकास और पहाड़ों का लगातार कटाव है। बड़े-बड़े पहाड़ों को आधुनिक मशीनों से काटकर सड़कों, भवनों और विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। पहाड़ों को काटने के साथ उनकी जड़ों में मौजूद हजारों पेड़ों का भी बलिदान हो जाता है। घने जंगलों में वन माफिया द्वारा चोरी-छिपे रात के समय हरे-भरे चंदन, देवदार, खैर और अन्य बेशकीमती पेड़ों को काटने की घटनाएं भी चिंता का विषय हैं। जंगलों में मौजूद औषधीय जड़ी-बूटियों का अवैध दोहन और वन्यजीवों का अवैध शिकार भी प्राकृतिक संपदा के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। यदि इस पर समय रहते प्रभावी रोक नहीं लगाई गई तो हिमाचल की प्राकृतिक विरासत को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

हिमाचल प्रदेश औषधीय पौधों की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध राज्य है। यहां अनेक ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में सदियों से होता आया है। दुर्भाग्य से वन माफिया और अवैध कारोबारी इन बहुमूल्य औषधीय पौधों को चोरी-छिपे जंगलों से निकालकर बाहर महंगे दामों पर बेचते हैं। हिमाचल के घने जंगल औषधीय और सुगंधित पौधों की प्रचुरता से भरे हुए हैं लेकिन इनके संरक्षण और वैज्ञानिक उपयोग के लिए जितनी गंभीरता की आवश्यकता है उतनी दिखाई नहीं देती। प्रदेश में औषधीय पौधों की खेती को बड़े व्यावसायिक स्तर पर बढ़ावा देने की पर्याप्त कोशिश अभी तक नहीं हो सकी है। जबकि इससे किसानों को अतिरिक्त आय मिल सकती है और जंगलों पर अवैध निर्भरता भी कम हो सकती है।

चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता का महत्व भारत में प्राचीन समय से रहा है। माना जाता है कि इसमें सैकड़ों औषधीय वनस्पतियों का उल्लेख मिलता है और इनमें से बड़ी संख्या ऐसी वनस्पतियों की है जो जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय परंपरा में वनस्पतियों को केवल प्राकृतिक संपदा नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा गया है। हिमाचल में उपलब्ध औषधीय वनस्पतियों का वैज्ञानिक अध्ययन, संरक्षण और नियंत्रित खेती रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर पैदा कर सकती है।

वनों की अंधाधुंध कटाई का प्रभाव केवल पेड़ों तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर मिट्टी, जलस्रोत, मौसम और जैव विविधता पर पड़ता है। जंगल कम होने से वर्षा के पानी को रोकने और जमीन में पहुंचाने की प्राकृतिक क्षमता कमजोर होती है। इसके परिणामस्वरूप भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और जलस्रोतों के सूखने जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधकर रखती हैं और पहाड़ों को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो ढलानों की मजबूती प्रभावित होती है और भारी बारिश के दौरान मलबा तथा मिट्टी तेजी से नीचे आने लगती है।

वनों के लगातार घटने का असर वन्यजीवों और पक्षियों पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में गौरैया जैसी पक्षी प्रजातियों की संख्या कम होना चिंता का विषय है। गिद्ध जैसे पक्षी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन उनकी संख्या भी कई क्षेत्रों में घटती गई है। यदि जंगलों और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए अनेक वन्यजीव और पक्षी केवल पुस्तकों और तस्वीरों तक सीमित हो सकते हैं। आधुनिक विकास के साथ दूरसंचार व्यवस्था का विस्तार भी जरूरी है लेकिन इसके लिए पर्यावरणीय प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

न्यूज ब्रीफ

बलिया में एमडीएम घोटाले का खुलासा, 14 लाख की होगी वसूली

एजेंसी, बलिया। बलिया के बांसडीह ब्लाक स्थित इंटर कॉलेज ताजपुर मुड़ियारी में मिड-डे-मील योजना में करीब 14 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 के दौरान बिना भोजन वितरण किए सरकारी धनराशि के भुगतान का मामला जांच में सामने आया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधानाचार्य चंद्रशेखर पांडेय और जिला समन्वयक एमडीएम अजीत पाठक को जिम्मेदार माना है। डीएम ने दोनों से पूरी राशि की वसूली करने और संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि बच्चों ने इस संबंध में जिलाधिकारी को गोपनीय चिट्ठी भेजी थी, जिसके बाद मामले की जांच कराई गई। सरकारी योजना में गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

केस्को पीडी घोटाले में छह अधिकारियों पर कार्रवाई

एजेंसी, कानपुर। कानपुर में केस्को के स्थायी रूप से बिजली कनेक्शन काटने की प्रक्रिया में कथित घोटाले की जांच तेज हो गई है। अनियमितताएं मिलने के बाद तत्कालीन अधिशासी अभियंता मनीष निषाद समेत छह अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोपपत्र जारी किया गया है। जांच में सामने आया कि कई बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटते समय नियमों की अनदेखी कर बिलों में संशोधन किया गया और मामूली रकम जमा कराकर पीडी कर दी गई। एक मामले में 56.75 लाख रुपये की बकायेदारी घटाकर 16.27 लाख रुपये की गई और केवल 5290 रुपये जमा कराए गए। मामले की विस्तृत जांच अधीक्षक अभियंता प्रमोद कुमार सिंह को सौंपी गई है। अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मिला है। विशेष लेखा जांच में और मामले सामने आने की संभावना है।

मेरठ में कूड़े से गैस बनाने की योजना को मिलेगी नई रफ्तार

एजेंसी, मेरठ। मेरठ में कूड़े से गैस बनाने की योजना को अब नई कंपनी के जरिए आगे बढ़ाने की तैयारी है। गांवड़ी में प्लांट स्थापित करने के लिए नगर निगम और एनटीपीसी के बीच सितंबर 2024 में करार हुआ था और अक्टूबर में भूमि पूजन भी किया गया था। इसके बावजूद दो साल में काम धरातल पर नहीं उतर सका। अब नगर निगम ने एनटीपीसी का अनुबंध समाप्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। साथ ही गेल और आईजीएल के प्रस्ताव भी लखनऊ भेजे गए हैं। आईजीएल ने प्लांट के लिए मिट्टी की जांच कराकर लेआउट भी नगर निगम में जमा किया है। शासन से जल्द निर्णय आने की उम्मीद है।

गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़ के बाद 50 हजार का इनामी बदमाश गुड्डू ढाढ़ी गिरफ्तार

एजेंसी, गोरखपुर। गोरखपुर में पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश गुड्डू ढाढ़ी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार सुबह सहजनवा-पीपीगंज सीमा पर सिसई घाट के पास पुलिस टीम को उसके मौजूद होने की सूचना मिली थी। घेराबंदी के दौरान आरोपित ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार गुड्डू ढाढ़ी के खिलाफ गोरखपुर समेत अन्य जिलों के थानों में करीब 45 मुकदमे दर्ज हैं। वह लूट के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था।

मीरजापुर में पांच भाइयों ने एक साथ पास की यूपीटीईटी, गांव में बंटी मिठाई

एजेंसी, मीरजापुर। मीरजापुर के हलिया क्षेत्र के देवघटा पांडेय गांव के बेमौरी मजरे में पांच भाइयों की एक साथ सफलता से खुशी का माहौल है। यूपीटीईटी 2026 के परिणाम में एक ही परिवार के पांच भाइयों ने उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। रामसागर के बेटे महेंद्र कुमार पांडेय, जितेंद्र पांडेय और रोहित कुमार पांडेय ने प्रयागराज के राजकीय डिग्री कॉलेज से बीएड किया, जबकि संदीप कुमार पांडेय और राजेश कुमार पांडेय ने मवई कला के पंचशील डिग्री कॉलेज से बीएड की पढ़ाई पूरी की। पांचों ने ईडब्ल्यूएस वर्ग से सफलता हासिल की। रोहित ने 120.99, जितेंद्र ने 113.89, महेंद्र ने 106.69, संदीप ने 97.94 और राजेश ने 92.43 अंक प्राप्त किए। सफलता के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी।

उप्र की नगरीय बसों में 29 अगस्त की रात तक महिलाओं को नहीं देना होगा किराया

एजेंसी, लखनऊ। रक्षाबंधन के अवसर पर नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत संचालित नगरीय परिवहन की बसों में महिलाओं एवं उनके साथ यात्रा करने वाले एक सहयात्री के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। यह सुविधा 27 अगस्त 2026 को प्रातः 6 बजे से 29 अगस्त 2026 की रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगी। यह घोषणा प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए. के. शर्मा की ओर से की गई है। उन्होंने गुरुवार को जारी अपने बयान में कहा कि निर्धारित अवधि में नगरीय बसों से यात्रा करने वाली महिलाओं और उनके साथ यात्रा करने वाले एक सहयात्री से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। इससे रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए मायके जाने वाली बहनों को यात्रा खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वे सहजता एवं सम्मान के साथ अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगी। शासन के निर्णय के अनुसार, 27 अगस्त को सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक नगरीय परिवहन की बसों में महिलाओं एवं उनके साथ यात्रा करने वाले एक सहयात्री को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी।

बीबीएयू के दीक्षा समारोह में 22 मेधावियों को गोल्ड मेडल देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

चार वर्षों के 508 मेधावी पाएंगे स्वर्ण पदक, राजनाथ सिंह करेंगे 22 को सम्मानित

एजेंसी, लखनऊ

लखनऊ स्थित बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षा समारोह का आयोजन 29 अगस्त को किया जाएगा। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और प्रभा चंद्रा समेत 22 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने समारोह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का सम्मानित करने के साथ उन्हें अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश और समाज के विकास में करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने बताया कि चार वर्षों के 508 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाना है।

लखनऊ में 29 अगस्त को होगा बीबीएयू का दीक्षा समारोह।

हालांकि इस समारोह में 22 मेधावियों को ही रक्षा मंत्री के हाथों सम्मानित किया जाएगा। इनमें स्नातक और परास्नातक स्तर के 17 विद्यार्थी, एक डीएसएसी तथा आरडी सोनकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चार विद्यार्थी शामिल हैं। अन्य मेधावियों को दूसरे चरण में सम्मान और उपाधियां प्रदान की जाएंगी।

दीक्षा समारोह में वर्ष 2023, 2024, 2025 और 2026 के विभिन्न पाठ्यक्रमों के कुल 8551 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इनमें 4832 पुरुष और 3719 महिला विद्यार्थी शामिल हैं। वर्षवार आंकड़ों के अनुसार 2023 में 2139, 2024 में 2115, 2025 में 2237 और 2026 में 2041 विद्यार्थियों को उपाधियां मिलेंगी। इसके अलावा पिछली अवधि के 19 विद्यार्थियों को भी उपाधि प्रदान की जाएगी।

पाठ्यक्रमवार विद्यार्थियों की बात करें तो 2771 स्नातक, 228 स्नातक बहु-प्रवेश एवं बहु-निर्गमन व्यवस्था वाले पाठ्यक्रमों, 4662 परास्नातक, 412 पीएचडी, 142 एकीकृत पाठ्यक्रम, 23 प्रमाणपत्र, 198 डिप्लोमा, 102 स्नातकोत्तर डिप्लोमा और 13 एमफिल विद्यार्थी शामिल हैं। सबसे अधिक 4662 उपाधियां परास्नातक विद्यार्थियों को दी जाएंगी।

बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की मौजूदगी को देखते हुए उपाधि वितरण कार्यक्रम को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में होगा। दूसरे चरण में दोपहर दो बजे से विद्यार्थियों को उनके संबंधित विभागों में उपाधियां प्रदान की जाएंगी। विश्वविद्यालय ने दीक्षा समारोह के लिए विद्यार्थियों के लिए विशेष परिधान भी निर्धारित किया है।

कानपुर से सीधे जुड़ेगा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, छह किलोमीटर दूरी होगी खत्म

एजेंसी, कानपुर

कानपुर शहर को लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ने की प्रक्रिया अब आगे बढ़ने लगी है। शहर की सीमा से करीब छह किलोमीटर दूर होने के कारण एक्सप्रेसवे का अपेक्षित लाभ कानपुरवासियों को नहीं मिल पा रहा था। लंबे समय से शहर को एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी देने की मांग की जा रही थी। अब इस दिशा में जल्द जमीनी सर्वे शुरू होने की उम्मीद है। सांसद रमेश अवस्थी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर यह मांग उठाई थी। उन्होंने बताया कि एक्सप्रेसवे शहर के बेहद करीब होने के बावजूद सीधा जुड़ाव नहीं होने से वाहन चालकों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है।

मंत्रालय के निर्देश के बाद संबंधित अधिकारियों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को संभावित मार्गों की जमीनी पड़ताल की जिम्मेदारी दी गई है। सर्वे के दौरान जमीन की उपलब्धता, मौजूदा सड़कों, यातायात दबाव और तकनीकी जरूरतों का अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होगी। रिपोर्ट में एक्सप्रेसवे को कानपुर शहर से जोड़ने के लिए सबसे व्यवहारिक मार्ग का चयन किया जाएगा।

सीधी कनेक्टिविटी बनने से कानपुर से लखनऊ की ओर आने-जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। शहर से एक्सप्रेसवे तक पहुंच आसान होने के साथ यात्रा का समय और दूरी भी कम हो सकती है। हालांकि अंतिम मार्ग और निर्माण की रूपरेखा सर्वे तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी।

जालसाजी पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, दो पावर प्रोजेक्ट्स की जमीन वापस

एजेंसी, कानपुर

उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर देहात में दो निजी कंपनियों को थर्मल पावर परियोजनाओं के लिए आवंटित करीब 944 हेक्टेयर भूमि का आवंटन रद कर दिया है। सरकार ने यह कार्रवाई परियोजनाओं को लंबे समय तक शुरू नहीं करने और आवंटित भूमि के कथित गलत इस्तेमाल के मामले में की है। लैंको अनपारा पावर लिमिटेड और हिमावत पावर प्राइवेट लिमिटेड को भोगनीपुर तहसील क्षेत्र में बिजली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित की गई थी। दोनों कंपनियों को परियोजनाओं के लिए पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद करीब 15 वर्ष बाद भी मौके पर काम शुरू नहीं हो सका।

सरकार के अनुसार दोनों कंपनियों ने आवंटित भूमि पर परियोजना स्थापित करने के बजाय उसे बैंकों में गिरवी रखकर ऋण लिया। बताया गया है कि इसके लिए आवश्यक अनुमति भी नहीं ली गई थी। लंबे समय तक परियोजनाओं में कोई ठोस प्रगति नहीं होने और सरकारी स्तर से जारी नोटिसों

की अनदेखी के बाद सरकार ने भूमि आवंटन निरस्त करने का फैसला लिया।

अब सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दोनों कंपनियों से भूमि वापस लेकर उसे राज्य के ऊर्जा विभाग के नाम दर्ज कराया जाए। इस कार्रवाई को सरकारी भूमि के संरक्षण और विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार की सख्ती से यह स्पष्ट संकेत गया है कि परियोजनाओं के नाम पर भूमि हासिल कर वर्षों तक उसका उपयोग नहीं करने या निर्धारित उद्देश्य से अलग इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही भविष्य में ऐसे मामलों में समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने की आवश्यकता भी सामने आई है।

प्रयागराज में गोबर और गीले कूड़े से बनेगी बिजली

एजेंसी, प्रयागराज। प्रयागराज में गीले कूड़े के बेहतर निस्तारण और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम नई पहल करने जा रहा है। शहर के झूंसी और फाफामऊ क्षेत्र में दो बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन प्लांटों में गोबर और गीले कूड़े का उपयोग कर बिजली तैयार की जाएगी। तैयार होने वाली बिजली का इस्तेमाल नगर निगम की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग में किया जा सकेगा। इससे एक ओर कूड़े के निस्तारण की समस्या कम होगी तो दूसरी ओर वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। नगर निगम के अनुसार दोनों प्लांट स्थापित करने में करीब छह करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। दोनों संयंत्रों की कुल क्षमता प्रतिदिन 100 मीट्रिक टन गीले कूड़े के निस्तारण की होगी। इससे लगभग 100 किलोवाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्लांट में गीले कूड़े और गोबर का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया जाएगा। नगर निगम की योजना से शहर में कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही गीले कूड़े को खुले में फेंकने या अन्य तरीकों से निस्तारित करने की आवश्यकता कम होगी। अधिकारियों के अनुसार करीब एक माह बाद दोनों स्थानों पर जमीन का चिह्नांकन किया जाएगा। इसके बाद प्लांट स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। यह परियोजना प्रयागराज में स्वच्छता के साथ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

नेपाल की बाढ़ से गंडक में बढ़ा पानी महराजगंज-कुशीनगर में हाई अलर्ट

एजेंसी, लखनऊ

त्रिशूली से नारायणी तक असर; सीमावर्ती गांवों में बढ़ाई गई निगरानी।

नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ का असर अब भारतीय क्षेत्र में दिखाई देने लगा है। भोटेकोशी नदी का बढ़ा हुआ पानी त्रिशूली नदी के रास्ते नारायणी यानी गंडक नदी में पहुंच रहा है। इसके कारण नारायणी नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। स्थिति को देखते हुए वाल्मीकि बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं, ताकि बढ़ते जलप्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। अनुमान है कि देर रात तक नदी में पानी का प्रवाह ढाई लाख से तीन लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है।

नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद भारतीय प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। महराजगंज और कुशीनगर जिलों के नदी किनारे बसे गांवों में निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारी संभावित स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नदी के जलस्तर में अधिक वृद्धि होने पर तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। करीब 40 किलोमीटर लंबे भारतीय क्षेत्र में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर का प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है।

प्रशासन की ओर से राहत और बचाव की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी गई हैं। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के साथ अधिकारियों को स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीणों को भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।

जौनपुर दीवानी अधिवक्ता संघ चुनाव में 76 नामांकन, 11 सितंबर को मतदान

अधिवक्ता संघ चुनाव में 76 प्रत्याशी मैदान में, 12 सितंबर को मतगणना

एजेंसी, जौनपुर

जौनपुर दीवानी अधिवक्ता संघ चुनाव 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अध्यक्ष और मंत्री समेत कुल 15 पदों के लिए 76 अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किया है। चुनाव अधिकारी राजीव कुमार गुप्त और गौरी शंकर मिश्र ने चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि मतदान 11 सितंबर को कराया जाएगा। इसके बाद 12 सितंबर को मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के बीच सक्रियता बढ़ गई है और विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ संपर्क अभियान तेज कर दिया है।

चुनाव अधिकारियों के अनुसार नामांकन प्रक्रिया दो दिनों तक चली। पहले दिन कुल 57 अधिवक्ताओं ने अलग-अलग पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। दूसरे दिन 19 अधिवक्ताओं ने पर्चे भरे। इस प्रकार दोनों दिनों में कुल 76 अधिवक्ताओं ने चुनाव मैदान में उतरने के लिए अपना नामांकन कराया। अब चुनाव प्रक्रिया का अगला चरण मतदान होगा।

चुनाव अधिकारियों ने बताया कि मतदान 11 सितंबर को सुबह नौ बजे शुरू होगा और शाम पांच बजे तक चलेगा। मतदान के दौरान एक घंटे का मध्यावकाश निर्धारित किया गया है। मतदान में हिस्सा लेने वाले सभी अधिवक्ताओं के लिए पहचान संबंधी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य किया गया है।

अध्यक्ष और मंत्री समेत 15 पदों पर चुनावी मुकाबला

चुनाव अधिकारियों ने सभी प्रत्याशियों, उनके समर्थकों और मतदाताओं से चुनाव के दौरान अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान और मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान या अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी से सहयोग करने को कहा गया है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिवक्ता संघ को नई कार्यकारिणी मिलेगी।

मेरठ की शिक्षिका शीतल देवल को मिलेगा देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान

एजेंसी, मेरठ। मेरठ के राजकीय हाईस्कूल कुढला की शिक्षिका शीतल देवल ने शिक्षा के क्षेत्र में जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उन्हें शिव नाडर प्रतिष्ठान भारत और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सैद प्रबंध विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार के लिए भौतिक विज्ञान विषय में चुना गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर पांच सितंबर को उन्हें सम्मानित किया जाएगा। शीतल देवल पिछले कई वर्षों से विद्यार्थियों को विज्ञान विषय को सरल और प्रयोगात्मक तरीके से समझाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने प्रकाश की प्रमुख घटनाओं को एक ही मंच पर प्रत्यक्ष रूप से समझाने वाला अनोखा उपकरण तैयार किया है।

गोरखपुर गुरुकुल पहुंचे वायुसेना प्रमुख, छात्रों को दिए सफलता के मंत्र

बोल, लक्ष्य से पहले सही दिशा चुनना जरूरी

एजेंसी, गोरखपुर

गोरखपुर के माथाबारी गांव स्थित सरस्वती गुरुकुल में गुरुवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह पहुंचे और विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को जीवन में सफलता हासिल करने के साथ सही दिशा चुनने और अच्छे संस्कार अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि दिशा गलत हो तो व्यक्ति कितना भी तेज दौड़े वह मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जीवन में लक्ष्य तय करने से पहले सही रास्ते का चुनाव करना बेहद जरूरी है।

वायुसेना प्रमुख ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन में गिरना कोई गलत बात नहीं है बल्कि गिरने के बाद उठकर दोबारा प्रयास करना ही सफलता की असली पहचान है। उन्होंने बच्चों को मेहनत और निरंतर प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज उनके सामने देश का भविष्य बैठा है। आने वाले समय में विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा कि कोई विद्यार्थी सेना में जाना चाहता है तो कोई नौसेना या वायुसेना में अपना भविष्य बना सकता है। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य क्षेत्रों में भी करियर बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन किसी भी उपलब्धि से पहले एक अच्छा इंसान बनना सबसे जरूरी है।

विकास | यूपी स्टार्टअप नीति 2026 से युवाओं को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन, योगी ने 107 स्टार्टअप को बांटे 3.42 करोड़ रुपए

योगी बोले- युवाओं के सपनों को उड़ान दे रही सरकार

एजेंसी, लखनऊ

लखनऊ में लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 की पुस्तिका का विमोचन किया और स्टार्टअप मिशन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 107 स्टार्टअप को 3.42 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की तथा सात स्टार्टअप संचालित करने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद उद्योग और स्टार्टअप के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। सरकार की नीतियों और प्रोत्साहन से युवाओं को अपने विचारों को व्यवसाय में बदलने के अवसर मिल रहे हैं और प्रदेश की नई पहचान तैयार हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को देश के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में आबादी के अनुपात के अनुसार 20 प्रतिशत हिस्सेदारी

हासिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने युवाओं और स्टार्टअप संचालकों को भरोसा दिलाया कि उनके हित में उठाए जाने वाले हर कदम में सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूमि और संसाधनों की कमी नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में संभावनाएं मौजूद हैं, जरूरत केवल अवसरों को पहचानकर उनका सही इस्तेमाल करने की है। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को ऐसा वातावरण मिले जहां वे जोखिम लेकर नए विचारों और तकनीकों पर काम कर सकें।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत में स्टार्टअप की संख्या बेहद सीमित थी, लेकिन अब देश में 2.5 लाख से अधिक स्टार्टअप हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी पिछले वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या बहुत कम थी, जबकि अब यह आंकड़ा 24 हजार से अधिक हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश में बदलते कारोबारी वातावरण और युवाओं के बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत बताया। उनके अनुसार नई नीतियों का उद्देश्य स्टार्टअप को केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर मार्गदर्शन, निवेश, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराने वाला मजबूत तंत्र तैयार करना है।

नई नीति के साथ मिशन पोर्टल शुरू

मुख्यमंत्री ने महिला उद्यमिता को भी प्रदेश के स्टार्टअप क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 24 हजार से अधिक स्टार्टअप में करीब आधे का संचालन महिलाएं कर रही हैं। यह बदलाव बताता है कि राज्य की युवा महिलाएं भी रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सरकार की कोशिश है कि महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं। स्टार्टअप को आर्थिक सहयोग देने की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने वित्तीय संस्थानों के सहयोग से स्टार्टअप के लिए पूंजी और सहायता का रास्ता तैयार किया है। नई नीति में पहले की तुलना में अधिक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि स्टार्टअप के लिए निर्धारित प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया गया है। इससे शुरुआती चरण में काम कर रहे उद्यमियों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने भी स्टार्टअप और रोजगार के क्षेत्र में सरकार की नीतियों का उल्लेख किया। नए इनक्यूबेटरों को संचालित करने के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट भी जारी किए गए।

एसपी कार्यालय पहुंचे सिपाही ने उठाया खौफनाक कदम

कानपुर देहात में एसपी कार्यालय की छत से सिपाही ने लगाई छलांग, हालत गंभीर

एजेंसी, कानपुर

कानपुर देहात में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब सिपाही अंकित देशवाल ने कार्यालय की छत से छलांग लगा दी। ऊंचाई से गिरने के कारण सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक सिपाही अंकित देशवाल सुबह अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा था। इसी दौरान वह कार्यालय की छत पर गया और अचानक छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि हाल ही में उसकी तैनाती पुलिस लाइन में की गई थी। हालांकि उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पाण्डे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के पीछे की वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल घायल सिपाही का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है।

सपा को 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से झटक देगी : केशव प्रसाद मौर्य

एजेंसी, लखनऊ

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी को 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से झटक देगी। उप मुख्यमंत्री ने गुरूवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव, राजद के लालटेन तेजस्वी यादव, तृणमूल दीदी ममता बनर्जी और आप नेता अरविंद केजरीवाल, इन सबके चेहरे अलग-अलग लेकिन इनकी ढपोरशंखी घोषणाएं और खोखली राजनीति का खालिस चरित्र एक है। बिहार ने राजद, पश्चिम बंगाल ने तृणमूल कांग्रेस और दिल्ली ने आप को नकार दिया। अगला नंबर सपा का है, जिसे 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से झटक देगी। यूपी ने 2012-17 के दरम्यान सपा की गुंडागर्दी, अपराध, माफिया, दंगाइयों और भ्रष्टाचारियों के संरक्षण वाली राजनीति न केवल देखी है, बल्कि काफी हद तक सही भी है। यह क़तई साफ है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को 2027 से 2047 तक यूपी की सत्ता और उनके दिल्ली वाले गार्जियन कांग्रेस के जेन-जी नेता राहुल गांधी को 2049 तक देश की सत्ता मिलने वाली नहीं है।

चार साल की सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए हरियाणा में सरकारी भर्तियों की तैयारी तेज

सरकार ने विभागों से मांगा आरक्षित पदों का ब्यौरा, संभावित भर्ती महीना भी बताने के निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के पहले बैच की चार साल की सैन्य सेवा पूरी होने के मद्देनजर उनके लिए सरकारी रोजगार की तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों और निगमों से पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित सीधी भर्ती के पदों का वास्तविक ब्यौरा मांगा है। सामान्य प्रशासन विभाग की मानव संसाधन-2 शाखा ने 25 अगस्त को आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों से 26 अगस्त दोपहर तीन बजे तक निर्धारित प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था।

सरकार इस कवायद के जरिए यह पता लगाएगी कि पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने पद आरक्षित हैं, ये पद किन विभागों में उपलब्ध हैं और इन पर भर्ती कब कराई जा सकती है। विभागों को केवल रिक्त पदों की संख्या बताने के बजाय पद का नाम, आरक्षण प्रतिशत, संभावित रिक्तियों की संख्या, श्रेणीवार विवरण और भर्ती का प्रस्तावित महीना भी बताना होगा। इसके साथ ही सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग समेत विभिन्न श्रेणियों के अनुसार भी रिक्तियों का ब्योरा मांगा गया है।

हरियाणा के 1,373 युवा पहले बैच में : अग्निपथ योजना के तहत हरियाणा से अब तक 7,228 युवा अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती हुए हैं। इनमें वर्ष 2022-23 में 2,227, वर्ष 2023-24 में 2,893 और वर्ष 2024-25 में 2,108 युवा शामिल हैं। योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी होने के बाद अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सैन्य सेवा में बनाए रखने का प्रावधान है। शेष अग्निवीरों को सेवा पूरी होने के बाद बाहर आना होता है।

देश में अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 से चार साल की सेवा पूरी करने के बाद बाहर होना शुरू हुआ है। हरियाणा के करीब 1,373 युवा इस पहले बैच में शामिल हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से आरक्षित पदों का ब्योरा जुटाने की प्रक्रिया इन युवाओं के सैन्य सेवा के बाद रोजगार की तैयारियों से सीधे जुड़ी मानी जा रही है।

आयोगों के जरिए होने वाली भर्तियों पर भी नजर : सरकारी आदेश में खासतौर पर उन पदों की जानकारी मांगी गई है, जिन पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जानी है। विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आगामी सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण लागू करने की स्थिति स्पष्ट होगी।

वंदेमातरम् के दौरान कांग्रेस विधायक गैरहाजिर, हरियाणा विधानसभा में छिड़ा सियासी विवाद

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत शुक्रवार को राष्ट्रगीत वंदेमातरम् के साथ हुई, लेकिन राष्ट्रगीत के दौरान कांग्रेस विधायकों की गैरमौजूदगी को लेकर सदन में सियासी विवाद खड़ा हो गया। राष्ट्रगीत बजने के समय कांग्रेस विधायक विधानसभा सदन में मौजूद नहीं थे और गीत समाप्त होने के बाद सदन में पहुंचे। इस दौरान भाजपा विधायक, अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया प्रतिनिधि और अतिथि राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े रहे।

कांग्रेस विधायकों के राष्ट्रगीत के समय सदन में मौजूद नहीं रहने पर भाजपा ने सवाल उठाते हुए इसे गंभीर विषय बताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि राष्ट्रगीत किसी राजनीतिक दल या सरकार का नहीं, बल्कि देश का सम्मान है। ऐसे में विधानसभा जैसे संवैधानिक संस्थान में इसके दौरान सभी सदस्यों की मौजूदगी अपेक्षित है।

हुड्डा पहले ही साध चुके हैं निशाना: यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रवाद को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक मतभेद लगातार देखने को मिलते रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही भाजपा पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा था कि भाजपा को कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

भाजपा अब कांग्रेस विधायकों की गैरमौजूदगी को इसी राजनीतिक बयानबाजी से जोड़कर देख रही है। पार्टी का कहना है कि राष्ट्रगीत के सम्मान में किसी प्रकार की राजनीतिक दूरी नहीं होनी चाहिए।

वंदेमातरम् पर लंबे समय से वैचारिक मतभेद : वंदेमातरम् को लेकर देश में कांग्रेस और भाजपा के बीच लंबे समय से वैचारिक मतभेद रहे हैं। भाजपा इसे राष्ट्रीय गौरव, स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और देशभक्ति की भावना का प्रतीक मानती है।

न्यूज ब्रीफ

गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर शिकंजा, 1319 नोटिस और 662 संपत्तियों पर रेस्टोरेशन आदेश जारी

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम। शहर की लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में अवैध निर्माण और जमीन के गलत इस्तेमाल के खिलाफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग अब तक 1319 कारण बताओ नोटिस और 662 रेस्टोरेशन आदेश जारी कर चुका है। कई इलाकों में अवैध निर्माण हटाने के साथ नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों को सील भी किया जा रहा है। विभाग की जांच डीएलएफ के साथ सुशांत लोक, साउथ सिटी, आरडी सिटी, ग्रीनवुड सिटी, वाटिका, द वेस्टरलीज और विपुल वर्ल्ड जैसी कॉलोनियों तक पहुंच गई है। सबसे अधिक 538 कारण बताओ नोटिस साउथ सिटी में जारी हुए हैं। इनमें 230 व्यावसायिक व आवासीय नियमों के उल्लंघन और 308 आवासीय उल्लंघनों से जुड़े हैं। सुशांत लोक में 283 नोटिस जारी किए गए हैं। विपुल वर्ल्ड में 145, ग्रीनवुड सिटी में 99 और आरडी सिटी में 86 नोटिस दिए गए हैं। इसके अलावा वाटिका में 44 और द वेस्टरलीज में 24 नोटिस जारी हुए हैं। विभाग ने 662 संपत्तियों को स्वीकृत नक्शे और नियमों के अनुरूप मूल स्थिति में लाने के आदेश दिए हैं। इनमें सुशांत लोक-1 में 250 और डीएलएफ फेज-3 में 248 रेस्टोरेशन आदेश शामिल हैं। डीएलएफ फेज-4 में 126 और फेज-2 में 38 आदेश जारी किए गए हैं।

फूलां गांव में पूर्व सरपंच सहित कई कांग्रेस समर्थक भाजपा में हुए शामिल

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद। गांव फूलां में भारतीय जनता पार्टी को उस समय मजबूती मिली, जब कांग्रेस से जुड़े पूर्व सरपंच जगदीश थालौड़ ने अपने समर्थकों और परिवार के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश महामंत्री वेद फूलां ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि उनके शामिल होने से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। भाजपा में शामिल होने वालों में सरपंच सुशील कुमार, अमर सिंह थालौड़, सतवीर थालौड़, पिंटू थालौड़, सुल्तान थालौड़, मानसिंह सिहाग, गुरजीत थालौड़, कुलदीप जेवलिया, रामकुमार बटेशर, सुशील मैहला और राजेश मैहला शामिल हैं। सभी ने भाजपा की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों में विश्वास जताया। वेद फूलां ने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ कार्य करने वाला विशाल परिवार है। जिला मीडिया प्रभारी कंवल चौधरी ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने नए सदस्यों से संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

सज्जन कुमार मुद्दे पर विधानसभा में कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। 1984 के सिख दंगों के दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को रोल मॉडल बताए जाने के आरोप को लेकर हरियाणा विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाया, जबकि हुड्डा पहले ही आरोप को खारिज कर चुके हैं। मामला तब गरमा गया, जब रतिया विधायक सरदार जरनैल सिंह हाथ में पर्चा लेकर सदन में खड़े हो गए। पर्चे में 1984 के दंगों के दोषी को रोल मॉडल बताने वालों के खिलाफ कार्रवाई और माफी की मांग की गई थी। कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने उनके हाथ से पर्चा छीन लिया, जिसके बाद भाजपा विधायकों ने विरोध जताया। हंगामे के दौरान कांग्रेस विधायकों द्वारा सदन में वीडियो बनाने पर स्पीकर हरविन्द्र कल्याण ने उन्हें चेतावनी दी। दोनों पक्षों में नारेबाजी भी हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर 1984 के सिख दंगों को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर की घटनाओं से लोगों के घाव आज भी ताजा हैं। उन्होंने कांग्रेस पर पीड़ितों से माफी नहीं मांगने का आरोप लगाया। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सदन में नियमों के अनुसार पोस्टर दिखाने की अनुमति नहीं है और स्पीकर को निष्पक्ष रहना चाहिए।

गन्ने की घटती खेती से बढ़ी चीनी की चिंता, महंगे दामों ने बिगाड़ा घरेलू बजट

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत

प्रदेश में चीनी के लगातार बढ़ते दाम के बीच गन्ने का घटता रकबा भी चिंता का कारण बन रहा है। बढ़ती लागत, अपेक्षाकृत कम भाव, मजदूरों की कमी और दूसरी फसलों से अधिक आय के चलते किसानों का गन्ने की खेती से मोहभंग होता जा रहा है। इसका असर चीनी मिलों को मिलने वाले गन्ने की उपलब्धता पर पड़ रहा है।

'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में प्रदेश में 29,188 किसानों ने 1,42,193 एकड़ में गन्ने की खेती की थी। वर्ष 2025 में किसानों की संख्या घटकर 29,062 रह गई, लेकिन रकबा बढ़कर 1,63,287 एकड़ हो गया। इस वर्ष 28,663 किसानों ने 1,62,534 एकड़ में गन्ना उगाया है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस बार किसानों की संख्या और गन्ने का रकबा दोनों में कमी आई है।

प्रदेश में शाहबाद, डाहर, नारायणगढ़, यमुनानगर, सोनीपत, गोहाना, भाली, महम, पलवल, करनाल, असंध, भादसों, जींद और कैथल समेत कई स्थानों पर चीनी मिलें संचालित हैं। इन मिलों के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ने की उपलब्धता जरूरी है। यदि किसान लगातार गन्ने से दूरी बनाते हैं तो आने वाले समय में मिलों के सामने कच्चे माल की कमी की समस्या बढ़ सकती है। सरकार गन्ने का रकबा और पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है।

हरियाणा में 78 शिक्षकों को मिलेगा राज्य शिक्षक सम्मान

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने लंबे समय से लंबित राज्य शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। वर्ष 2024 और 2025 के लिए कुल 78 शिक्षकों का चयन किया गया है। इनमें वर्ष 2024 के लिए 40 और वर्ष 2025 के लिए 38 शिक्षक शामिल हैं। इस घोषणा के साथ दो साल से पुरस्कार का इंतजार कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। चयनित शिक्षकों में 20 महिला शिक्षक भी शामिल हैं। वर्ष 2024 के पुरस्कार के लिए 11 और वर्ष 2025 के लिए नौ महिला शिक्षकों का चयन किया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार, इन शिक्षकों ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए विद्यार्थियों की शिक्षा और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरियाणा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया ने चयनित शिक्षकों के नामों से संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं।

फरीदाबाद में महंगाई के खिलाफ नुक्कड़ नाटक सरकार से कीमतें नियंत्रित करने की उठी मांग

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद

बढ़ती महंगाई के खिलाफ गुरुवार को फरीदाबाद जन संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने एनआईटी-5 स्थित माता गुजरी चौक मोड़ पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर विरोध जताया। नाटक के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से आम लोगों, मजदूरों और कम आय वाले परिवारों को हो रही परेशानियों को सामने रखा। साथ ही सरकार से महंगाई पर तत्काल नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम आदमी की आय सीमित है, लेकिन दैनिक जरूरतों पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। खाद्य पदार्थों से लेकर पेट्रोलियम उत्पादों तक की बढ़ती कीमतों का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ रहा है। ऐसे में गरीब और मजदूर वर्ग के लिए परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है।

महंगाई डायन के रूप में दिखा कार्यकर्ता : नुक्कड़ नाटक के दौरान एक कार्यकर्ता 'महंगाई डायन' की वेशभूषा में नजर आया। इस गेटअप ने मौके पर मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं था, बल्कि लोगों को महंगाई के प्रभाव और इसके कारणों के प्रति जागरूक करना था।

नाटक में चीनी, सरसों के तेल, दाल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का विशेष रूप से जिक्र किया गया। समिति के अनुसार, चीनी की कीमत 62 रुपये प्रति किलो से अधिक पहुंच गई है। सरसों का तेल 250 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बताया गया, जबकि दालों के दाम भी 150 रुपये प्रति किलो से अधिक होने का दावा किया गया। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा होने की बात कहते हुए कहा कि महंगे ईंधन का असर परिवहन खर्च से लेकर अन्य जरूरी सामान की कीमतों पर भी पड़ता है। समिति के सदस्यों ने कहा कि महंगाई की सबसे अधिक मार दैनिक मजदूरी पर निर्भर परिवारों पर पड़ रही है।

20 साल से पढ़ा रहे 12 हजार गेस्ट टीचर्स अब भी कर रहे नियमितीकरण का इंतजार

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

दो दशक की सेवा के बाद भी स्थायी दर्जे को तरस रहे हजारों गेस्ट टीचर्स

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में करीब 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे 12 हजार गेस्ट टीचर्स आज भी नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हजारों विद्यार्थियों का भविष्य संवारने के बावजूद उनकी नौकरी के आगे अब भी 'गेस्ट' का दर्जा जुड़ा हुआ है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि समान परिस्थितियों में काम करने वाले करीब पांच हजार गेस्ट लेक्चरर्स को नियमित किया जा चुका है, जबकि स्कूलों के गेस्ट टीचर्स के मामले में अब तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

गेस्ट टीचर्स ने वर्ष 2014 में नियमितीकरण की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन किया था। उस समय भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर पहली कलम से गेस्ट टीचर्स को पक्का करने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं हो सका। वर्ष 2019 में सरकार ने गेस्ट टीचर्स को 58 वर्ष तक सेवा का लाभ देने की इच्छा जताई थी, लेकिन न्यायालय में मामला लंबित होने को अड़चन बताया गया।

अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से गेस्ट टीचर्स के पक्ष में आदेश आने और उसके खिलाफ अपील खारिज होने के बाद शिक्षकों को उम्मीद बंधी है। इसके बावजूद करीब 12 हजार शिक्षक नियमितीकरण के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने मुख्यमंत्री से बातचीत कर स्थायी समाधान का संकेत दिया है।

गेस्ट टीचर्स संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी डा. अजय लोहान के अनुसार हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर शिक्षकों का करीब चार हजार करोड़ रुपये का एरियर बनने का दावा है। उनका कहना है कि शिक्षक यह आर्थिक लाभ छोड़ने तक को तैयार हैं। यदि 2014 के बजाय 2019 से लाभ मिले, ज्वाइनिंग तिथि से वरिष्ठता मिले और नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दिया जाए, तो भी शिक्षक समाधान स्वीकार करने को तैयार हैं।

सरकार के आंतरिक आकलन के अनुसार नियमितीकरण से करीब 32 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आने का अनुमान है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि जब वे पुराने वित्तीय लाभ छोड़ने को तैयार हैं, तो सरकार के सामने नियमितीकरण का रास्ता आसान होना चाहिए।

गेस्ट टीचर्स संगठनों ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्षों तक विद्यार्थियों का भविष्य संवारने वाले शिक्षकों के अपने भविष्य को भी अब स्थायी सुरक्षा मिलनी चाहिए।

डेढ़ दशक पुराने हत्याकांड में पूर्व विधायक बाली पहलवान समेत सात दोषियों को उम्रकैद

भारतेन्दु संवाददाता, रोहतक

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल राठी की अदालत ने 15 साल पुराने हत्या मामले में महम के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने पूर्व विधायक समेत चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि आठ आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

मामला 5 मई 2011 का है। गांव मोखरा में गोशाला के चंदे को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद कलानौर की अनाज मंडी में निंगाणा गांव निवासी विष्णु की गोली लगने से मौत हो गई थी। मृतक के बसाना गांव निवासी पूर्व सरपंच जीजा सीताराम की शिकायत पर बाली पहलवान समेत 21 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने गवाह और अन्य साक्ष्य पेश किए। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने बाली पहलवान सहित सुनील, दिनेश उर्फ काला, राजेश, पवन, सुनील उर्फ सुल्हड़ और मुकेश को दोषी करार दिया।

वहीं सतेंद्र उर्फ मिंटू, परमजीत, सतीश, कुलदीप, राजेंद्र, दिनेश, रविंद्र और फूल कुमार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। मामले में छह अन्य आरोपियों सोमबीर, रोहतास, धर्म सिंह, राजबीर, अजय और धनपत की अलग-अलग समय पर मौत हो चुकी है।

बाली पहलवान ने मामले में तत्कालीन आइजी वी. कामराजा के सामने आत्मसमर्पण किया था। बाद में उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए उन्हें निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। करीब डेढ़ दशक तक चले मुकदमे के बाद आए फैसले पर मृतक के जीजा सीताराम ने कहा कि न्याय मिलने में काफी समय लगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।

फर्जी खनिज बिलिंग से 50 करोड़ के घोटाले का आरोप, खनन फर्मों के कार्यालयों पर कार्रवाई

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर

खनन रिकॉर्ड में 20 लाख टन से अधिक सामग्री दर्ज, साइट पर कम मात्रा मिलने का दावा।

पंचकूला की खनन साइट से खनिज सामग्री की कथित फर्जी बिलिंग के मामले में 50 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले के आरोप सामने आए हैं। बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की गठित कमेटी ने गंगानगर कालोनी स्थित श्री गणेश माइंस और राक बाटम माइंस के कार्यालयों पर छापेमारी कर बिलिंग और कंपनी से जुड़े दस्तावेजों की जांच की।

यह कार्रवाई पंचकूला निवासी संजीव चौधरी की याचिका पर की गई। आरोप है कि फर्जी बिलों के माध्यम से पंचकूला की खनन साइट की खनिज सामग्री यमुनानगर के पत्थर कुचलने वाले संयंत्रों को दिखाकर भेजी गई। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस व्यवस्था की आड़ में यमुनानगर में निकाले गए अवैध खनिज को वैध दिखाया गया।

मामले में आम आदमी पार्टी नेता आदर्श पाल सिंह का नाम भी चर्चा में है। उन पर संबंधित फर्म में छिपे साझेदार के रूप में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। हालांकि आदर्श पाल सिंह ने खनन से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि खनन के ठेके के समय जगाधरी से विकास और ललित गए थे। उन्होंने कहा कि उनका खनन कारोबार से कोई संबंध नहीं है।

शिकायतकर्ता संजीव चौधरी के अनुसार, सौदा तय होने के बाद हिस्सेदारी भी निर्धारित की गई थी। उसके मुताबिक उनकी 20 प्रतिशत, एक अन्य व्यक्ति की 25 प्रतिशत और शेष हिस्सेदारी आदर्श पाल सिंह की तय हुई थी। आरोप है कि आदर्श पाल ने सीधे फर्म में शामिल होने के बजाय ललित, विकास और नवीन बतरा को निदेशक बनाने की बात कही थी।

चौधरी ने बताया कि करीब 11 महीने बाद जब फर्म का हिसाब-किताब मांगा गया तो मामले को टालने की कोशिश की गई। संदेह होने पर लगभग दो महीने पहले जांच शुरू की गई। आरोप है कि दस्तावेजों की जांच में पता चला कि निदेशक पद से संबंधित प्रक्रिया में फर्जी हस्ताक्षर किए गए और निदेशक मंडल में बदलाव कर दिया गया।

शिकायतकर्ता का दावा है कि कंपनी ने कम समय में 20 लाख टन से अधिक खनिज सामग्री निकालने का रिकॉर्ड दिखाया, जबकि संबंधित खनन स्थल पर इतनी मात्रा में खनिज मौजूद ही नहीं था। साइट का सर्वे भी कराया गया था।

धान के पंजीकरण में उलटफेर से उठे सवाल, किसानों की संख्या बढ़ी लेकिन रकबा घटा

पोर्टल के आंकड़ों में गड़बड़ी की आशंका, भाकियू चढ़ूनी ने धान पंजीकरण की उच्चस्तरीय जांच मांगी

भारतेन्दु संवाददाता, कुरुक्षेत्र

प्रदेश में धान की फसल मंडियों में पहुंचने से पहले ही मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पोर्टल पर गैर-बासमती धान के पंजीकरण में पिछले वर्ष की तुलना में रकबा करीब 4.73 लाख एकड़ कम हुआ है, जबकि पंजीकृत किसानों की संख्या करीब 3.97 लाख बढ़ गई है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने इन आंकड़ों को गंभीर बताते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में 4,83,897 किसानों ने 28,80,192 एकड़ गैर-बासमती धान का पंजीकरण कराया था। इस वर्ष तीन अगस्त तक ही 8,81,128 किसानों ने 24,07,104 एकड़ गैर-बासमती धान का पंजीकरण कराया है। यानी किसानों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन पंजीकृत रकबा काफी कम हो गया है। किसान संगठन का कहना है कि इन आंकड़ों का बारीकी से सत्यापन किया जाना जरूरी है।

सत्यापन प्रक्रिया पर भी उठे सवाल : पंजीकरण के साथ कृषि विभाग की ओर से किए गए भूमि सत्यापन के आंकड़े भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वर्ष 2025 में पोर्टल पर 28,80,192 एकड़ गैर-बासमती धान का पंजीकरण हुआ था, जबकि कृषि विभाग ने 30,16,285 एकड़ भूमि का सत्यापन किया था। पंजीकृत रकबे से करीब 1,36,093 एकड़ अधिक भूमि का सत्यापन होने को लेकर भी किसान संगठनों ने सवाल उठाए हैं।

भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का कहना है कि धान खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पंजीकरण से लेकर सत्यापन तक हर स्तर पर जांच आवश्यक है। संगठन ने आशंका जताई है कि यदि आंकड़ों में किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो आगामी धान खरीद के दौरान इसका सीधा असर किसानों और सरकारी व्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है।

छह जिलों के आंकड़ों पर विशेष नजर : भवानी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और चरखी दादरी जिलों के आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। पिछले वर्ष इन छह जिलों में करीब 64,726 एकड़ धान का रकबा दर्ज किया गया था। इन जिलों में धान की सरकारी खरीद नहीं होती है। इसके बावजूद इस वर्ष पंजीकरण में किसानों की संख्या बढ़ने और रकबे में बदलाव को लेकर किसान संगठन ने जांच की मांग की है।

संगठन का कहना है कि पोर्टल पर दर्ज प्रत्येक किसान और उसके रकबे का जिला, तहसील, गांव तथा खसरा नंबर के स्तर पर सत्यापन कराया जाना चाहिए। इससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और यदि कहीं फर्जी या गलत पंजीकरण हुआ है तो उसका पता लगाया जा सकेगा।

भाकियू ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की : भाकियू चढ़ूनी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश बैंस ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष धान खरीद में करीब 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला हुआ था। उनका कहना है कि यदि उस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो इस वर्ष भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने सरकार और संबंधित विभागों से पोर्टल के आंकड़ों की गहन जांच कराने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि किसानों के वास्तविक रकबे और फसल का सही विवरण दर्ज होना जरूरी है, ताकि सरकारी खरीद व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे। किसान संगठन ने मांग की है कि धान की मंडियों में आवक शुरू होने से पहले ही पूरे पंजीकरण और सत्यापन तंत्र की समीक्षा की जाए। इससे किसानों के हितों की रक्षा के साथ सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

नए सॉफ्टवेयर से जमीन के इंतकाल में आएगी तेजी, 11 दिन में पूरी होगी प्रक्रिया

भारतेन्दु संवाददाता, झज्जर

प्रदेश में भूमि का इंतकाल दर्ज कराने के लिए लोगों को अब राजस्व कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व विभाग इंतकाल की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। नई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद भूमि इंतकाल दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया अधिकतम 11 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लोगों को अनावश्यक इंतजार और कार्यालयों में होने वाली देरी से राहत मिलने की उम्मीद है।

राजस्व विभाग की नई व्यवस्था में इंतकाल के आवेदन से लेकर उसके अंतिम पंजीकरण तक हर स्तर के लिए, निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचेगा और निर्धारित अवधि में उसकी जांच की जाएगी। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।

दस्तावेजों में कमी मिलने पर रुकेगी प्रक्रिया : नई व्यवस्था में दस्तावेजों की जांच को भी महत्वपूर्ण बनाया गया है। यदि पटवारी को आवेदन या प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी तरह की कमी दिखाई देती है, तो वह अपने स्तर पर प्रक्रिया को रोक सकेगा। संबंधित कमी दूर होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे गलत, अधूरे या संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर इंतकाल दर्ज होने की संभावना कम होगी। पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के प्रधान राजबीर गुलिया के अनुसार नया सॉफ्टवेयर तैयार होने के साथ ही नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य इंतकाल दर्ज करने की प्रक्रिया में होने वाली देरी को खत्म करना और लोगों को समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराना है।

तीन स्तरों पर होगी जांच: नई व्यवस्था के तहत इंतकाल की प्रक्रिया तीन स्तरों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले आवेदन पटवारी के पोर्टल पर पहुंचेगा। पटवारी को आवेदन और दस्तावेजों की जांच कर प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए चार दिन का समय मिलेगा।

इसके बाद मामला गिरदावर के पोर्टल पर जाएगा। गिरदावर दस्तावेजों और संबंधित रिकॉर्ड की जांच करेगा तथा इसके लिए तीन दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

अंतिम चरण में फाइल तहसीलदार के पोर्टल पर पहुंचेगी। तहसीलदार स्तर पर जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए चार दिन का समय निर्धारित किया गया है।

न्यूज ब्रीफ

नोएडा में मासूम की हत्या पर आक्रोश एनकाउंटर की मांग को लेकर मां की जिद

एजेंसी, नई दिल्ली। नोएडा में 13 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले में उसकी मां ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग करते हुए करीब 36 घंटे तक शव लेने से इनकार कर दिया। वह सेक्टर-94 स्थित मोर्चरी के बाहर डटी रही और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती रही। मामला सेक्टर-54 के जंगल से जुड़ा है, जहां 16 अगस्त को सेक्टर-20 क्षेत्र के किशोर को कथित तौर पर दो हजार रुपये के लेनदेन के विवाद में उसके दोस्तों ने बुलाया था। आरोप है कि विवाद के दौरान किशोर की हत्या कर दी गई। घटना के बाद परिवार में आक्रोश फैल गया। किशोर की मां ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और एनकाउंटर की मांग की। इसी मांग को लेकर उन्होंने लंबे समय तक बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया। बुधवार को वह दिनभर मोर्चरी के बाहर मौजूद रहीं। मामले की जानकारी मिलने के बाद सांसद महेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार से बातचीत कर मां को समझाया और न्याय का भरोसा दिलाया। सांसद के समझाने के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे के कारणों तथा आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव और लोगों में आक्रोश का माहौल रहा। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है।

दिल्ली पुलिस की परीक्षा देने जा रहे सीआईएसएफ जवान की ट्रेन हादसे में मौत

एजेंसी, नई दिल्ली। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर गुरुवार सुबह हुए ट्रेन हादसे में सीआईएसएफ जवान विवेक डागुर (23) की मौत हो गई। विवेक मूल रूप से टप्पल क्षेत्र के गांव सालपुर के रहने वाले थे और वर्तमान में ओडिशा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में तैनात थे। जानकारी के अनुसार, विवेक दिल्ली पुलिस की शारीरिक परीक्षा में शामिल होने के लिए घर लौट रहे थे। इसी दौरान अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय वह हादसे का शिकार हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है और हादसे से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। विवेक डागुर, गुलवीर डागुर के पुत्र थे। वह अपने परिवार में दो भाइयों में बड़े थे। कम उम्र में ही देश की सुरक्षा में योगदान देने वाले विवेक की अचानक मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया। परिजनों के अनुसार, विवेक दिल्ली पुलिस की शारीरिक परीक्षा में शामिल होने को लेकर घर लौट रहे थे। परीक्षा में शामिल होने से पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग अलीगढ़ के लिए रवाना हुए। विवेक की मौत से गांव में भी शोक का माहौल है।

रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा, गुरुग्राम में घंटों बस का इंतजार करती रहीं महिलाएं

एजेंसी, नई दिल्ली। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर महिलाओं को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई, लेकिन गुरुग्राम बस अड्डे पर पर्याप्त बसें उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बस अड्डे पर सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों और परिजनों के साथ पहुंचीं। मुफ्त यात्रा के चलते यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक रही। इसके बावजूद यात्रियों की भीड़ के मुकाबले रोडवेज बसों की संख्या कम दिखाई दी। बसों के इंतजार में महिलाओं को घंटों बस अड्डे पर खड़ा रहना पड़ा। कई यात्रियों ने बताया कि बस आने के बाद उसमें बैठने के लिए भी काफी भीड़ हो गई। बच्चों और बुजुर्गों के साथ यात्रा कर रहे परिवारों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। यात्रियों का कहना था कि रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा की घोषणा के साथ प्रशासन को अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी करनी चाहिए थी, ताकि महिलाओं को सुविधा के बजाय परेशानी का सामना न करना पड़े। मुफ्त यात्रा की सुविधा को महिलाओं के लिए राहत भरा कदम माना गया, लेकिन पर्याप्त परिवहन व्यवस्था नहीं होने से इसकी व्यवस्था पर सवाल उठे। यात्रियों ने भविष्य में त्योहारों के दौरान अतिरिक्त बसें चलाने और बेहतर इंतजाम करने की मांग की।

दिल्ली में जलभराव को लेकर सख्ती पीडब्ल्यूडी मंत्री ने दिए कड़े निर्देश

एनडीएमसी में जलभराव पर मंत्री का सख्त रुख, लापरवाही पर कार्रवाई तय

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली में हाल की तेज बारिश के बाद कई इलाकों में हुए जलभराव को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली के जल एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में जलभराव की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जल निकासी व्यवस्था और बारिश के दौरान सामने आई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सम्मेलन कक्ष में हुई। इसमें संबंधित मुख्य अभियंता और विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हाल में हुई बारिश के दौरान अलग-अलग स्थानों पर जमा हुए पानी और उसे निकालने में लगी अवधि की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति दोबारा पैदा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पहले से तैयारी मजबूत रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया। प्रवेश साहिब सिंह ने स्पष्ट किया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में लापरवाही के कारण जलभराव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि भविष्य में दोबारा जलभराव की समस्या सामने आती है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाने और लोगों को परेशानी से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए।

दरअसल, मंगलवार को राजधानी में कम समय में हुई तेज बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया था। सड़कों पर जलभराव के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली क्षेत्र के कई प्रमुख हिस्सों में भी पानी जमा होने की शिकायतें सामने आई थीं। इससे एक दिन पहले एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने जलभराव को लेकर स्थानीय लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। स्स्स

नोएडा में थार सवार युवकों की गुंडई, दो बहनों से छेड़छाड़ और पिस्तौल दिखाकर धमकी

एजेंसी, नई दिल्ली

नोएडा में थार सवार युवकों की कथित गुंडई का मामला सामने आया है। आरोप है कि आधी रात के समय स्कूटी से जा रही दो सगी बहनों का युवकों ने पीछा किया और उनके साथ अश्लील हरकतें कीं। विरोध करने पर आरोपियों ने अपनी थार गाड़ी आगे लगाकर दोनों बहनों की स्कूटी रोक दी और पिस्तौल निकालकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद दोनों बहनें काफी डर गईं। उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि दोनों बहनें स्कूटी से जा रही थीं, तभी थार सवार युवकों ने उनका पीछा करना शुरू किया। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद आरोपियों ने स्कूटी को रोक लिया। आरोप है कि युवकों ने दोनों बहनों के साथ अश्लील व्यवहार किया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो मामला और गंभीर हो गया। पीड़िताओं के अनुसार, विरोध करने पर युवकों ने पिस्तौल निकाल ली और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना से दोनों बहनों में भय का माहौल पैदा हो गया। उन्होंने किसी तरह मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि थार सवार युवकों की पहचान की जा सके। पुलिस घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है। घटना सामने आने के बाद इलाके में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

फरीदाबाद में बेकाबू डंपर ने दो पुलिसकर्मियों को कुचला, दोनों की मौत

एजेंसी, नई दिल्ली

फरीदाबाद में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो पुलिस कॉन्स्टेबलों की मौत हो गई। पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी में राइडर ड्यूटी पर तैनात नवीन और अभिषेक सोहना रोड पर सरूरपुर के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार और बेकाबू डंपर ने दोनों को कुचल दिया। हादसे में एक कॉन्स्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

बताया जा रहा है कि हादसे के बाद दोनों घायल पुलिसकर्मी करीब एक घंटे तक मदद का इंतजार करते रहे। स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंच सकी। समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिलने से उनकी हालत और गंभीर होती गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है। दो पुलिसकर्मियों की मौत की खबर से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। अधिकारियों ने घटना पर दुख जताते हुए मृतक जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की तत्परता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

रेवाड़ी में सांपों का कहर, जनवरी से अगस्त तक 75 लोगों को डसा

एजेंसी, नई दिल्ली

रेवाड़ी जिले में बारिश के मौसम के साथ सर्पदंश का खतरा बढ़ गया है। जनवरी से अगस्त तक जिले में 75 लोग सांप के काटने का शिकार हो चुके हैं। वर्षा के दौरान सांपों के बिलों में पानी भर जाने के कारण वे सुरक्षित और सूखे स्थानों की तलाश में बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में उनके घरों, पशुबाड़ों और आसपास के सूखे स्थानों में पहुंचने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश के मामले अधिक सामने आ रहे हैं। खेतों, कच्चे घरों और पशुबाड़ों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। रात के समय बाहर निकलते हुए टॉर्च का इस्तेमाल करना और जमीन पर सोने से बचना उपयोगी सावधानियां मानी जाती हैं। बारिश के मौसम में सावधानी बेहद जरूरी है। सांप दिखने पर उसे छेड़ें नहीं और काटने पर तुरंत अस्पताल पहुंचाएं, घरेलू इलाज से बचें।

रिटायरमेंट के दिन ही मिलेंगे पेंशन दस्तावेज एनडीएमसी कर्मचारियों को बड़ी राहत

एजेंसी, नई दिल्ली

सेवानिवृत्ति के साथ मिलेंगे पेंशन संबंधी जरूरी दस्तावेज

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को पेंशन से जुड़े दस्तावेज हासिल करने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को सेवा के अंतिम दिन ही पेंशन संबंधी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

एनडीएमसी के इस फैसले के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन की प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। कर्मचारियों और विभिन्न कर्मचारी एसोसिएशनों की ओर से लंबे समय से पेंशन संबंधी औपचारिकताओं में आने वाली परेशानियों की शिकायतें की जा रही थीं। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए एनडीएमसी अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कर्मचारियों के अनुसार, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन से जुड़े दस्तावेजों और अन्य औपचारिकताओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों में जाना पड़ता था। दस्तावेज तैयार कराने, जमा करने और प्रक्रिया की जानकारी लेने में समय लगता था। कई बार छोटी-छोटी औपचारिकताओं के कारण कर्मचारियों को दोबारा कार्यालय पहुंचना पड़ता था। नई व्यवस्था से इस परेशानी को कम करने का प्रयास किया गया है।

अब सेवानिवृत्ति से पहले ही पेंशन संबंधी प्रक्रिया को पूरा करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि कर्मचारी के सेवा से मुक्त होने के दिन जरूरी कागजात उसे सौंपे जा सकें। इससे कर्मचारियों को अपनी पेंशन प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट रूप से पता चल सकेगी और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।

बांधों से छोड़े पानी का असर, प्रयागराज में फिर बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर

एजेंसी, नई दिल्ली

प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और विभिन्न बांधों से छोड़े जा रहे पानी के कारण दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार, 26 अगस्त की शाम से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ। पिछले चार घंटों के दौरान गंगा के जलस्तर में करीब 4 सेंटीमीटर और यमुना में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय लोग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

यमुना में मध्य प्रदेश की केन और बेतवा नदियों के साथ-साथ राजस्थान की चंबल नदी का पानी पहुंच रहा है। इसके अलावा माताटीला बांध से भी यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है। इन कारणों से यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हुई बारिश का असर गंगा के जलस्तर पर भी पड़ा है। गंगा में कानपुर बैराज और नरौरा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण प्रयागराज में नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोग लगातार नदी के पानी की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। हालांकि, फिलहाल स्थिति को लेकर किसी बड़े खतरे की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जलस्तर में लगातार वृद्धि होने पर निचले इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे और संभावित प्रभावित क्षेत्रों पर निगरानी रखने की जरूरत बढ़ गई है। लोगों को भी सावधानी बरतने और नदी के बढ़ते पानी से दूर रहने की सलाह दी जा सकती है। आने वाले दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में बारिश की स्थिति के आधार पर गंगा और यमुना के जलस्तर में आगे भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

रक्षाबंधन से पहले आगरा में बड़ी कार्रवाई, 7000 लीटर मिलावटी दूध नष्ट

एजेंसी, नई दिल्ली

रक्षाबंधन से पहले आगरा में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने बड़ी कार्रवाई की है। त्योहार के दौरान बाजार में मिलावटी दूध, मावा और एनालॉग पनीर खपाने की तैयारी के बीच खाद्य सुरक्षा टीम ने करीब 7000 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया और 145 किलो मावा जब्त किया। बुधवार सुबह एफएसडीए की टीम ने सैंया टोल प्लाजा पर मध्य प्रदेश नंबर के एक टैंकर को रोककर जांच की। जांच के दौरान टैंकर में करीब 7000 लीटर मिलावटी दूध पाया गया। बताया गया कि टैंकर चालक के पास दूध से संबंधित कोई बिल या वैध दस्तावेज नहीं था। टीम ने कार्रवाई करते हुए दूध को मौके पर नष्ट करा दिया।

इसके अलावा फतेहाबाद के नाथूपुर क्षेत्र में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। यहां से 145 किलो मावा बरामद किया गया, जिसे जांच के लिए जब्त कर लिया गया। टीम ने अलग-अलग खाद्य पदार्थों के कुल 16 नमूने भी लिए हैं। इन नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के दौरान दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग काफी बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाकर मिलावटखोर नकली या घटिया गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ बाजार में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ऐसे मामलों पर लगातार नजर रख रही है।

अधिकारियों ने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री और आपूर्ति रोकने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

गुरुग्राम में 600 किमी सीवर-ड्रेनेज नेटवर्क का होगा सर्वे, सड़क धंसने की वजह तलाशेगा जीएमडीए

एजेंसी, नई दिल्ली

धंसती सड़कों से परेशान गुरुग्राम, होगा बड़ा सर्वे

गुरुग्राम में मानसून के दौरान सड़कों के बार-बार धंसने की समस्या ने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। शहर की सड़कों के नीचे बिछी पुरानी सीवर और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन लाइनों को इसकी संभावित वजह माना जा रहा है। अब गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए बड़े स्तर पर सर्वे कराने का फैसला किया है। जीएमडीए अपने करीब 600 किलोमीटर लंबे सीवर और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन नेटवर्क का विस्तृत सर्वे कराएगा। इस सर्वे का उद्देश्य यह पता लगाना है कि नेटवर्क की लाइनें कितनी पुरानी हैं, उनकी मौजूदा स्थिति कैसी है और किन स्थानों पर लीकेज या अन्य तकनीकी समस्या सामने आ रही है।

अधिकारियों के अनुसार, मानसून के दौरान लगातार बारिश होने पर जमीन के नीचे मौजूद पुरानी पाइपलाइन और ड्रेनेज व्यवस्था पर दबाव बढ़ जाता है। कहीं पाइपलाइन में लीकेज होने या उसके आसपास की मिट्टी कमजोर होने से सड़क की सतह धंसने की स्थिति बन सकती है। शहर के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद जीएमडीए ने पूरे नेटवर्क की स्थिति की जांच कराने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित सर्वे अगले महीने से शुरू होने की संभावना है। इसके तहत सीवर और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन की लाइनों की उम्र, संरचना, लीकेज वाले स्थानों और उनकी क्षमता का आकलन किया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि किन इलाकों में नेटवर्क को मरम्मत, बदलने या अपग्रेड करने की जरूरत है। सर्वे से मिलने वाली जानकारी के आधार पर जीएमडीए आगे की कार्ययोजना तैयार करेगा।

एसटीपी टेंडर मामले में एसीबी की कार्रवाई तेज, आरोपियों की पेशी पर अदालत में सुनवाई

दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी टेंडर घोटाले में नया मोड़, पूर्व सीईओ समेत दो की पेशी की मांग

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी घोटाले में नया मोड़

दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर घोटाला मामले में जांच एजेंसी एंटी करप्शन ब्रांच ने अदालत का रुख किया है। एसीबी ने अदालत में आवेदन दाखिल कर मामले में पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय और नागेंद्र यादव को पेश करने की मांग की है। इस घटनाक्रम के बाद मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई में नया मोड़ आया है। इसी मामले में आरोपी पंकज वर्मा को दो दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया। एसीबी ने अदालत से पंकज वर्मा को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है। अब इस मांग पर अदालत का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत इस मामले में दोपहर 2:15 बजे अपना आदेश पारित करेगी।

मामला दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े एसटीपी के टेंडर में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है। जांच एजेंसी इस मामले में टेंडर प्रक्रिया, संबंधित अधिकारियों की भूमिका और कथित वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। एसीबी का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर कुछ लोगों या कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। जांच के दौरान एजेंसी ने कई लोगों से पूछताछ की है और दस्तावेजों तथा वित्तीय लेन-देन से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, मामले में कथित भ्रष्टाचार की पूरी कड़ी का पता लगाने के लिए आरोपियों की भूमिका की पड़ताल जरूरी है। पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय और नागेंद्र यादव की अदालत में पेशी की मांग भी इसी जांच का हिस्सा है। एसीबी यह स्पष्ट करना चाहती है कि टेंडर प्रक्रिया में किस स्तर पर निर्णय लिए गए और उसमें किन लोगों की भूमिका रही।

वहीं, पंकज वर्मा की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद अब उनकी न्यायिक हिरासत को लेकर अदालत का निर्णय होना है। दोपहर 2:15 बजे आने वाला आदेश आगे की जांच की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल एसीबी मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी है और अदालत के आदेश के बाद आरोपियों की हिरासत तथा आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी। मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अभी जांच जारी है और अदालत के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ने जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने अदालत में आवेदन दाखिल कर पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय और नागेंद्र यादव को पेश करने की मांग की है। एसीबी का कहना है कि मामले की जांच में दोनों की भूमिका से जुड़े पहलुओं की पड़ताल जरूरी है। वहीं, आरोपी पंकज वर्मा को दो दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया। एसीबी ने उनकी न्यायिक हिरासत की मांग की है।

इस पर अदालत दोपहर 2:15 बजे आदेश पारित करेगी। मामला दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़ा है। जांच एजेंसी टेंडर प्रक्रिया, अधिकारियों की भूमिका और कथित वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। अदालत के आगामी आदेश से आरोपियों की हिरासत और आगे की जांच की दिशा स्पष्ट हो सकती है। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

नोएडा को मिलेगा बड़ा ट्रैफिक सॉल्यूशन, 1200 मीटर लंबा डबलडेकर फ्लाईओवर बनेगा

एजेंसी, नई दिल्ली

नोएडा में यातायात जाम की समस्या से लाखों लोगों को राहत देने के लिए एक बड़े डबलडेकर फ्लाईओवर के निर्माण की योजना है। फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद (एफएनजी) कॉरिडोर स्थित छिजारसी क्षेत्र में बनने वाला यह फ्लाईओवर करीब 1200 मीटर लंबा होगा। परियोजना पर लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रस्तावित फ्लाईओवर 12 लेन का होगा, जिसमें छह-छह लेन के दो स्तर बनाए जाएंगे। यह फ्लाईओवर राष्ट्रीय राजमार्ग-9 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर से गुजरेगा।

इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में रोजाना लगने वाले भीषण जाम को कम करना और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है। अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना से प्रतिदिन करीब तीन लाख लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। छिजारसी और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में वाहन आने-जाने के कारण अक्सर लंबा जाम लगता है। डबलडेकर फ्लाईओवर बनने के बाद स्थानीय यातायात को तेज और सुगम बनाने में मदद मिलेगी। यह परियोजना नोएडा के साथ-साथ फरीदाबाद और गाजियाबाद के बीच कनेक्टिविटी को भी मजबूत कर सकती है।

फ्लाईओवर के निर्माण से प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव कम होगा और यात्रियों का समय भी बचेगा। परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। नोएडा के छिजारसी में बनने वाला 12 लेन का डबलडेकर फ्लाईओवर यातायात व्यवस्था को नई रफ्तार देगा।

प्रेमी के लिए पति और बच्चों को छोड़ा, 13 महीने बाद लौटी तो पति ने किया साफ इनकार

एजेंसी, नई दिल्ली

इंस्टाग्राम के जरिए ट्रक चालक से प्रेम संबंध होने के बाद पति और बच्चों को छोड़कर गई एक महिला के 13 महीने बाद वापस लौटने से परिवार में विवाद खड़ा हो गया। महिला की शादी करीब 20 साल पहले हुई थी और उसके बच्चे भी हैं। आरोप है कि वह प्रेमी के साथ चली गई थी और लंबे समय तक उसके साथ रही। वापस लौटने के बाद महिला ने पति के साथ रहने की कोशिश की, लेकिन पति ने उसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। पति ने अपनी मां की कसम खाकर कहा कि वह अब पत्नी को अपने घर में नहीं रखेगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। परिवार के अनुसार, विवाद के दौरान महिला ने कथित तौर पर पति पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद मामला और गंभीर हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद महिला दोबारा अपने प्रेमी के पास चली गई। घटना की जानकारी सामने आने के बाद परिवार और आसपास के लोगों में भी चर्चा शुरू हो गई।

बिलासपुर में नौ ऐतिहासिक किले, बच्चरेटू किले के जीर्णोद्धार की योजना नहीं

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नौ ऐतिहासिक किले दर्ज हैं। हालांकि, इनमें प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर बच्चरेटू किले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की फिलहाल सरकार की कोई प्रस्तावित योजना नहीं है। सरकार ने विधानसभा में यह स्थिति स्पष्ट की है।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने वीरवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। विधायक ने सरकार से बिलासपुर जिले में मौजूद ऐतिहासिक किलों की संख्या और उनके नाम की जानकारी मांगी थी। साथ ही उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार ऐतिहासिक बच्चरेटू किले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो इसे कब तक किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री द्वारा दिए गए लिखित जवाब के अनुसार बिलासपुर जिले में कुल नौ ऐतिहासिक किले हैं। इनमें बच्चरेटू किला, बरसेह किला, फतेहपुर किला, सरयून किला, त्यून किला, झंज्यार किला, बहादुरपुर किला, कोट कहलूर किला और रतनपुर किला शामिल हैं। विधायक जीत राम कटवाल ने खास तौर पर ऐतिहासिक बच्चरेटू किले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने को लेकर सरकार से स्थिति पूछी थी। इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। यानी मौजूदा समय में बच्चरेटू किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई प्रस्तावित योजना सरकार के पास नहीं है।

हिमाचल में पुराने कांट्रेक्ट कैरिज व्हीकल का नहीं होगा चालान, सरकार ने जारी किए निर्देश

शिमला। हिमाचल प्रदेश में 12 से 15 वर्ष की आयु वाले अनुबंधित यात्री वाहनों (कांट्रेक्ट कैरिज व्हीकल) के संचालकों को फिलहाल राहत दी गई है। प्रदेश की सीमा के भीतर संचालित होने वाले ऐसे वाहनों के चालान नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक अनुबंधित यात्री वाहनों की आयु सीमा के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से अंतिम निर्णय नहीं आता।

उपमुख्यमंत्री ने वीरवार को विधानसभा में दिए वक्तव्य में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनुबंधित यात्री वाहनों की आयु सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने की मांग को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है और यह मामला पहले ही भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के समक्ष उठाया जा चुका है। राज्य सरकार ने केंद्र से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपने स्तर पर अनुबंधित यात्री वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष नहीं कर सकती। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 59 के तहत मोटर वाहनों की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इसलिए केंद्रीय प्रावधान में बदलाव के बिना राज्य स्तर पर आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय लेना संभव नहीं है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से इस विषय पर केवल अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है, बल्कि वाहन संचालकों की मांग को केंद्र के सामने लगातार उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के तहत वाहनों की निर्धारित आयु सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष की गई है और यह व्यवस्था एक अप्रैल 2026 से लागू है। इसी आधार पर अनुबंधित यात्री वाहनों के लिए भी 15 वर्ष की आयु सीमा पर सकारात्मक विचार करने का अनुरोध केंद्र से किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के निर्णय तक इच्छुक वाहन संचालक नियमानुसार अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के तहत आवेदन कर परमिट प्राप्त कर सकते हैं। वाहन संबंधी व्यवस्था और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पोर्टल का संचालन एवं प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया जाता है। एक अप्रैल 2026 से अब तक 1009 वाहन संचालक इस पोर्टल के माध्यम से इस व्यवस्था का लाभ उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अखिल भारतीय पर्यटक परमिट की फीस कम करने का मामला भी केंद्र के समक्ष उठाया है। इसके अलावा राज्य की सीमा के भीतर चलने वाले अनुबंधित यात्री वाहनों की परमिट अवधि 15 वर्ष करने का अनुरोध भी केंद्र सरकार से किया जाएगा। इससे वाहन संचालकों को अधिक राहत मिल सकती है। उपमुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कुछ राज्यों में अनुबंधित यात्री वाहनों की आयु सीमा 25 वर्ष होने संबंधी दावों का भी उल्लेख किया।

फिटनेस केंद्र पर्याप्त नहीं, मैन्युअल जांच जारी रखने की अनुमति मांगेगी सरकार

उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच के लिए स्वचालित परीक्षण केंद्रों की स्थिति भी सदन में रखी। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 62 के तहत वाहनों की फिटनेस जांच स्वचालित परीक्षण केंद्रों के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था है। हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में बद्दी, हरोली और नादौन में तीन स्वचालित परीक्षण केंद्रों को मंजूरी दी गई है। निजी क्षेत्र में कांगड़ा के रानीताल, मंडी के कांगू, बिलासपुर, नालागढ़ और पांवटा साहिब में पांच केंद्रों को मंजूरी मिली है। इनमें रानीताल और कांगू के केंद्र काम करना शुरू कर चुके हैं, जबकि अन्य केंद्रों में काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में पांच और स्वचालित परीक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें कांगड़ा के जस्सूर या डमटाल और पालमपुर, सिरमौर के काला अंब, कुल्लू के भुंतर और चंबा के बनीखेत शामिल हैं। उन्होंने माना कि प्रदेश में अभी स्वचालित परीक्षण केंद्रों की संख्या पर्याप्त नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार के समक्ष यह मामला भी प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा कि जब तक इन केंद्रों की व्यवस्था व्यापक स्तर पर स्थापित नहीं हो जाती, तब तक मैन्युअल फिटनेस जांच जारी रखने की अनुमति दी जाए।

विद्यार्थियों ने बनाई आकर्षक राखियां, जवानों को भी भेजीं

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। तृप्ता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलवाड़ा में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कक्षा दूसरी से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए राखी मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने आकर्षक एवं रचनात्मक राखियां तैयार कीं, जिनकी विद्यालय परिसर में प्रदर्शनी भी लगाई गई।

विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश राणा और चेयरमैन वरिंद्र नरियाल ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई कुछ राखियां देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए भी भेजी गईं। इस अवसर पर बच्चों ने जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की, जो देश की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। प्रधानाचार्य राकेश राणा ने विद्यार्थियों को रक्षाबंधन के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि हमें उन लोगों के प्रति भी सम्मान व्यक्त करना चाहिए, जो किसी न किसी रूप में हमारी सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय के बस चालक-परिचालक बच्चों को सुरक्षित स्कूल लाने-ले जाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। वहीं, गैर-शिक्षण कर्मचारी भी विद्यार्थियों की सुरक्षा और देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चेयरमैन वरिंद्र नरियाल और प्रधानाचार्य राकेश राणा ने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई-बहन के प्रेम, विश्वास व स्नेह का यह पावन बंधन सभी के जीवन में सुख-समृद्धि और खुशियां लाए।
डीएस ठाकुर, विधायक, डलहौजी, हिमाचल प्रदेश।

न्यूज ब्रीफ

हिमाचल हाईकोर्ट को मिले तीन नए न्यायाधीश

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जारी अधिसूचना के अनुसार चिराग भानु सिंह को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल को दो वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के अनुसार नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 217(1) और 224 के तहत की गई हैं। इनका कार्यकाल कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जून में तीनों नामों को मंजूरी दी थी। चिराग भानु सिंह वर्तमान में कांगड़ा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं और उन्हें न्यायिक क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का अनुभव है। भूपेश शर्मा वर्तमान में हिमाचल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं। उन्होंने विभिन्न जिलों में न्यायिक सेवाएं देने के साथ सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली है। योगेश जसवाल वर्तमान में सिरमौर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। वे हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी के निदेशक सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे चुके हैं।

राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलो इंडिया सवांद आयोजित

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अवसर पर खेलो इंडिया सवांद आयोजित किया गया। मंडी जिले के तीन चयनित संस्थानों में बल्लभ महाविद्यालय भी इस आयोजन का हिस्सा रहा। मुख्य अतिथि संतोष कुमार कपूर, विशिष्ट अतिथि कमल किशोर, प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार उपस्थित रहे। नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन में युवाओं को खेलों से जुड़ने और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रधानमंत्री के संबोधन के पश्चात कमल किशोर के साथ युवा संवाद आयोजित किया गया, जिसका संचालन के नीरज जी ने किया। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. दीपाली अशोक ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम युवाओं को खेल, फिटनेस, नेतृत्व, एवं नशामुक्त जीवन से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा।

नीट में 85% स्टेट कोटा देने की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, पालमपुर। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और अन्य राज्यों में रह रहे प्रवासी हिमाचलियों ने प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर रोष जताते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। ज्वालामुखी विकास सभा, पालमपुर सुधार सभा, हिमाचल कल्याण सभा, हिमाचल मंडी जन कल्याण सभा, हिमाचल मित्र मंडल, अखिल भारतीय प्रवासी हिमाचली संयुक्त मोर्चा और हिम सामाजिक संगठन दिल्ली सहित विभिन्न संस्थाओं ने प्रवासी हिमाचलियों के हितों से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। ज्वालामुखी विकास सभा के महासचिव राकेश चंद्र ने कहा कि दिल्ली-चंडीगढ़ सहित अन्य राज्यों में रहने वाले कई हिमाचली परिवारों के बच्चे बोनाफाइड हिमाचली होने के बावजूद नीट-यूजी की 85 प्रतिशत स्टेट कोटा काउंसलिंग से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने मांग की कि निजी क्षेत्र में कार्यरत हिमाचली अभिभावकों के बच्चों को भी राज्य कोटे में पात्र माना जाए। पालमपुर सुधार सभा के अध्यक्ष एवं समाजसेवी विजय डोगरा ने कहा कि प्रवासी हिमाचली प्रदेश की हर विपदा में सहयोग करते रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा। संस्थाओं ने उत्तराखंड की तर्ज पर प्रवासी हिमाचली कल्याण बोर्ड गठित करने, नीट-यूजी के 85 प्रतिशत राज्य कोटे में प्रवासी हिमाचली बच्चों को पात्रता देने तथा दिल्ली-चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवनों में प्रवासी संस्थाओं के कार्यक्रमों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की है। साथ ही हिमाचल सदन की बुकिंग संबंधी प्रतिबंध हटाने की मांग भी उठाई गई। संस्थाओं ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र विचार नहीं हुआ तो दिल्ली में विशाल प्रवासी हिमाचली महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

आईआरडीपी चयन के मापदंडों में बदलाव करे सरकार: जीतराम कटवाल

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। झंडूता चुनाव क्षेत्र के विधायक जीतराम कटवाल ने विधानसभा के मानसून सत्र में आईआरडीपी सर्वे के नौवें चरण की गाइडलाइंस पर कड़ा ऐतराज जताया और नियमों में तत्काल संशोधन की मांग की। पात्र परिवार हो रहे वंचित: उन्होंने कहा कि मनरेगा में केवल एक दिन काम करने की शर्त का फायदा उठाकर साधन-संपन्न लोग योजना में शामिल हो रहे हैं, जबकि बेसहारा महिलाएं और वास्तविक गरीब परिवार कड़े नियमों के चलते छूट रहे हैं। सर्टिफिकेट की समस्या: बिलासपुर जिला में ही लगभग 7,000 लोगों के इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पाए हैं। पहले जिन पंचायतों में 150 परिवार चयनित थे, वहां अब यह संख्या घटकर 35 से 50 रह गई है। आवेदन की तिथि बढ़ी: विधायक के तर्कों को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने गाइडलाइंस में बदलाव के संकेत दिए हैं और आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी है।

पांच करोड़ से बड़े निर्माण कार्यों की संयुक्त निविदा से इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों के हित प्रभावित नहीं होंगे: धर्माणी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में वीरवार को सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों की संयुक्त निविदा को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने नियम-62 के तहत यह मामला सदन में उठाया था।

लोक निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति में तकनीकी शिक्षा एवं नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि संयुक्त निविदा व्यवस्था से इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों के माध्यम से जुड़े हिमाचली कामगारों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजेश धर्माणी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने 19 मई, 2026 को एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार पांच करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित लागत वाले कार्यों को सिविल, इलेक्ट्रिकल और उद्यान संबंधी कामों को शामिल करते हुए संयुक्त निविदा के आधार पर दिया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी भवन निर्माण में शामिल विद्युत से जुड़े काम पात्र इलेक्ट्रिकल एजेंसियों के माध्यम से ही करवाए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि निविदा की शर्तों के अनुसार मुख्य ठेकेदार को छोटे घटक का काम खुद करना होगा या विद्युत कार्यों के लिए किसी पात्र एजेंसी को अपने साथ जोड़ना होगा। इसके लिए मुख्य ठेकेदार को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अधिकतम तीन इलेक्ट्रिकल एजेंसियों का विवरण देना होगा। यदि बोली जमा करते समय यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो बोली स्वीकृत होने से पहले यह विवरण देना होगा। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग में कई बड़े भवन निर्माण कार्य सिविल और इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों के बीच पर्याप्त समन्वय नहीं होने के कारण देर से पूरे होते हैं। ऐसे मामलों में यह भी तय करना मुश्किल होता है कि देरी के लिए जिम्मेदारी किसकी है। सरकार ने इसी समस्या को देखते हुए बड़े कार्यों को एक ही संस्था के माध्यम से करवाने की व्यवस्था की है। इससे काम की जिम्मेदारी स्पष्ट होगी और निर्माण की गुणवत्ता तथा समय सीमा पर निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी। राजेश धर्माणी ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की व्यवस्था का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में भी भवन और सड़क निर्माण के लिए समग्र निविदा प्रणाली अपनाई जाती है। इसमें सिविल कार्यों के साथ भवन के अंदर और बाहर किए जाने वाले विद्युत कार्यों को भी शामिल किया जाता है।

रोबोटिक सर्जरी के दावों से पहले अस्पतालों की मूलभूत सुविधाएं सुधारें सरकार: त्रिलोक जम्वाल

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने विधानसभा में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार रोबोटिक सर्जरी जैसी बड़ी घोषणाएं करने से पहले अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करे। विधायक ने कहा कि प्रदेश के कई स्वास्थ्य संस्थानों में दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं और बुनियादी ढांचे की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने आईजीएमसी की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि लिफ्ट खराब होने के कारण मरीजों को स्ट्रेचर के माध्यम से ले जाना पड़ रहा है। वहीं, चम्याणा अस्पताल के लिए चार वर्षों में संपर्क मार्ग तक नहीं बन पाया है। बिलासपुर जोनल अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में डेड बॉडी वैन उपलब्ध नहीं है, जबकि एकमात्र एंबुलेंस अक्सर वीआईपी ड्यूटी में रहती है। ऑक्सीजन प्लांट करीब छह माह से खराब है और निजी क्षेत्र से सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पूरे जिले में एक भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और करीब 80 प्रतिशत पोस्टमार्टम मामलों को एम्स बिलासपुर रेफर किया जा रहा है। मैमोग्राफी मशीन का प्रिंटर दो वर्षों से उपलब्ध नहीं है। विधायक ने हिमकेयर और सहारा योजना को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा और कहा कि लाभार्थियों को समय पर सहायता नहीं मिल रही है।

तृप्ता स्कूल में फ्रूट और सलाद मेकिंग गतिविधि में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। तृप्ता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलवाड़ा में कक्षा चौथी और पांचवीं के विद्यार्थियों के लिए फ्रूट एवं सलाद मेकिंग गतिविधि का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने इस गतिविधि में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न प्रकार के फलों से आकर्षक और पौष्टिक फ्रूट सलाद तैयार किए।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कक्षा चौथी के विद्यार्थियों ने सेब, अमरूद, अनानास, नाशपाती, कीवी सहित विभिन्न मौसमी फलों से सुंदर ढंग से फ्रूट सलाद तैयार किया। विद्यार्थियों ने गतिविधि के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा। इसी प्रकार कक्षा पांचवीं के विद्यार्थियों ने भी विभिन्न प्रकार के सलाद तैयार कर अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने प्रधानाचार्य के साथ बातचीत करते हुए फ्रूट सलाद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि फलों का नियमित सेवन शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। प्रधानाचार्य राकेश राणा ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता और प्रस्तुति की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से बच्चों में स्वस्थ खान-पान, स्वच्छता और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया।

विधायक गांधी ने विधानसभा में उठाया कंसा चौक डंपिंग साइट का मामला

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। बल्ह विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी ने विधानसभा में स्याह पंचायत स्थित नगर परिषद नेरचौक की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन साइट कंसा चौक को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार से पूछा कि लंबे समय से संचालित डंपिंग साइट को किसी उपयुक्त वैकल्पिक स्थान पर कब स्थानांतरित किया जाएगा और इस संबंध में सरकार की क्या योजना है।

जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया कि कंसा चौक स्थित डंपिंग साइट को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का फिलहाल कोई विचार या प्रस्ताव नहीं है। विधायक ने सरकार के इस जवाब पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि क्षेत्र की जनता की वर्षों पुरानी गंभीर समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है। उन्होंने कहा कि कंसा चौक का मैदान बल्ह विधानसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण खेल मैदानों में शामिल है। डंपिंग साइट के कारण आसपास के लोगों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कचरे के उचित प्रबंधन और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर भी प्रशासन को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। विधायक ने सरकार से जनहित में इस समस्या का स्थायी समाधान करने, वैकल्पिक स्थान तलाशने और क्षेत्रवासियों को राहत देने की दिशा में जल्द कदम उठाने की मांग की।

चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन पर्ची से 3 साल में 16.38 करोड़ रुपए की आय, अनियमितताओं पर एफआईआर

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ व मंदिर श्री चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन की सुविधा देने के लिए शुरू की गई 'सुगम दर्शन पर्ची' व्यवस्था से मंदिर न्यास को अगस्त 2023 से जून 2026 तक 16 करोड़ 38 लाख 47 हजार 86 की आय हुई है।

इस व्यवस्था के संचालन के दौरान अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों और कार्रवाई को लेकर भी सरकार ने विधानसभा में स्थिति स्पष्ट की है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने वीरवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। विधायक ने पूछा था कि क्या माता चिंतपूर्णी मंदिर में 'सुगम दर्शन पर्ची' व्यवस्था लागू की गई है और इससे कितनी आय हुई है। उन्होंने यह भी पूछा था कि पर्चियां काटने के दौरान अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं या नहीं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई। सरकार के लिखित जवाब के अनुसार माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में 'सुगम दर्शन पर्ची' व्यवस्था अगस्त 2023 से शुरू की गई थी। इससे हुई आय का वर्षवार ब्योरा भी विधानसभा में दिया गया। 8 अगस्त 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच इस व्यवस्था से 1 करोड़ 43 लाख 2 हजार 641 रुपये की आय हुई। वर्ष 2024 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आय 4 करोड़ 66 लाख 38 हजार 336 रुपये रही। वर्ष 2025 में इस व्यवस्था से मंदिर को 6 करोड़ 9 लाख 43 हजार 469 रुपये की आय हुई। इसके बाद वर्ष 2026 में 1 जनवरी से 30 जून तक 4 करोड़ 19 लाख 62 हजार 640 रुपये की आय दर्ज की गई। इन सभी अवधियों को मिलाकर कुल आय 16 करोड़ 38 लाख 47 हजार 86 रुपये रही। सतपाल सिंह सत्ती के दूसरे सवाल में सुगम दर्शन पर्ची काटने के दौरान अनियमितताओं की शिकायतों का मुद्दा उठाया गया था। सरकार ने जवाब में कहा कि सुगम दर्शन पर्ची काटने के दौरान अनियमितताओं की कोई शिकायत श्री चिंतपूर्णी मंदिर न्यास कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, मंदिर अधिकारी की ओर से सुगम दर्शन पर्ची सॉफ्टवेयर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद कुछ अनियमितताएं पाई गईं। सरकार के अनुसार इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई है और पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है

चिट्टा अकाल मृत्यु, इससे दूर रहें युवा: नरेंद्र

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। चिट्टा आज प्रदेश में एक गंभीर खतरा बन चुका है, चिट्टा अकाल मृत्यु है, युवाओं को इससे दूर रहकर, खेलों में सहभागिता बढ़ानी चाहिए। यह बात हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष व भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेंद्र अत्री ने एनसीओई, हमीरपुर में चल रहे खेल उत्सव में फुटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ पर बतौर मुख्यातिथि कहीं। एनसीओई ,हमीरपुर खेलों के प्रति युवाओं को आकर्षित करने व नशे के खिलाफ जागरूकता लाने की दृष्टि से, व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। भाजपा नेता नरेंद्र अत्री ने युवाओं को मौजूद खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, प्रबंधकों को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ी खेल के मैदान में मेहनत करके न केवल अपने संस्थान, अपने क्षेत्र, अपने परिवार व राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं, बल्कि स्वस्थ व सशक्त समाज के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। अतः आज जब प्रदेश में चिट्टा रुपी नशा एक गंभीर समस्या बन चुका है, ऐसे में जिम्मेवार युवाओं, खिलाड़ियों, प्रशिक्षक व समाज के सभी जिम्मेदार नागरिकों की नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान में और अधिक जिम्मेदार भूमिका अपेक्षित रहती है। इस अवसर पर फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबाल ,एथलेटिक्स आदि खेल मुकाबले आयोजित किया जा रहे हैं। इस मौके पर एनसीओई हमीरपुर, सेंटर प्रभारी दिव्या शर्मा, अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक जानी चौधरी, हैप्पी कुमार,अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रशिक्षक प्रेम ठाकुर, हॉकी प्रशिक्षक पिंकी चौहान, एथलीट प्रशिक्षक राजेंद्र धीमान, अनीश, कपिल शामा, दीक्षित गौतम, रियान आदि अन्य खेल प्रबंधक भी मौजूद रहे।

चुनावी गारंटी के नाम पर मातृशक्ति से धोखा : वीरेंद्र

भारतेन्दु संवाददाता, ऊना। राष्ट्रीय वॉलीबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस सरकार पर हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के साथ चुनावी वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। वीरवार को ऊना में पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने प्रदेश की हर महिला को 1,500 प्रतिमाह देने की गारंटी दी थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस वादे को पात्रता, आय सीमा और अन्य शर्तों में बांट दिया गया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने 18 नवंबर 2022 को हिमाचल में स्पष्ट रूप से महिलाओं को 1,500 प्रतिमाह देने का वादा किया था। यह कांग्रेस की प्रमुख चुनावी गारंटियों में शामिल था। चुनावों के दौरान महिलाओं से इस संबंध में फार्म भी भरवाए गए और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्हें नियमित आर्थिक सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने इस वादे का स्वरूप ही बदल दिया।

पठानकोट में कर्मचारियों-पेंशनरों का महाबंद

सरकारी दफ्तरों पर लटके ताले, कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। पंजाब के कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के संयुक्त फ्रंट के आह्वान पर पठानकोट में आयोजित महाबंद का व्यापक असर देखने को मिला। जिलेभर के सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में कामकाज ठप रहा। कर्मचारियों और पेंशनरों ने संस्थानों को बंद कर ताले लगाए और बस स्टैंड पर एकत्र होकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।

डीएसी कॉम्प्लेक्स मलिकपुर, सिविल अस्पताल, रोडवेज, डैम सहित कई सरकारी संस्थानों में बंद के चलते सन्नाटा पसरा रहा। बड़ी संख्या में कर्मचारी, पेंशनर, शिक्षक, पटवारी, आंगनवाड़ी वर्कर, स्वास्थ्य विभाग, एनएचएम, बिजली बोर्ड, रोडवेज, सफाई कर्मचारी, दर्जा-4 कर्मचारी और विभिन्न विभागों के कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल हुए। पीएसएमएसयू के जिला प्रधान विशालवीर सिंह के नेतृत्व में संगठन के सदस्य रोष रैली में पहुंचे। इसके अलावा स्टेट पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट, पुलिस पेंशनर्स, शिक्षक संगठनों, पंजाब रोडवेज पनबस एवं पीआरटीसी वर्कर्स यूनियन, सिंचाई, लोक निर्माण, जल सप्लाई एवं सैनिटेशन, कृषि, वन, पशुपालन, आयुर्वेदिक, नगर परिषद, सीवरेज बोर्ड सहित अनेक संगठनों ने भाग लिया। क्लर्क, स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, आशा वर्कर्स, मिड-डे मील वर्कर्स, पंचायत सचिव, डीसी कार्यालय, अदालत और जेल विभाग के कर्मचारियों ने भी समर्थन दिया। सरकारी संस्थानों को बंद करने के बाद कर्मचारी और पेंशनर बस स्टैंड पर एकत्र हुए। यहां से गांधी चौक तक विशाल रोष मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की कर्मचारी एवं पेंशनर विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला कर्मचारियों की भी बड़ी संख्या में भागीदारी रही। गांधी चौक पर प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर रोष जताया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबे समय से लंबित मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण उन्हें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा है। पीएसएमएसयू जिला प्रधान विशालवीर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों की एकजुटता सरकार को आगामी चुनावों में जवाब देगी। उन्होंने मांग की कि 17 जुलाई 2020 का पुरानी पेंशन योजना संबंधी पत्र रद्द कर सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। साथ ही पेंशनरों को 2.59 गुणांक का लाभ और डीए के लंबित बकाए जारी करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें स्वीकार नहीं हुईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और आगामी चुनावों में कर्मचारी-पेंशनर अपनी एकता और ताकत का जवाब देंगे।

चुनाव से पहले 5 लाख नौकरियों का वादा, अब युवाओं के हाथ में लॉटरी का टिकट थमाने की तैयारी : अनुराग

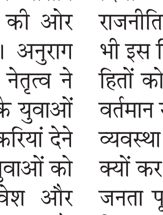

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित लॉटरी टेंडर को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए इसे प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए चिंताजनक कदम बताया है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा करने के बजाय सरकार ऐसी व्यवस्था लाने की तैयारी कर रही है, जो युवाओं को आसान पैसे और जुए की प्रवृत्ति की ओर आकर्षित कर सकती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने चुनाव से पहले हिमाचल के युवाओं को पांच लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। आज युवाओं को रोजगार के अवसर, निवेश और सुरक्षित भविष्य की आवश्यकता है, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं इसके विपरीत दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार देने के बजाय युवाओं के हाथ में लॉटरी का टिकट थमाना प्रदेश के भविष्य के साथ न्याय नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिमाचल की भोली-भाली जनता से चुनाव के दौरान बड़े-बड़े वादे किए थे। कांग्रेस सरकार को अब उन वादों का हिसाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि पांच लाख नौकरियों का वादा पूरा करने की दिशा में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि लॉटरी को लेकर हिमाचल प्रदेश में पहले भी राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर व्यापक सहमति रही है। तत्कालीन धूमल और वीरभद्र सरकारों ने भी ऐसी व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ने दिया था। जब अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं की सरकारें भी इस विषय पर प्रदेश के सामाजिक हितों को प्राथमिकता देती रही हैं, तो वर्तमान सुक्खू सरकार आखिर लॉटरी व्यवस्था को फिर से लाने की कोशिश क्यों कर रही है, यह सवाल प्रदेश की जनता पूछ रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे शांतिपूर्ण प्रदेश में युवाओं को रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, न कि उन्हें लॉटरी और जुए के आकर्षण की ओर ले जाने की।

नेपाल त्रासदी में हिमाचल का कोई व्यक्ति नहीं लापता : सुक्खू

विधानसभा में दो मिनट का मौन रखा, कहा- जलवायु परिवर्तन से बढ़ रहा प्राकृतिक आपदाओं का खतरा

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेपाल में हुई भीषण त्रासदी पर गहरा दुख जताते हुए कहा है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार 133 भारतीय नागरिकों के लापता होने की सूचना है।

उन्होंने कहा कि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश के किसी नागरिक के लापता होने की जानकारी उन्हें नहीं मिली है। नेपाल में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए वीरवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में दो मिनट का मौन भी रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल में हुई आपदा बहुत बड़ी है और यह जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव की ओर भी संकेत करती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023–24 में हिमाचल प्रदेश में आई आपदाओं के दौरान भी उन्होंने मौसम में हो रहे बदलाव और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मुद्दा उठाया था। इसका असर पहले हिमाचल प्रदेश और बाद में उत्तराखंड सहित पूरे हिमालयी क्षेत्र में दिखाई दे सकता है। उन्होंने कहा कि जब किसी बड़ी आपदा में बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है तो उसका गहरा आघात होता है। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023–24 की आपदाओं के बाद आपदा प्रबंधन को लेकर लगातार बैठकें की जाती रही हैं। तेज बारिश, बादल फटने और नदियों में अचानक बाढ़ आने जैसी स्थितियों को देखते हुए समय रहते प्रशासन को अलर्ट किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में बारिश अपेक्षाकृत कम हुई है, लेकिन जिन क्षेत्रों में तेज बारिश या बादल फटने की घटना होती है, वहां प्रशासन को पहले से सतर्क किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और इससे बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का पूरे एशियाई क्षेत्र में अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि हिमाचल में आपदाओं के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, पर्यावरण विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की टीम से विस्तृत अध्ययन कराने का आग्रह किया था। इसके बाद एक टीम हिमाचल प्रदेश में अध्ययन के लिए आई थी। हालांकि उस अध्ययन के बाद क्या निष्कर्ष सामने आए, इसकी जानकारी उन्हें अभी नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि बादल फटने की घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण हो सकता है और इसके चलते आपदाओं से होने वाला नुकसान भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में भूस्खलन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। पहाड़ों में कटाव होने के बाद कुछ समय तक भूस्खलन की घटनाएं जारी रह सकती हैं और स्थिति सामान्य होने में समय लगता है।

प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी प्रक्रिया अभी दिल्ली स्तर पर चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक केंद्र सरकार से औपचारिक मंजूरी नहीं मिलती, तब तक हिमाचल प्रदेश यह नहीं मान सकता कि उसे 1500 करोड़ रुपये की राशि मिल गई है।

लॉटरी भाग्य का खेल, खरीदना किसी के लिए अनिवार्य नहीं : मुख्यमंत्री

लॉटरी को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉटरी भाग्य का खेल है और किसी व्यक्ति के लिए इसे खरीदना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसकी इच्छा होगी, वही लॉटरी खरीदेगा। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर दिए गए पत्र और उठाए गए सवालों पर सरकार गौर करेगी। ग्लेशियर झीलों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस विषय पर सतर्क है। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक ग्लेशियर झील के बारे में जानकारी सामने आई है, जो कई वर्षों से मौजूद है। इस संबंध में ग्लेशियरों का अध्ययन करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक भी की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर ग्लेशियर कम हो रहे हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में उनमें बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। ऐसे में मौजूदा स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन होने के बाद ही पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि यदि सड़क की स्थिति ठीक नहीं है तो वाहन चालकों से टोल क्यों लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से बात करेंगे।

रक्षाबंधन पर प्रदेश में इस बार सभी सरकारी संस्थानों में छुट्टी, महिलाओं को एचआरटीसी बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में इस बार रक्षाबंधन के मौके पर सभी सरकारी संस्थानों में छुट्टी रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 28 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस फैसले से इस बार रक्षाबंधन पर सरकारी कर्मचारियों को भी अवकाश मिलेगा।

सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 28 अगस्त शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह अवकाश रक्षाबंधन के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों को पर्व मनाने के लिए दिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 28 अगस्त का यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक अवकाश नहीं माना जाएगा। हिमाचल में पहले रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को अवकाश दिए जाने की व्यवस्था थी। इस बार सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए सभी सरकारी संस्थानों में छुट्टी घोषित की है। यानी रक्षाबंधन पर पुरुष सरकारी कर्मचारियों को भी अवकाश मिलेगा। छुट्टी की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पहले विधानसभा में की और इसके बाद इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई। रक्षाबंधन के दिन हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में कहा कि पर्व के मौके पर महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को मिलेगी। सरकार के इस फैसले से रक्षाबंधन के दिन सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को परिवार के साथ पर्व मनाने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ब्रह्माकुमारी बहनों ने बांधी राखी।

न्यूज ब्रीफ

छात्रों ने जवानों को राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन

भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल सूरजपुर के विद्यार्थियों ने देश की रक्षा में तैनात वीर जवानों के साथ रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया। चेयरमैन रणवीर सिंह, सचिव कमलजीत सिंह और प्रधानाचार्या अनुमीत कौर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में कक्षा सातवीं, आठवीं और दसवीं की छात्राएं अपने अध्यापकों के साथ फौजी छावनी पहुंचीं। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने जवानों को राखियां बांधकर उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। इससे पहले विद्यार्थियों ने नृत्य, भाषण और कविता की प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को भावपूर्ण बनाया। छात्राओं द्वारा राखी बांधे जाने पर जवानों ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। छावनी में जवानों की ओर से विद्यार्थियों का स्वागत किया गया तथा उनके खान-पीने की उचित व्यवस्था भी की गई। प्रधानाचार्या अनुमीत कौर ने विद्यार्थियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व भाई-बहन के पवित्र प्रेम और आपसी विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के साथ त्योहार मनाना बच्चों में राष्ट्रप्रेम और सम्मान की भावना को मजबूत करता है।

नेपाल में बाढ़ के बाद जारी की हेल्पलाइन डेस्क

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। नेपाल में 26 अगस्त को आई अचानक बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन बिलासपुर ने नेपाल गए जिले के लोगों के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए हेल्पलाइन डेस्क सक्रिय किया है। प्रशासन ने ऐसे लोगों के परिजनों से अपील की है, जिनके रिश्तेदार नेपाल में फंसे, लापता या प्रभावित हो सकते हैं। जिला प्रशासन के अनुसार संबंधित व्यक्ति की उपलब्ध जानकारी जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (डीईओसी) को आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन 1077, दूरभाष नंबर 01978-224901, 01978-224902, 01978-224903 और 01978-224904, मोबाइल 94594-57061 अथवा ई-मेल ddmabilaspur@gmail.com पर साझा की जा सकती है। डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा कि परिजनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर डीईओसी संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा। इसके माध्यम से लापता या प्रभावित लोगों की तलाश, सहायता और बचाव के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने परिजनों से अपील की है कि वे उपलब्ध जानकारी जल्द साझा करें, ताकि जरूरतमंद लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाई जा सके। प्रशासन ने कहा कि सही और समय पर मिली जानकारी किसी की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है।

डीसी ने एसएए केंद्र व वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने वीरवार को विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए) केंद्र, शिशु गृह और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, व्यवस्थाओं और सेवाओं की जानकारी लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीसी ने बताया कि बिलासपुर में एसएए केंद्र हाल ही में शुरू हुआ है। यहां अनाथ, परित्यक्त एवं आत्मसमर्पित बच्चों को सुरक्षित आश्रय, संरक्षण और देखभाल उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्तमान में केंद्र में कोई बच्चा नहीं है। कानूनी प्रक्रिया के तहत बच्चों के पुनर्वास और दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया भी यहीं से संचालित होगी। वन स्टॉप सेंटर में घरेलू एवं अन्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को परामर्श, पुलिस, कानूनी, चिकित्सा और आश्रय सहायता दी जा रही है। केंद्र में 24 दिसंबर 2018 से 27 अगस्त 2026 तक 700 मामले दर्ज हुए हैं। उपायुक्त ने दोनों केंद्रों में संवेदनशील एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हमीरपुर में तीन केंद्रों पर होगी नीट-पीजी परीक्षा

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। देशभर के मेडिकल कॉलेजों में एमडी, एमएस सहित अन्य स्नातकोत्तर डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा के लिए जिला हमीरपुर में तीन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एडीसी अभिषेक गर्ग ने बुधवार शाम प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों और परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर आवश्यक प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) द्वारा टीसीएस के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिले में आईओएन डिजिटल जोन आईडीजेड हमीरपुर (झनियारी), न्यू गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोपालनगर, पक्का भरो और सेवन स्टार इंटरनेशनल स्कूल बणी, बड़सर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। एडीसी ने केंद्र प्रभारियों को एनबीईएमएस के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जबकि अभ्यर्थियों का प्रवेश सुबह 7 बजे से शुरू होगा। एडीसी ने परीक्षा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

नेपाल यात्रा पर गए लोगों से संपर्क नहीं हो रहा है तो तुरंत करें सूचित : अभिषेक गर्ग

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। एडीसी अभिषेक गर्ग ने जिला के सभी एसडीएम, तहसीलदारों, खंड विकास अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर उनके क्षेत्रों से कोई स्थानीय निवासी नेपाल यात्रा पर गया है और उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित करें। उन्होंने बताया कि बुधवार को नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद गृह विभाग ने यह जानकारी मांगी है, ताकि नेपाल यात्रा पर गए लोगों की लोकेशन का पता किया जा सके और उनसे संपर्क किया जा सके। एडीसी ने जिलावासियों से भी अपील की है कि अगर उनका कोई परिजन या रिश्तेदार नेपाल यात्रा पर गया हुआ है और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो तुरंत संबंधित एसडीएम, तहसीलदार या खंड विकास अधिकारी को सूचित करें।

साइंटिफिक असिस्टेंट का फाइनल परिणाम घोषित

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने साइंटिफिक असिस्टेंट (डिजिटल फॉरेंसिक) के एक पद को भरने के लिए पोस्ट कोड-25021 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इस पद के लिए कुल 67 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 32 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी थी और इस परीक्षा में 4 उम्मीदवारों का चयन दस्तावेजों की जांच के लिए किया गया था। 7 अगस्त को दस्तावेजों की जांच के बाद इस पद के लिए अंशुल शर्मा का चयन किया गया है।

झंडूता में मारपीट के बाद 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत, आरोपी गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, झंडूता। पुलिस थाना तलाई के तहत संगांसवीं निवासी 42 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह की मारपीट के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की मां की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान धर्मेंद्र सिंह निवासी संगांसवीं-2, डाकघर बलोह, तहसील झंडूता के रूप में हुई है। शिकायत के अनुसार धर्मेंद्र सुबह काम के सिलसिले में घर से निकला था। आरोप है कि मलांगण निवासी बंटी उर्फ अनूप कुमार (44) ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद धर्मेंद्र बलोह स्कूल के समीप अचेत अवस्था में मिला। परिजन और स्थानीय लोग उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस थाना तलाई में आरोपी के खिलाफ एफआईआर संख्या 117/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी अनूप कुमार उर्फ बंटी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी घुमारवीं और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

उखली में मनाया 77वां वन महोत्सव

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। वन विभाग ने गांव उखली में 77वां वन महोत्सव मनाया, जिसमें मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर पौधरोपण किया।

इस अवसर पर विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों, पंचायत जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में उपस्थित अन्य स्थानीय लोगों को बधाई देते हुए सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की वन संपदा हमारी अमूल्य धरोहर ही नहीं, बल्कि यह प्रदेश की जलवायु का संरक्षण भी करती है और प्राकृतिक सुंदरता को निखारती है इसलिए, वनों का संरक्षण और अधिक से अधिक पौधरोपण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सुनील शर्मा बिट्टू ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के वनों के संरक्षण के साथ-साथ पौधरोपण के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने की दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं। इसके लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना आरंभ की गई है। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों, महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधरोपण एवं इन पौधों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इससे प्रदेश का हरित आवरण बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पौने चार वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान कई सराहनीय योजनाएं आरंभ की हैं और जिला हमीरपुर के लिए मेडिकल कालेज, बस स्टैंड, हैलीपोर्ट, डेडिकेटड साइंस कालेज और कई अन्य बड़ी परियोजनाएं मंजूर की हैं। इससे जिला में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं।

इस अवसर पर वन अरण्यपाल निशांत मंढोत्रा ने मुख्य अतिथि, अन्य अतिथियों और स्थानीय लोगों का स्वागत किया तथा विभाग के पौधरोपण कार्यक्रमों की जानकारी दी। स्थानीय पंचायत प्रधान सुमन कुमारी, उपप्रधान दौलत राम, पंचायत सदस्य लेखराम और अन्य पंचायत जनप्रतिनिधियों ने भी सुनील शर्मा बिट्टू का स्वागत किया। कार्यक्रम में हमीरपुर एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुमार, वन उप अरण्यपाल अंकित कुमार सिंह, विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के पदाधिकारी, वन विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे।

युवाओं को रोजगार चाहिए लॉटरी का टिकट नहीं : जम्वाल

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। भाजपा विधायक व मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने प्रदेश सरकार द्वारा लॉटरी शुरू करने के निर्णय पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल के लाखों युवाओं को रोजगार देने की गारंटी तो पूरी नहीं की, लेकिन अब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए लॉटरी का टिकट देने की तैयारी कर रही है।

राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। सरकार के चार वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन युवाओं को न तो वादा किया गया रोजगार मिला और न ही स्थायी रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा किए गए। उन्होंने कहा कि जिस सरकार से युवा रोजगार की उम्मीद कर रहे थे, वह अब राजस्व जुटाने के लिए लॉटरी का सहारा लेने जा रही है। हिमाचल के युवाओं को रोजगार चाहिए, लॉटरी का टिकट नहीं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले भी लॉटरी चलती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय लिया था। इसके बाद प्रदेश में बनी विभिन्न सरकारों ने भी इसे दोबारा शुरू नहीं किया। अब वर्तमान कांग्रेस सरकार का इसे पुनः शुरू करने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्वाल ने कहा कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि वह किस दिशा में हिमाचल को ले जा रही है। एक तरफ प्रदेश में नशे की समस्या लगातार गंभीर हो रही है और आए दिन युवाओं के नशे की चपेट में आने की खबरें सामने आती हैं, वहीं सरकार कभी भांग की खेती को रोजगार का माध्यम बनाने की बात करती है और अब लॉटरी शुरू करने जा रही है।

द्रोणाचार्य कॉलेज में 'उमंग' फ्रेशर पार्टी में विद्यार्थियों ने बिखेरा रंग

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। द्रोणाचार्य स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय रैत में बीबीए और बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए फ्रेशर पार्टी 'उमंग' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्रबंध निदेशक जीएस पठानिया और प्रधानाचार्य डॉ. परवीन शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। नवागंतुक स्टूडेंट्स ने गायन और नृत्य की शानदार प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान मिस्टर एवं मिस फ्रेशर का चयन भी किया गया। विद्यार्थियों ने भारतीय और पश्चिमी परिधानों में मॉडलिंग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बीबीए में सूर्यांश को मिस्टर फ्रेशर और मन्नत को मिस फ्रेशर चुना गया, जबकि बीकॉम में सारांश को मिस्टर फ्रेशर तथा शिवानी को मिस फ्रेशर का खिताब मिला। बीबीए के अक्षित को मिस्टर पर्सनैलिटी, अंशिता को मिस पर्सनैलिटी, जयन को मिस्टर बेस्ट वॉक और पायल को मिस बेस्ट वॉक चुना गया। कार्यक्रम के अंत में मिस्टर एवं मिस फ्रेशर ने केक काटा और सभी ने प्रीति भोज का आनंद लिया। प्रधानाचार्य डॉ. परवीन शर्मा ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर डीन ऑफ कॉलेज सहायक प्रो. अनीता चंदेल, विभागाध्यक्ष वितिका महाजन, रजत सहित अध्यापक वर्ग और निर्णायक मंडल के सदस्य उपस्थित रहे।

घुमारवीं कॉलेज में 29 को मनाया जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस

भारतेन्दु संवाददाता, घुमारवीं। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित खेल उत्सव में श्रीमती सोनिका धर्माणी मुख्यातिथि के रूप में शिरकत कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता से होगी। इसके बाद सुबह 10:30 बजे हॉकी और 11 बजे शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विभिन्न खेल गतिविधियों के बाद दोपहर 2 बजे समापन समारोह होगा, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. प्रीतम लाल ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस विद्यार्थियों में अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ जीवनशैली की भावना विकसित करने का अवसर है। मेजर ध्यानचंद का जीवन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है और उनकी उपलब्धियां युवाओं को कड़ी मेहनत व दृढ़ संकल्प के लिए प्रेरित करती हैं।

जनगणना ड्यूटी में तैनात पदोन्नत जेबीटी को लेकर स्पष्ट आदेश मांगे

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने जिला मंडी में जेबीटी से मुख्य शिक्षक पद पर पदोन्नत अध्यापकों को जनगणना ड्यूटी के कारण कार्यभार ग्रहण करने में आ रही समस्या पर चिंता जताई है।

महासंघ ने शिक्षा विभाग से इस संबंध में तत्काल स्पष्ट व लिखित दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। जिला मंडी में 119 जेबीटी अध्यापकों को मुख्य शिक्षक के पद पर पदोन्नति मिली है। इनमें कई अध्यापक वर्तमान में जनगणना कार्य में तैनात हैं। पदोन्नति आदेश जारी होने के बाद यह स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वे नई पाठशाला में तत्काल कार्यभार ग्रहण करें या जनगणना ड्यूटी पूरी होने तक वर्तमान पाठशाला में ही सेवाएं दें। महासंघ ने कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, वहीं पदोन्नति कर्मचारी का सेवा संबंधी अधिकार है। इसलिए विभाग को दोनों दायित्वों के बीच समुचित तालमेल स्थापित करना

◆ **मंडी के 119 जेबीटी बने मुख्य शिक्षक, कार्यभार ग्रहण को लेकर असमंजस**

चाहिए। महासंघ ने दो विकल्प सुझाए हैं। पहला, पदोन्नत अध्यापक नई पाठशाला में कार्यभार ग्रहण करें और जनगणना ड्यूटी पूरी होने तक, यानी 31 मार्च 2027 तक, पूर्व पाठशाला में सेवाएं देने की अनुमति मिले। दूसरा, जनगणना ड्यूटी में तैनात अध्यापकों को 31 मार्च 2027 तक वर्तमान पाठशाला में ही कार्यरत रखा जाए और इसके बाद नई पाठशाला में कार्यभार ग्रहण करने के स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं।

महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारी राष्ट्रीय दायित्वों से पीछे नहीं हटते, लेकिन पदोन्नति को लेकर अनिश्चितता भी उचित नहीं है। उन्होंने प्रदेशभर में ऐसे मामलों के लिए एक समान नीति बनाने की मांग की, ताकि कर्मचारियों को प्रशासनिक परेशानी न हो।

बिलासपुर में मारपीट के दो मामले दर्ज, पुलिस जांच में जुटी

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर के कोट कहलूर और भराड़ी थाना क्षेत्रों में मारपीट के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। पुलिस ने शिकायतों के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोट कहलूर थाना: पुरोइयां निवासी सतीश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने राजन, दीपक, राहिल और सुरजीत के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। भराड़ी थाना: घुमारवीं तहसील के पपलाह गांव निवासी शिवानी की शिकायत पर उसके पति शशि कुमार के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बिलासपुर ने दोनों मामलों की पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार दोनों मामलों में शिकायतों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

आयोजन संस्कृत सप्ताह पर एमसीएम डीएवी कॉलेज कांगड़ा में चर्चा-परिचर्चा आयोजित

भारतीय दर्शन पर विद्यार्थियों ने किया विचार-विमर्श

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। एमसीएम डीएवी कॉलेज कांगड़ा के संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत सप्ताह के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक एवं सारगर्भित चर्चा-परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा तथा भारतीय ज्ञान-परंपरा के विभिन्न आयामों से परिचित करवाना और वर्तमान संदर्भ में संस्कृत के महत्व को समझाना रहा।

कार्यक्रम में संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य डॉ. अरुणदीप शर्मा ने विद्यार्थियों के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान वेद एवं उपनिषद, सांख्य एवं योग दर्शन, श्रीमद्भगवद्गीता, रामायण, महाभारत, पुराण और आयुर्वेद सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। विद्यार्थियों ने चर्चा में सक्रिय भागीदारी करते हुए विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न और विचार प्रस्तुत किए। गीता के कर्मयोग एवं जीवन-दर्शन तथा रामायण और महाभारत में निहित नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर विशेष चर्चा हुई। साथ ही आयुर्वेद और प्राचीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान की वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर भी विचार साझा किए गए। कार्यक्रम में संस्कृत विभाग के सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. बलजीत सिंह पटियाल ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि संस्कृत भारतीय संस्कृति, दर्शन, साहित्य और ज्ञान-विज्ञान की समृद्ध परंपरा की महत्वपूर्ण संवाहक है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को अपनी गौरवशाली ज्ञान-परंपरा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एमसीएम डीएवी कॉलेज का बीए प्रथम वर्ष का परिणाम रहा 91 प्रतिशत

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला द्वारा घोषित बीए प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम में एमसीएम डीएवी कॉलेज कांगड़ा के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर कॉलेज का नाम रोशन किया है। कॉलेज का कुल परीक्षा परिणाम 91 प्रतिशत रहा। कॉलेज में राशि ने 84.63 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं श्रुति पुरी ने 82 प्रतिशत अंक लेकर दूसरा तथा राशि देवी ने 81.88 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। तीनों छात्राओं ने कॉलेज की शीर्ष तीन पोजीशन पर कब्जा कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम से कॉलेज परिवार में खुशी का माहौल है। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. बलजीत सिंह पटियाल ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए विशेष रूप से राशि, श्रुति पुरी और राशि देवी की उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन छात्राओं की सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत है। प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, लगन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। कॉलेज में उपलब्ध सकारात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें निरंतर मेहनत और लगन के साथ सफलता के नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।

2 अक्तूबर तक सभी पात्र संस्थानों में सक्रिय होंगी जूनियर और यूथ रेड क्रॉस इकाइयां

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। डीसी व भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, जिला शाखा बिलासपुर के अध्यक्ष राहुल कुमार की अध्यक्षता में बचत भवन में जूनियर रेड क्रॉस व यूथ रेड क्रॉस की संयुक्त समीक्षा व समन्वय बैठक हुई।

बैठक में युवा इकाइयों को सक्रिय बनाने और अधिक युवाओं को समाज सेवा से जोड़ने पर चर्चा की गई। डीसी ने सभी पात्र शैक्षणिक, स्वास्थ्य व तकनीकी संस्थानों में 2 अक्तूबर तक जूनियर व यूथ रेड क्रॉस इकाइयों के गठन तथा सुदृढ़ीकरण का लक्ष्य पूरा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को रेड क्रॉस की गतिविधियों से जोड़कर उनमें सेवा, संवेदना, सामाजिक जिम्मेदारी व नेतृत्व की भावना विकसित की जा सकती है। उन्होंने रेड क्रॉस के सात मौलिक सिद्धांतों मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता व सार्वभौमिकता की जानकारी देने और उन्हें जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। युवाओं को मानव सेवा, नशा-मुक्त बिलासपुर अभियान, वृद्धजनों की सहायता, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य जागरूकता और सामुदायिक सेवा से जोड़ने की बात कही। बैठक में सुरेश कुमार नड्डा व सुमन चड्ढा को उपाध्यक्ष तथा सुशील पुंडीर, प्रोमिला वसु, पवन संख्यान च प्रकाश धीमान को सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके अलावा रेड क्रॉस व एराइज, चंडीगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगजनों के लिए परामर्श, कौशल विकास व आजीविका सुदृढ़ीकरण आधारित पायलट परियोजना शुरू करने की जानकारी दी गई। परियोजना में 20 से 30 प्रतिभागियों को डिजिटल व सहायक तकनीक, संचार कौशल और सरकारी योजनाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में करीब 70 प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पेज स्पिरानैक खूबसूरत गोल्फ खिलाड़ी

पेज स्पिरानैक अमेरिका की प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी, सोशल मीडिया व्यक्तित्व और खेल प्रशिक्षक हैं। उनका जन्म 26 मार्च 1993 को व्हीट रिज, कोलोराडो, अमेरिका में हुआ था। उन्होंने कम उम्र से ही गोल्फ खेलना शुरू किया और कॉलेज स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन किया।

न्यूज ब्रीफ

कच्चे तेल की नरमी से रुपया मजबूत

एजेंसी, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का सकारात्मक असर भारतीय रुपये पर दिखाई दिया। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में रुपया चार पैसे मजबूत होकर 95.40 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। कारोबार की शुरुआत 95.50 रुपये प्रति डॉलर पर हुई थी और कुछ समय बाद मुद्रा ने शुरुआती नुकसान की भरपाई कर बढ़त हासिल की। ब्रेंट कच्चे तेल का भाव 0.41 प्रतिशत गिरकर 87.48 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जिससे रुपये को सहारा मिला। डॉलर सूचकांक में भी मामूली कमजोरी दर्ज की गई। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी बुधवार को 502.63 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की थी। विशेषज्ञों के अनुसार, तेल कीमतों और वैश्विक बाजार की दिशा रुपये के आगे के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

एप्पल का नौ सितंबर को बड़ा आयोजन,आईफोन अठारह प्रो समेत नए उपकरणों पर नजर

एजेंसी, नई दिल्ली। एप्पल का वार्षिक सितंबर आयोजन इस बार नौ सितंबर को आयोजित होने जा रहा है। क्यूपर्टिनो स्थित एप्पल पार्क के स्टीव जॉब्स थिएटर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर तकनीकी जगत में काफी उत्सुकता है। आयोजन में आईफोन अठारह प्रो और आईफोन अठारह प्रो मैक्स पेश किए जाने की चर्चा है। संभावित बदलावों में नई चिप, बेहतर कैमरा और डिजाइन में सुधार शामिल हैं। सबसे बड़ा आकर्षण एप्पल का पहला मुड़ने वाला आईफोन हो सकता है, जिसे लेकर कई तरह की रिपोर्ट सामने आई हैं। इसके अलावा नई एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी पेश किए जाने की उम्मीद है। यह आयोजन कंपनी के नए नेतृत्व में पहला बड़ा वैश्विक उत्पाद लॉन्च भी होगा।

कनाडाई कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मिलीं सीतारमण

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कनाडा यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को टोरंटो में एक बिजनेस सम्मेलन में भाग लिया और वहां की विभिन्न कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से द्विपक्षीय मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि वित्त मंत्री ने कनाडा की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ), अध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित एक उच्च स्तरीय बिजनेस राउंडटेबल में भाग लिया। इस राउंडटेबल का आयोजन कनाड-इंडिया बिजनेस काउंसिल और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसमें हरित प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज, दुर्लभ मृदा तत्व, ऊर्जा भंडारण, टिकाऊ बुनियादी ढांचा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोटिव, कपड़ा, ग्रीन स्टील, एयरोस्पेस, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, एआई, परिसंपत्ति प्रबंधन, उच्च शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों के प्रमुख कारोबारी नेता शामिल हुए।

कैरोलिना मुचोवा और जाकुब मेंसिक ने जीता यूएस ओपन मिश्रित युगल खिताब

एजेंसी, न्यूयॉर्क। चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा और जाकुब मेंसिक ने बेलिंडा बेनचिच और फ्लावियो कोबोली को 6-3, 1-6, 10-6 से हराकर यूएस ओपन 2026 मिश्रित युगल खिताब जीत लिया। पहले सेट में चेक जोड़ी ने शानदार शुरुआत की, लेकिन दूसरे सेट में बेनचिच-कोबोली ने वापसी कर मुकाबला बराबर कर दिया। निर्णायक टाईब्रेक में मेंसिक की दमदार सर्विस और नेट पर शानदार खेल ने जीत सुनिश्चित की। यह मुचोवा और मेंसिक का साथ में पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है।

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए की तीनों प्रारूपों की टीमें घोषित

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की महिला चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम के भारत दौरे के लिए भारत ए की टी-20, एकदिवसीय और बहुदिवसीय टीमों की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए टीम तीन टी-20, तीन एकदिवसीय और एक बहुदिवसीय मुकाबला खेलेगी। टी-20 सीरीज के सभी मुकाबले न्यू चंडीगढ़ में खेले जाएंगे, जबकि एकदिवसीय मैच मोहाली के पीसीए स्टेडियम में होंगे। दौरे का समापन धर्मशाला में बहुदिवसीय मुकाबले के साथ होगा। टी-20 टीम की कप्तानी अनुष्का शर्मा को सौंपी गई है और सयाली सतघरे उपकप्तान होंगी। एकदिवसीय तथा बहुदिवसीय टीमों की कमान यास्तिका भाटिया संभालेंगी।

दिनुषा की शतकीय पारी से ड्रॉ हुआ कोलंबो टेस्ट, भारत 1-0 से विजेता

भारत ने अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी

एजेंसी, नई दिल्ली

भारत और श्रीलंका के बीच खेली गई दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार को रोमांचक अंदाज में ड्रॉ पर समाप्त हुआ। श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुषा ने शानदार नाबाद शतक लगाकर अपनी टीम को हार से बचा लिया। पांचवें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में नौ विकेट पर 429 रन बनाकर पारी घोषित नहीं की और मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दिनुषा 133 रन बनाकर नाबाद रहे। इस नतीजे के साथ भारत ने दो मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने गाले में खेले गए पहले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराया था।

कोलंबो टेस्ट में भारत ने अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम पहली पारी में 290 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 213 रन की बड़ी बढ़त मिली और श्रीलंका को फॉलोऑन खेलना पड़ा। फॉलोऑन के बाद श्रीलंका के सामने मैच बचाने की बड़ी चुनौती थी। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक मेजबान टीम छह विकेट पर 229 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी। ऐसे में भारतीय टीम को पांचवें दिन जीत की उम्मीद थी।

पांचवें दिन सोनल दिनुषा ने केशरा नुवानथा के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों का मजबूती से सामना किया। दोनों बल्लेबाजों ने सातवें विकेट के लिए 112 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इस साझेदारी ने श्रीलंका को संकट से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। नुवानथा ने 46 रन की उपयोगी पारी खेली, जबकि दिनुषा ने धैर्य और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाते हुए नाबाद 133 रन बनाए। दिनुषा की पारी के कारण श्रीलंका लगातार विकेट गंवाने के बावजूद मुकाबले में बना रहा और अंततः भारत को जीत से रोकने में सफल रहा।

दिनुषा के लिए यह पूरी सीरीज बेहद यादगार रही। उन्होंने कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में भी 103 रन की शानदार पारी खेली थी। इससे पहले गाले में खेले गए पहले टेस्ट में भी उन्होंने शतक लगाया था। इस तरह उन्होंने सीरीज में लगातार शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी निरंतरता और मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी करने की क्षमता ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट में बड़ी हार से बचाया।

कोलकाता में उरुग्वे से होगी भारतीय फुटबॉल टीम की टक्कर

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के लिए आने वाला अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम बेहद चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होने वाला है। टीम 6 अक्टूबर को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में दो बार की फीफा विश्व कप चैंपियन उरुग्वे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मैत्री मुकाबला खेलेगी। यह मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय टीम के खिलाफ अपनी क्षमता परखने का महत्वपूर्ण अवसर देगा। उरुग्वे दुनिया की मजबूत फुटबॉल टीमों में शामिल है और उसके खिलाफ खेलना भारतीय टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुभव हासिल करने का बड़ा मौका होगा।

उरुग्वे के खिलाफ मुकाबला भारतीय टीम के लिए इस अंतरराष्ट्रीय विंडो में तीसरा बड़ा मैत्री मैच होगा। इससे पहले भारत 26 सितंबर को बेंगलुरु में पनामा के खिलाफ मैदान में उतरेगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को कोलकाता में भारतीय टीम पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राजील का सामना करेगी। इस तरह कुछ ही दिनों के अंतराल में भारतीय खिलाड़ियों को पनामा, ब्राजील और उरुग्वे जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की टीमों के खिलाफ खेलने का अवसर मिलेगा।

उरुग्वे की टीम अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित टीमों में गिनी जाती है। उसने दो बार फीफा विश्व कप का खिताब जीता है और उसके पास कई अनुभवी तथा प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहे हैं। मौजूदा फीफा विश्व रैंकिंग में उरुग्वे 20वें स्थान पर है। ऐसे में भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला आसान नहीं माना जा रहा है। भारतीय खिलाड़ियों को उरुग्वे की तेज गति, तकनीकी क्षमता और मजबूत रक्षात्मक शैली का सामना करना होगा। इस मुकाबले को लेकर एक खास बात यह भी है कि उरुग्वे के मौजूदा मुख्य कोच डिएगो फोरलान का भारत से पुराना जुड़ाव रहा है। फोरलान वर्ष 2016 में मुंबई सिटी एफसी के लिए खेल चुके हैं।

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स फाइनल में पहुंची

अनमोल शर्मा और तेजस्वी दहिया के अर्धशतकों के बाद दिव्यांश रावत की घातक गेंदबाजी रही कारगर

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के पहले क्वालिफायर मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 15 रन से हराकर फाइनल में सीधे प्रवेश कर लिया। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय मैच में वापसी की उम्मीद जगा दी थी लेकिन साउथ दिल्ली के गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में शानदार नियंत्रण दिखाते हुए जीत अपने नाम कर ली। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट खोकर 193 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। टीम की पारी में अनमोल शर्मा और कप्तान तेजस्वी दहिया ने अहम भूमिका निभाई। अनमोल ने 67 रन की शानदार पारी खेली जबकि तेजस्वी ने 57 रन बनाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत आधार दिया और मध्य तथा अंतिम ओवरों में तेजी से रन जुटाए।

साउथ दिल्ली ने 193 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज की

194 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। शुरुआती विकेट गिरने के बाद टीम दबाव में नजर आई लेकिन केशव डबास और वंश बेदी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले में रोमांच पैदा कर दिया। केशव ने 59 रन जबकि वंश ने 52 रन की तेजतर्रार पारी खेली। दोनों ने साउथ दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बनाया और लक्ष्य के करीब पहुंचने की कोशिश की। हालांकि साउथ दिल्ली के गेंदबाजों ने महत्वपूर्ण समय पर वापसी की। दिव्यांश रावत ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट हासिल किए और सेंट्रल दिल्ली की रन गति पर अंकुश लगाया। अंतिम ओवरों में लगातार विकेट गिरने के कारण सेंट्रल दिल्ली किंग्स की पूरी टीम 19.4 ओवर में 178 रन पर सिमट गई। इस तरह साउथ दिल्ली ने 15 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने डीपीएल 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। टीम के लिए बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों का प्रदर्शन निर्णायक रहा। वहीं सेंट्रल दिल्ली किंग्स के पास अभी फाइनल में पहुंचने का एक और मौका है। उसे अब क्वालिफायर दो में जीत हासिल करनी होगी।

2036 ओलंपिक की तैयारी पर युवाओं से चर्चा करेंगे पीएम मोदी

एजेंसी, नई दिल्ली

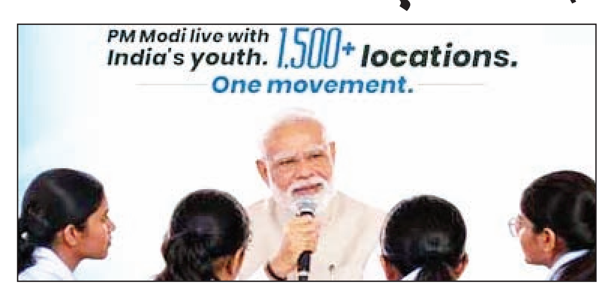

राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के युवा खिलाड़ियों और युवाओं से विशेष संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री 'खेलो इंडिया संवाद' कार्यक्रम के तहत गुरुवार को 'खेल की बात, प्रधानमंत्री मोदी के साथ' कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह संवाद देश के 1500 से अधिक शिक्षण संस्थानों में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ने के साथ देश में खेल संस्कृति को मजबूत करना और उभरती प्रतिभाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद विभिन्न संस्थानों में युवाओं और खेल जगत से जुड़े लोगों के साथ संवाद कार्यक्रम होंगे। इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम में जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं के विस्तार, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के अवसर उपलब्ध कराने तथा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

कार्यक्रम में देश के कई दिग्गज खिलाड़ी भी युवाओं से बातचीत करेंगे। दीपा करमाकर, साइना नेहवाल, गगन नारंग, पीआर श्रीजेश, मैरी कॉम, बाइचुंग भूटिया, पुलेला गोपीचंद, अंजू बॉबी जॉर्ज, कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू और पीटी उषा जैसे खिलाड़ी अपने अनुभव युवाओं के साथ साझा करेंगे। वे अपने संघर्ष, चुनौतियों और सफलता के सफर के बारे में बताएंगे तथा प्रतिभागियों के सवालों का जवाब भी देंगे। इस संवाद में भारत के दीर्घकालिक खेल लक्ष्यों पर भी विशेष ध्यान रहेगा। वर्ष 2036 के ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण व्यवस्था और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

जन-धन योजना के 12 साल पूरे

59.09 करोड़ खाते खुले और 3.17 लाख करोड़ रुपए जमा

एजेंसी, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के 12 वर्ष पूरे होने पर देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में हुई प्रगति का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 19 अगस्त 2026 तक योजना के तहत 59.09 करोड़ जन-धन खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल 3.17 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। योजना के तहत 41.29 करोड़ निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड भी जारी किए गए हैं। खास बात यह है कि 78 प्रतिशत से अधिक खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बैंकिंग सुविधाओं से दूर रहने वाली आबादी को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक बैंकिंग सुविधा से वंचित वयस्क को बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं वाला खाता उपलब्ध कराना है। इन खातों में न्यूनतम शेष राशि रखने की अनिवार्यता नहीं है और रखरखाव शुल्क भी नहीं लिया जाता। खाताधारकों को निःशुल्क रुपे कार्ड के साथ दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा मिलती है। पात्र खाताधारक 10 हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं।

जन-धन योजना की एक बड़ी उपलब्धि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 56 प्रतिशत खाताधारक महिलाएं हैं। इससे महिलाओं को बचत, डिजिटल लेनदेन और सरकारी वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में मदद मिली है। योजना के खातों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक सरकारी सहायता और अन्य वित्तीय लाभ सीधे पहुंचाने की व्यवस्था को भी मजबूती मिली है।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि योजना को केवल खातों की संख्या या जमा राशि के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके जरिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की पहुंच आसान हुई है। जन-धन योजना ने बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। आने वाले समय में इन खातों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना वित्तीय समावेशन को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

लॉर्ड्स में वापसी को तैयार बाबर आजम

एजेंसी, नई दिल्ली। लॉर्ड्स टेस्ट से पहले पाकिस्तान के लिए बाबर आजम की फिटनेस को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। हाथ की चोट के कारण पहला टेस्ट नहीं खेल सके बाबर ने बताया कि वह दूसरे मुकाबले के लिए करीब 90 प्रतिशत फिट हैं। उन्होंने पिछले एक सप्ताह में अभ्यास और फिटनेस पर काफी मेहनत की है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जाना है। पहले टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान की टीम श्रृंखला बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। बाबर की वापसी होती है तो पाकिस्तान की अंतिम एकादश में बदलाव होना तय माना जा रहा है। खराब फॉर्म से जूझ रहे युवा सलामी बल्लेबाज अजान अवैस को बाहर बैठना पड़ सकता है।

सहवाग-द्रविड़ के बेटों को मिला भारतीय अंडर-19 टीम में मौका

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के भारत दौरे के लिए भारतीय पुरुष अंडर-19 टीम की घोषणा कर दी है। आगामी दौरे में तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला और दो बहुदिवसीय मुकाबले खेले जाएंगे। टीम में पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को भी शामिल किया गया है। दोनों खिलाड़ियों के चयन ने क्रिकेट प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले आर्यवीर और विकेटकीपर-बल्लेबाज अन्वय को पहली बार भारत की अंडर-19 एकदिवसीय टीम में जगह मिली है। अब दोनों युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी।

सहवाग के बेटे आर्यवीर और द्रविड़ के बेटे अन्वय चुने गए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफअंडर-19 सीरीज में दिखाएंगे दम

राजकोट में 18 सितंबर से एकदिवसीय श्रृंखला शुरू होगी। टीम की कप्तानी लक्ष्य रायचंदानी को सौंपी गई है, जबकि यशबर्धन चौहान उपकप्तान होंगे। घरेलू क्रिकेट और विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर चुने गए इन खिलाड़ियों के सामने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित करने का अवसर होगा।

लगेज खोने पर यात्रियों को एयरलाइन से मिलेगा मुआवजा

एजेंसी, नई दिल्ली

चेक-इन लगेज नहीं मिला या खराब पहुंचा तो यात्री को मिलेगा मुआवजा

हवाई यात्रा के दौरान चेक-इन किया हुआ सामान गुम या क्षतिग्रस्त होने पर यात्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। विमानन नियमों के तहत ऐसी स्थिति में यात्री संबंधित एयरलाइन से मुआवजे का दावा कर सकते हैं। सामान गुम होने या क्षतिग्रस्त मिलने पर एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले एयरलाइन के बैगेज काउंटर पर शिकायत दर्ज कराना जरूरी है। इसके लिए प्रॉपर्टी इरेगुलैरिटी रिपोर्ट दर्ज कराकर उसकी प्रति और संदर्भ संख्या सुरक्षित रखनी चाहिए। आगे मुआवजा लेने की प्रक्रिया में यह दस्तावेज महत्वपूर्ण होता है।

नियमों के अनुसार यदि चेक-इन सामान मिलने में 24 घंटे से अधिक की देरी होती है तो जरूरी वस्तुओं के लिए यात्री को मुआवजा दिया जा सकता है। वहीं 21 दिनों तक सामान नहीं मिलने पर उसे पूरी तरह गुम माना जाता है। घरेलू उड़ानों में सामान खोने की स्थिति में निर्धारित नियमों के अनुसार प्रति किलोग्राम अधिकतम 20 हजार रुपये तक मुआवजे का प्रावधान बताया गया है।

यात्री को घटना के सात दिनों के भीतर एयरलाइन को लिखित शिकायत भी देनी चाहिए। शिकायत के साथ बोर्डिंग पास, सामान की पर्ची और नुकसान की तस्वीरें जैसे जरूरी दस्तावेज लगाए जा सकते हैं। यदि एयरलाइन उचित मुआवजा देने से इनकार करती है तो यात्री उपभोक्ता आयोग का रुख कर सकता है।

पीएम किसान की 24वीं किस्त के लिए करना होगा इंतजार

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे देशभर के करोड़ों किसानों को रक्षाबंधन के मौके पर निराशा हाथ लगी है। किसानों के खातों में इस दिन दो-दो हजार रुपये की अगली किस्त नहीं आएगी। सरकार की ओर से अभी तक 24वीं किस्त जारी करने की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में रक्षाबंधन पर किस्त मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। प्रत्येक किस्त में दो हजार रुपये मिलते हैं। योजना की पिछली यानी 23वीं किस्त 20 जून को जारी की गई थी। इसके बाद से किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 24वीं किस्त अक्टूबर या नवंबर में जारी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जब तक केंद्र सरकार की ओर से तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तब तक किसी निश्चित तारीख को लेकर दावा करना उचित नहीं होगा। किसानों को सलाह है कि वे अपने बैंक खाते, आधार और भूमि संबंधी विवरण की स्थिति जांचते रहें।

रक्षाबंधन से पहले सोना-चांदी सस्ता

1.58 लाख रुपए के करीब पहुंची सोने की कीमत; 24 और 22 कैरेट के दाम भी गिरे

एजेंसी, नई दिल्ली

रक्षाबंधन के त्योहार से पहले सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट ने आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहकों को राहत दी है। घरेलू सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव में नरमी देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमत घटकर करीब 1,57,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। इसके साथ ही दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में भी 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दाम में कमी दर्ज की गई है।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार में आए बदलाव प्रमुख कारण हैं। अमेरिकी व्यक्तिगत उपभोग व्यय सूचकांक के आंकड़ों और वैश्विक स्तर पर हाजिर सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर पड़ा है। चांदी के भाव में भी बड़ी गिरावट दर्ज होने से त्योहारी मांग के बीच ग्राहकों को खरीदारी का बेहतर अवसर मिला है।

रक्षाबंधन के मौके पर देशभर में सोने-चांदी के आभूषण और अन्य कीमती वस्तुओं की मांग बढ़ती है। ऐसे में कीमतों में आई कमी से ग्राहकों की खरीदारी क्षमता बढ़ सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि कीमती धातुओं के भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार में ताजा भाव की जानकारी लेना जरूरी है।

सेंसेक्स 539 अंक गिरकर 76,934 पर बंद, निफ्टी 117 अंक नीचे आया

27 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 539 अंक टूटकर 76,934 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 117 अंक गिरकर 24,091 पर आ गया। कारोबार के दौरान मेटल, सरकारी बैंक और मीडिया क्षेत्र के शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली रही। इससे पहले 26 अगस्त को भी बाजार में गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों का बाजार में भरोसा कायम है और उन्होंने बीते सात दिनों में 11,273 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। वहीं ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम 27 अगस्त से खुल गया है, जिसके जरिये कंपनी 700 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।